हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

25 फरवरी, 2020

खण्ड–1, अंक–4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 25 फरवरी, 2020

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

मार्कण्डा नैशनल महाविद्यालय, शाहबाद मार्कण्डा, जिला कुरूक्षेत्र के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनराराम्भ)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

विभिन्न मामलें उठाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराराम्भ)

गैर सरकारी दिवस को सरकारी दिवस में परिवर्तित करना

बैठक का समय बढ़ाना

गैर सरकारी दिवस को सरकारी दिवस में परिवर्तित करना (पुनराराम्भ)

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 25 फरवरी, 2020

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र□न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

Construction of Bye-Pass

***262. Smt. Naina Singh Chautala**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Bye-Pass in Badhra Town; if so, the time by which the said Bye-Pass is likely to be constructed?

mi&eq[;ea=h ¼Jh nq";Ur pkSVkyk½ % नहीं, जी।

श्रीमती नैना सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह जो बाढड़ा के बाई–पास का एरिया है यह दिल्ली–बाढड़ा–पिलानी जाने वाले मुख्य मार्ग पर पड़ता है। बाढड़ा बाई–पास न बनने की वजह से यहां बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। अध्यक्ष महोदय, बाढड़ा मार्किट में दिन–प्रतिदिन लोगों का आना जाना लगा रहता है जिससे आये दिन यहां पर जाम की समस्या बन जाती है। अगर यह बाई–पास बन जाता है तो लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल जायेगी। यही नहीं यदि यह बाई–पास बन जाता है तो आगे चलकर यह बाई–पास 50 गांवों को जोड़ने का काम भी करेगा। अतः बाढड़ा बाई–पास को जल्द से जल्द बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं साथ ही एक ओर सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आदमपुर डाडी गांव से होते हुए नारनौल के लिए जो हाइवे जा रहा है उसकी हालत बहुत खस्ता है क्योंकि इस हाइवे पर ओवरलोडिंग डंपर दिन–रात चलते हैं। खस्ता हालत होने की वजह से इस रोड पर ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और गाडियां भी बहुत मुश्किल से ही निकल पाती है। अतः इस दिशा में भी ध्यान देने की जरूरत है। (विघ्न)

डॉ अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय मैं भी माननीय सदस्या के इस प्रश्न का समर्थन करता हूँ।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा है उसके संदर्भ में मैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा जोकि बाढड़ा को क्रास करते हुए जा रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट हरियाणा–यू.पी. बार्डर से सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी तथा लोहारू तक जाने वाला प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट बाढड़ा के अंदर से गुजरेगा और इस प्रोजेक्ट में एक सड़क फोर लेन की

भी होगी और जो दूसरा प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट हिसार, तोशाम, सतनाली, बाढड़ा जुईं, महेंद्रगढ़ तथा रिवाड़ी तक है। इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में एन.एच.ए.आई. ने हमसे प्रपोजल मांगा था और हमने इसकी डी.पी.आर. बनाकर उनको भेज दी है। यही नहीं हमने नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस प्रोजेक्ट को टेक–अप करने संबंधी एक पत्र भी लिख दिया है। अगर वह इस प्रोजेक्ट को टेक अप कर लेते हैं तो इसकी जो वाइडनिंग का काम होगा उससे शहर के अंदर फोर लेनिंग की सुविधा भी हो जायेगी और अगर इनके प्रपोजल में बाई पास का प्रोवीजन भी होगा तो आने वाले समय में शहर के बाहर से बाई पास भी बन जायेगा अगर मान लो एन.एच.ए.आई. इस प्रोजेक्ट को टेक अप नहीं करता है तो भी हम अपने पी.डब्लयू.डी.(बी.एंड आर.) महकमे के साथ मिलकर इसको टेक अप करते हुए पूरा करने का काम करेंगे।

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, आदमपुर ढाडी से नारनौल वाला जो नैशनल हाइवे न. 148–बी है, इसकी भी फोर लेनिंग का काम पैंडिंग है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस बारे में भी जरूर गौर फरमायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष जी, अभय सिंह जी ने भी तो संबंधित प्रश्न से अलग एक प्रश्न पूछा है और बावजूद इसके आपने उनको प्रश्न पूछने की इजाजत दी है लेकिन कल आपने ऐसा नहीं होने दिया था? ऐसा नहीं होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, माननीय सदस्य अभय सिंह यादव जी ने बाढड़ा के संबंध में ही प्रश्न पूछा है और यही कारण है कि मैंने उनको प्रश्न पूछने की परमिशन भी दी है।

श्री दुश्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जिस सड़क की वे बात कह रहे हैं उस सड़क का काम पहले ही किया जा चुका है लेकिन चूंकि इस एरिया में माइनिंग का काम बड़े जोर–शोर से होता है और इसकी वजह से यहां पर हैवी ट्रैफिक चलता रहता है जिसका परिणाम यह निकलकर सामने आता है कि यह सड़क निरंतर टूटती रहती है। इस सड़क पर रिपेयरिंग के कार्य की बहुत जरूरत है और बहुत जल्दी इस सड़क पर रिपेयर कार्य शुरू करवा दिया जायेगा।

.....

Death of Cows in Gaushalas

***193. Shri Shishpal Singh :** Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state the total number of cows died during the year 2019-20 in Gaushalas of District Sirsa togetherwith the steps taken by the Government in the matter?

कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रका□ा दलाल) : श्रीमान जी, राज्य में आमतौर पर गौषालाएं पंजीकृत समितियों/ न्यासों द्वारा संचालित की जाती हैं। सिरसा जिले में 122 पंजीकृत तथा 20 अपंजीकृत गौषालाएं हैं। सिरसा जिले की गौषालाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2019–20 में (15 जनवरी 2020 तक) कुल 4368 गायों की मृत्यु हुई है। राजकीय पषु चिकित्सा संस्थाएं गौषालाओं में गौवंष को पषु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं। इसके अतिरिक्त, हरियाणा गौसेवा आयोग द्वारा भी समय–समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

श्री भी□ापाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2018 के बीच में सिरसा जिले में लगभग 10772 गाय मरी हैं अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार ने गायों को बचाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ? मुझे इसके बारे में स्पष्ट तौर से बताया जाये।

श्री जय प्रका□ा दलाल : अध्यक्ष महोदय, सिरसा की गौशालाओं में लगभग 50 हजार के करीब गौवंश हैं और पिछले एक साल के अंदर 4368 गऊओं की मौत हुई हैं। आमतौर पर घरों में पालने वाली गऊओं की उम्र 14 साल के करीब होती है। लेकिन हमारी गौशालाओं में सड़कों व बाजारों से पॉलीथीन वगैरह खाकर बेसहारा गायें आती हैं। इस प्रकार से उनकी नैचुरल मृत्यु की उम्र कम हो सकती है। अत्यधिक सर्दी और गर्मी की वजह से भी नैचुरल गायों की मौतें हुई हैं। फिर भी हमने विभाग को और पशु चिकित्सक को प्लास्टिक वगैरह खाए हुए गायों का इलाज करने के लिए तरह–तरह के निर्देश दिए हुए हैं। सरकारी पशु चिकित्सक समय–समय पर गौशालाओं में जाकर बीमार गायों की देखभाल करते रहते हैं।

श्री भी□ापाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। सिरसा जिले में लगभग 10772 गायों की डैथ हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बाद इस दिशा में सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? दूसरी

बात यह है कि लगभग 4 हजार से लेकर 5 हजार तक गायें गौशालाओं से बाहर सड़कों पर बेसहारा घुमती रहती हैं, उनकी मृत्यु का कोई भी आंकड़ा सरकार के पास मौजूद नहीं है। गौशालाओं में जो गायों की मृत्यु का आंकड़ा है वह वाकई में चिंतनीय है। जिस गौशाला में 400–500 गौवंश हैं वहां पर गायों की मृत्यु 10 प्रतिशत वार्षिक के करीब आती है जोकि बहुत ज्यादा है। मेरा सवाल यह है कि गायों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से क्या–क्या कदम उठाये जा रहे हैं? कितनी दवाइयां वगैरह गौशालाओं में भेजी गई हैं? गौशालाओं में गायों के बीमारी के क्या–क्या कारण निकले हैं? अत्याधिक सर्दी और अत्याधिक गर्मी की वजह से जो गायों की मौतें हुई हैं उनका क्या समाधान निकला है? मैं माननीय मंत्री जी सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ।

श्री जय प्रका□ा दलाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में गौसेवा आयोग बनाया हुआ है। गौसेवा आयोग गौशालाओं का निरीक्षण करने के बाद जहां व्यवस्था की कोई कमी होती है उसके लिए सहायता करती है। गायों के आहार की व्यवस्था के लिए ग्रांट देती है और दवाइयों के लिए भी इंतजाम करती है। जरूरत के मुताबिक पशु चिकित्सक भी मुहैया करवाने की कोशिश करती है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने गौशालाओं में कितनी दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं और वहां पर पशु आहार की क्या–क्या व्यवस्था की गई है, इस बात का जवाब माननीय मंत्री जी सदन में दें ?

श्री भी□ापाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पशु आहार भी दिया जा रहा है और दवाइयां भी दी जा रही हैं। लेकिन अब तक कितना पशु आहार व दवाइयां दी गई हैं, कृपया करके माननीय मंत्री इस बात का जवाब सदन में बताने की कृपा करें।

श्री जय प्रका□ा दलाल : अध्यक्ष महोदय, गौसेवा आयोग तीन हजार गौवंश पर पशु चिकित्सा अस्पताल की व्यवस्था करता है। गौसेवा आयोग ने पिछले 3–4 साल में लगभग 70 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गौशालाओं के बारे में सरकार को बहुत फिक्र है, यह अच्छी बात है। लेकिन आज सड़कों और बाजारों में इतनी बेसहारा गायें घूमती रहती हैं। इन बेसहारा गायों के बारे में सरकार की तरफ से कहा गया था कि हर गांव–गांव प्रबंध करेंगे और उनके लिए पैसे की व्यवस्था करेंगे। अध्यक्ष

महोदय, सरकार को बने 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। सरकार ने गौशालाओं के लिए क्या–क्या प्रबंध किए हैं, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें।

श्री जय प्रका□ा दलाल : अध्यक्ष महोदय, हम जल्दी ही ऐसा फैसला करने वाले हैं कि हरियाणा में जितनी भी गौशालाएं हैं अगर वे सड़कों और बाजारों में बेसहारा गायों के बारे में सहयोग करेगी और बेसहारा गायों को अपने गौशालाओं में इक्ट्ठा करेगी तो सरकार एक पॉलिसी बनाकर उन गौशालाओं को अलग से ग्रांट देगी। इस प्रकार से आने वाले समय में जो बेसहारा गायें सड़कों पर घुमती नजर आती हैं वे धीरे–धीरे गौशालाओं में नजर आने लगेगी।

श्री दीपक मंगला : अध्यक्ष महोदय, आवारा गायों की जगह बेसहारा गायें वर्ड यूज किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आवारा गाय की जगह बेसहारा गाय कहा जाये।

.....

To Shift the Electric Poles

***32. Shri Abhe Singh Yadav :** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the electric poles erected in the middle of village Phirnis and Aam-Rastas in the Mahendergarh district; if so, the details thereof togetherwith the time by which these are likely to be shifted ?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान जी, गांव की फिरनियों के ऊपर से गुजरने वाली एच.टी/एल.टी. लाइनों को स्थानांतरित करने की नीति दिनांक 16.03.2016 पहले से ही है।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपनी रिटन रिप्लाई में लिखा है कि –

> "the policy dated 16.03.2016 to shift the HT/LT lines passing over the villages Phirnis already exits."

इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह बात अकेले गांव की फिरनियों की नहीं है । जो 4 करम, 5 करम और 6 करम के एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाले रास्ते हैं उनके बीचों–बीच बोर्ड ने खम्भे गाड़ रखे हैं । मैं मंत्री जी को 2–3

रोड ऐसे दिखा सकता हूं जहां पर मैटल्ड रोड़ है और उनके बीच में खम्भे खड़े हैं। फिरनियों के बीच में तो आम ही खम्भे खड़े हुए हैं । मेरा निवेदन है और मुझे समझ में नहीं आता कि आम रास्तों के बीचों–बीच बोर्ड खम्भे क्यों गाड़ता है ? मुझे तो यह भी शक है कि यह कानूनी टैनेबल भी है या नहीं ? मेरा निवेदन है कि आम रास्तों के बीच में खड़े हुए खम्भों को बिजली बोर्ड अपने खर्चे पर हटाए । रोड़ को पक्का करने वालों को अगर हम इस बारे में कहते हैं तो वे कहते हैं कि उनके ऐस्टीमेटस में खम्भे को हटाने का प्रोविजन नहीं है । आप इसका ऐस्टीमेटस बनवाकर बिजली बोर्ड में जमा करवा दें । इसे केवल बिजली बोर्ड ही हटवा सकता है । अतः इस समस्या को गम्भीरता से लेने की जरूरत है। मेरा पुनः निवेदन है कि आम रास्तों के बीच से खम्भों को तुरन्त हटा दिया जाए ।

.....

मार्कण्डा नैशनल महाविद्यालय, शाहबाद, मारकण्डा, जिला कुरूक्षेत्र के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का अभिनन्दन

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, आज मार्कण्डा नैशनल कॉलेज, शाहबाद, मार्कण्डा, जिला कुरूक्षेत्र के अध्यापकगण एवं विद्यार्थी दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं, मैं सदन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ ।

.....

तारांकित प्र□न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, कॉलोनियों, आवासीय मकानों, तालाबों, विद्यालयों, फिरनियों आदि के ऊपर से गुजर रही एच.टी./एल.टी. लाईन्स को हटाने के निर्देश हमने पहले ही दिए हुए हैं । बिजली विभाग के खम्भे गाड़ने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता चला गया और नये–नये रास्ते, सड़कें आदि बनती चली गई लेकिन उस समय डिवाइडर नहीं बनाए गए जिस वजह से ये खम्भे सड़कों के बीच में आ गए । अब हम उनको हटा रहे हैं । मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई खम्भा किसी व्यक्ति के घर में लगा है तो उसको हटाने के लिए उस व्यक्ति के हैड पर पैसा लगता है ।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या मकानों के ऊपर से गुजरने वाली हाई वॉल्टेज पावर की तारों को बदलने का प्रावधान है ? मेरा निवेदन है कि अगर विभाग में ऐसा प्रावधान है तो उन तारों को जल्दी से जल्दी बदल दिया जाए । पिछले दिनों मेरे हल्के बाढ़ड़ा के

बलियाली गांव में एक किसान की खेतों में इन तारों की वजह से डैथ हो गई थी । प्रदेश में ऐसे बहुत–से किसान हैं जो बिजली के ट्यूबवैल्ज के द्वारा अपने खेतों में पानी देते हैं । प्रदेश में बहुत–सी जगहों पर आज भी इन तारों को नहीं बदला गया है जिसकी वजह से आये दिन प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं । माननीय बिजली मंत्री मेरे लिए पिता तुल्य हैं । मेरा उनसे निवेदन है कि बिजली की इन तारों को जल्दी से जल्दी हटाया/बदला जाए ।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग ने मकानों के ऊपर से कभी तारें नहीं डाली थी । तारें डालने के बाद लोगों ने अपने प्लॉट्स में मकान बना लिए । ऐसे में जिस प्लॉट के ऊपर से तार डाली गई थी और बाद में उस पर मकान बना दिया गया तो वह मकान तारों के नीचे आ गया । इसके अतिरिक्त बाद में झाड़ली और खेदड़ में थर्मल पावर प्लांट लगाए गए तो इनसे उत्पन्न हुई बिजली को बाहर भेजने के लिए तारें डाली गई । ऐसे में कई घरों के ऊपर से तारें गुजर गई । अब बड़ी लाइन के तारों को हटाना तो बहुत मुश्किल है लेकिन हम छोटी लाइन के तारों को हटा रहे हैं ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, कई गांवों की जोहड़ों के ऊपर से बिजली की तारें गुजर रही हैं । ऐसे में वहां पर पशुओं की कैजुअल्टी हो जाती है । मेरे हल्के के लाठ गांव में फिरनी के बीच में एक खम्भा खड़ा है । मेरा निवेदन है कि इन तारों को सरकारी खर्च पर हटाया जाए, इसके लिए किसान या पंचायत से कोई पैसा न लिया जाए । इनको सरकारी खर्च पर हटाने के लिए पोलिसी बनाई जानी चाहिए ।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि कॉलोनियों, आवासीय मकानों, तालाबों, विद्यालयों, फिरनियों आदि के ऊपर से गुजर रही एच.टी./एल.टी. लाईन्स को हटाने के निर्देश हमने पहले ही दिए हुए हैं।

.....

Sanctioned Posts In PHCs And CHCs

***55. Shri Shamsher Singh Gogi :** Will the Health Minister be pleased to state the total number of sanctioned posts of the staff in Community Health Centres and Primary Health Centres falling under the Assandh Assembly Constituency togetherwith the number of staff working at present?

Home Minister (Shri Anil Vij) : Sir, the respective numbers are 231 and 97 .

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और टोटल ग्रामीण क्षेत्र है। वहां पर एक सी.एच.सी. और 8 पी.एच. सीज. हैं लेकिन इनमें सिर्फ 3 डॉक्टर्ज हैं। अगर आप इस बात का सर्वे करवाकर कम्पेरिजन करवा लें तो आपको पता चलेगा कि क्या करनाल शहर और अंबाला शहर में ही ज्यादा डॉक्टर्ज की जरूरत है, क्या गांवों के गरीब लोगों को डॉक्टर्ज की जरूरत नहीं है ? मेरे असन्ध हल्के की सी.एच.सी. में 5:00 बजे के बाद कोई ओ.पी.डी. नहीं की जाती है। अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो रात को ओ.पी. डी. नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त पैरा मेडिकल स्टॉफ भी पूरा नहीं है। यह स्टॉफ कब तक पूरा होगा ? यह स्टॉफ पूरा क्यों नहीं हो रहा है ? मेरे क्षेत्र के साथ भेदभाव क्यों है? क्या हम टैक्स नहीं देते हैं ? हम सरकार को मार्केट कमेटी से टैक्स के रुपये सबसे ज्यादा पैसे कमाकर देते हैं। वे भी किसान ही हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे इस बारे में अंबाला शहर से कम्पैरिजन करके बताएं ? माननीय श्री अनिल विज जी अच्छे मंत्री हैं।

श्री अनिल विजः स्पीकर सर, मैं माननीय विधायक जी की चिन्ता से सहमत हूं कि हमारे विभाग के पास स्टॉफ और डॉक्टर्ज की शार्टेज है। ऐसा नहीं है कि यह समस्या केवल हरियाणा प्रदेश में ही है बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी डॉक्टर्ज और स्टॉफ की शार्टेज है। डब्ल्यू.एच.ओ. के मापदण्ड के मुताबिक 1,000 की पोपूलेशन पर एक डॉक्टर होना चाहिए, परन्तु हमारे देश में 1800 की पोपूलेशन पर एक डॉक्टर है। डॉक्टर्ज की शार्टेज है, इसीलिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी मेडिकल कॉलेजिज खोलने के ऊपर जोर दे रहे हैं ताकि और ज्यादा डॉक्टर्ज तैयार हों और हमें संबंधित डॉक्टर्ज की सेवाएं मिल सकें। फिर भी हम इस शार्टेज को देखते हुए अपने यहां पर कमी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए विभाग द्वारा 447 मेडिकल ऑफिसर्ज की भर्ती का प्रोसैस स्टार्ट किया जा चुका है और इसके लिए 1 मार्च, 2020 को इन आवेदकों का रिटन टैस्ट रोहतक यूनिवर्सिटी में होगा। रिटन टैस्ट और उनकी वैटेज के नम्बर्ज के आधार पर मेरिट बनाकर डॉक्टर्ज की भर्ती कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह मानकर चलें कि मार्च के फर्स्ट हॉफ में 447 डॉक्टर्ज लगा दिये जाएंगे। माननीय विधायक जी के हल्के में भी

डॉक्टर्ज लगाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ–साथ एक नयी पॉलिसी तैयार की है क्योंकि रेगुलर डॉक्टर्ज की भर्ती करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसमें लगभग 1 या 2 साल का प्रोसैस लग जाता है और एच.पी.एस.सी. के परव्यू से बाहर निकलना पड़ता है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इजाजत दे दी है और संबंधित योजना मंजूर हो चुकी है कि जैसे ही काई सीट खाली होगी तो वहां पर एडहॉक बेसिज पर डॉक्टर्ज की भर्ती कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त हम 342 एडहॉक डॉक्टर्ज की भी भर्ती करने जा रहे हैं। इसमें संबंधित डॉक्टर्ज को सैलेरी के स्थान पर पैकेज देंगे। इसमें जो डॉक्टर एम.बी.बी.एस होगा, उसको 85,000 रुपये महीना देंगे। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। उसको डेढ़ लाख रुपये की सैलेरी देंगे। हम समझते हैं कि इस प्रक्रिया के तहत डॉक्टर्ज की सारी कमी पूरी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हमने फैसला कर लिया है कि इस साल से हरियाणा प्रदेश के किसी भी सरकारी कॉलेज में अगर कोई एडमिशन लेगा तो उसके लिए यह मेनडेटरी होगा कि एम.बी.बी.एस. का कोर्स पूरा करने के बाद 2 साल के लिए वह हरियाणा प्रदेश के सरकारी होस्पिटल्ज में काम करेगा और इसके लिए संबंधित फार्म पर हस्ताक्षर करना होगा। सर, ऐसा करने से हमें लगभग 1600 डॉक्टर्ज और मिल जाएंगे। मैं समझता हूं कि इससे हमारे प्रदेश में डॉक्टर्ज की कमी पूरी हो जाएगी। पैरा मेडिकल स्टॉफ की भी कमी है। माननीय सदस्य ने बताया कि इनके विधान सभा क्षेत्र की पी.एच.सी. में पैरा मेडिकल स्टॉफ की कमी है। अगर नेचूरली देखा जाए तो कई जगहों पर 9 कर्मचारियों की जगह पर 1 ही कर्मचारी है। इसमें बहुत दिक्कत है। इसके लिए एच.एस.एस.सी. को रिकमेंडेशन भेजी हुई है। जिसमें स्टॉफ नर्स की 1584 पोस्ट्स के लिए भेजी हुई है। फार्मासिस्ट की 92 पोस्ट्स के लिए भेजी हुई है। ओफथलमिक असिस्टैंट की 66 पोस्ट्स के लिए भेजी हुई है। रेडियोग्राफर की 197 पोस्ट्स के लिए भेजी हुई है। लैब टैक्नीशियन की 307 पोस्ट्स के लिए भेजी हुई है। लैब असिस्टैंट की 28 पोस्ट्स के लिए भेजी हुई है। ऑपरेशन थियेटर असिस्टैंट की 100 पोस्ट्स के लिए भेजी हुई है। एम.पी.एच.डब्ल्यू फिमेल की 432 पोस्ट्स के लिए भेजी हुई है। डैंटल हाईजैनिस्ट के लिए 29 पोस्ट्स के लिए भेजी हुई है। डाइटिशियन की 23 पोस्ट्स के लिए भेजी हुई है। टी.बी. हैल्थ विजिटर की 8 पोस्ट्स के लिए भेजी हुई है। सोसल वर्कर की 33 पोस्ट्स के लिए भेजी हुई है। फिजियोथैरेपिस्ट्स की 92 पोस्ट्स के लिए भेजी हुई है और क्लॉस फोर की 1782 पोस्ट्स भरने के लिए भेजी

हुई है। इन पोस्ट्स को भरने में समय लग सकता है। इसके साथ ही मैंने आदेश जारी किए हैं कि सैंग्शन पोस्टों के अगेंस्ट जहां–जहां पर भी हमारे पास वैंकसीज हैं वहां पर कांट्रैक्चुअल बेसिज के आधार पर भर्तियां करने की जो पार्ट–2 की पॉलिसी बनी हुई है उसके तहत कांट्रेक्चुअल बेस पर भर्तियां कर ली जायें। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि हम इसकी जल्दी ही प्रक्रिया आरम्भ करने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस तरह के कदम उठाने के बाद हमारे स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की और अन्य स्टाफ की जो कमियां हैं वह आने वाले समय में पूरी कर ली जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि हमें प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है, हमें भी इस बात की चिंता हर वक्त रहती है।

श्री भाम□ोर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की बात ठीक है कि पिछले 6 सालों से डॉक्टरों की भर्ती करने की कोशिश की जा रही है परन्तु अब तक डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है। मेरे असंध अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, पूरे एरिया में जितनी पी.एच.सीज. हैं, वहां पर ओपन में डिलीवरी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम असंध अस्पताल में एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर की ड्यूटी रात के समय में तो लगा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, वहां पर डी.सी. रेट पर जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं वे लोग ही पैंशेंट्स की पट्टियां करने का काम करते हैं। मैंने वहां पर खुद मौके पर भी जाकर देखा है। मैं किसी व्यक्ति की शिकायत भी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा न हो कि मेरे शिकायत करने पर जो डेली वेजिज पर कर्मचारी लगे हैं वे कहीं भाग जायें। मैं इसके अलावा यह भी बताना चाहूंगा कि काफी लम्बे समय से इस अस्पताल की लैब भी बंद है और पैशेंट्स बाहर धक्के खाकर अपने टैस्ट करवाने पर मजबूर हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में डॉक्टरों की कमियां तो बहुत हैं परन्तु मुझे मंत्री जी की तरफ से आश्वासन चाहिए कि असंध अस्पताल में कम से कम एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर को अप्वॉयंट कर दिया जाएगा तभी मैं सहमत हो पाऊंगा नहीं तो मैं अगली बार भी यही प्रश्न माननीय मंत्री जी के सामने रखूंगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हर विधायक का अपने हल्के के बारे में चिंता करना वाजिब बात है। इस बात को सरकार भी मानती है कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमियां हैं लेकिन मौजूदा कमियों के बावजूद भी हमने हैल्थ विभाग में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो आई.एम.आर. है, जब हमारी

सरकार सत्ता में आई थी तब उस वक्त यह 41 से भी अधिक था और आज वह 41 से घटकर 28 हो गया है। इस प्रकार हमारी सरकार ने आज बहुत ज्यादा अचीवमैंट हासिल की है। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से हमारा एम.एम.आर. भी जो पहले 127 प्रतिशत था वह भी आज घटकर 98 प्रतिशत रह गया है। हमारे प्रदेश का जो सैक्स रेशो है, उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे प्रदेश की जो ओ.पी.डी. है, you will be surprised to know that despite all the in pediments, despite all the difficulties हमारी ओ.पी.डी. लगभग 30 प्रतिशत बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा इन्फ्रांस्ट्रक्चर और स्टाफ के होते हुए हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों का रूझान और विश्वास सरकारी अस्पतालों की तरफ ज्यादा बढ़ा है।

श्री भाम□ोर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि.....(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, आपने तीन सम्पलीमैंटरी पूछ ली है। यह कोई बहस का विषय नहीं है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर को लगाने की बात है, मैं उस बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर को जल्दी से जल्दी असंध अस्पताल में लगाने की कोशिश करेंगे।

श्री भाम□ोर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, हमें आज गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर की जरूरत है। मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि मान लो किसी व्यक्ति को एक महीने के बाद खाना खाने को दिया जाये तो क्या वह व्यक्ति जिंदा रह पायेगा? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर असंध अस्पताल में लगाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। (विघ्न)

श्री भाम□ोर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की बात का विरोध नहीं कर रहा हूं परन्तु माननीय मंत्री जी की बात ठीक है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि यह बहस का विषय नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बातना चाहूंगा कि यह क्वैश्चन ऑवर है इसलिए प्लीज, आप बैठ जायें।

Construction Work of Four Lane Road

***59. Rao Dan Singh** : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the construction work of four laning of N.H-148(B) from Narnaul to Bhiwani has been stopped for the last many days; and

(b) If so, the time by which the abovesaid construction work is likely to be started/completed?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) :(a) & b) Sir, four laning of section of NH-148B from Bhiwani to Mandola (Charkhi Dadri) has been completed on 25.09.2019. The section from Mandola (Charkhi Dadri) to Narnaul of NH-148B falls under jurisdiction of NHAI and no four laning work has been taken up by NHAI in this stretch. Therefore, no time frame can be given.

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में नॉर्थ–साउथ कॉरीडोर के नाम से गांव पनियाला और गांव कोटपुतली राजस्थान से लिंक करके भिवानी होता हुआ महेन्द्रगढ़ और नारनौल के बीच से गुजरता हुआ फोर लेन का प्रपोजल रखा था। उस समय सरकार ने एक–एक इंच भूमि अधिग्रहण की थी और कम्पनी ने अर्नेस्ट मनी हरियाणा गवर्नमैंट के पास 25 करोड़ रुपये जमा करवाई थी लेकिन उसके बाद कम्पनी को लगा कि यह कांट्रैक्ट उसके लिए फिजिबल नहीं है तो वह कम्पनी कांट्रैक्ट बीच में ही छोड़कर चली गई थी। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद दादरी, भिवानी और बाढ़ड़ा हल्का जहां की श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी विधायक है वहां के पालड़ी और आदमपुर डाडी इन दो गांवों को छोड़कर बाकी जगह फोर लेन का सारे का सारा कंस्ट्रक्शन वर्क कम्पलीट हो चुका है। मेरे हल्के से आगे जहां से नारनौल शुरू होता है वहां से राजस्थान को जो जोड़ने वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर भी यह रोड फोर लेन बनने लग रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़ ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उसकी निरंतर उपेक्षा की जा रही है? पहले से ही

जिला तो महेन्द्रगढ़ बनाया हुआ है लेकिन हैड क्वॉर्टर ऍट नारनौल है। जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ उस समय भी हरियाणा के सात जिलों में से महेन्द्रगढ़ एक जिला था and Rewari was also a part of that. आज फिर से हमारे क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। अब मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमती नैना चौटाला जी के विधान सभा क्षेत्र भी दो गांव लगते हैं और मेरा क्षेत्र भी लगता है। आज उप मुख्यमंत्री जी के पास यह महकमा है जैसे कि कहा भी जाता है कि घर की बही और काका लिखने वाला, इसलिए आज काके के पास बही है मतलब बेटा काम करने वाला है और मॉ का क्षेत्र है तो यह काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। अब इस काम के होने में क्या परेशानी हो सकती है? मैं यह बात भी बताना चाहूंगा कि इसके लिए लैण्ड भी एक्वॉयर नहीं करनी है। इसी प्रकार से पेड़ काटने की परमिशन ऑलरेडी मिली हुई है और पोल शिफ्ट करने की एवज़ में उस समय यह कह दिया गया था कि आपको 61 करोड़ रूपये देने हैं। इस प्रकार से पोल्स को शिफ्ट करने कर प्रॉविजन भी कर दिया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज ऐसी क्या दिक्कत है कि एन.एच. 148 (बी) को डिवैल्प नहीं किया जा रहा है? हमारे महेन्द्रगढ़ में आर.ओ.बी. का एक पार्ट कंस्ट्रक्ट हो चुका है और दूसरे का कंस्ट्रक्शन वर्क भी अलॉट होने वाला था। वहां पर इतना हैवी ट्रैफिक है जिसकी वजह से वहां पर सैंकड़ों मौतें हो चुकी है। अगर सरकार को मेरी बात पर यकीन न हो तो सरकार इससे सम्बंधित पिछले पांच साल का डाटा निकलवाकर देख ले, स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जायेगी। अभी–अभी पिछले 15 दिन के अंदर दो मौतें मेरी क्षेत्र के अंदर हुई हैं। उस समय यह हुआ था कि एक अनियंत्रित ट्रक पूरे गांव के घुस गया था। वहां पर बाई–पास की लैण्ड एक्वॉयर हो चुकी हैं। अगर सरकार इस फोर लेनिंग सड़क का काम पूरा करवा दे तो मैं समझता हूं कि मेरे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया होगा।

डॉ. अभय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं भी माननीय सदस्य की इस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य पहली बार इस हाउस में निर्वाचित होकर नहीं आये हैं। वे पुरानी सरकारों के शासनकाल की भी बात कर रहे थे। इनको इस पूरे प्रोजैक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि इस सड़क की फोर लेनिंग का कार्य एक पार्ट में नहीं बना। इनकी पार्टी की सरकार द्वारा इस प्रोजैक्ट

के कार्य को पांच हिस्सों में बांटा गया था। इनको हाउस को मिसलीड नहीं करना चाहिए कि यह एक प्रोजैक्ट था। राय मलिकपुर से लेकर भिवानी बाई–पास होते हुए आगे खरक तक इनकी सरकार द्वारा इस सड़क के निर्माण कार्य को पांच हिस्सों में बांटा गया था। इसको एन.एच.ए.आई. ने टेक–अप किया। अब एन.एच.ए.आई. ने इस प्रोजैक्ट के दो फेजिज को कम्पलीट कर लिया है और एक फेज को दिसम्बर, 2020 तक कम्पलीट कर लिया जायेगा। जो बीच के दो फेज महेन्द्रगढ़ जिले में हैं जिनके बारे में अभी माननीय सदस्य बात कर रहे थे वो एक नया प्रोजैक्ट जो ग्रीन फील्ड हाईवे बनना है उसके हिस्से के अंदर अब एन.एच.ए.आई. डिवैल्प करने का काम करेगी। उसी कारण वर्क अलॉटमैंट होने से पहले इन दो फेजिज को जो इस पूरे प्रोजैक्ट के अंदर आने थे ग्रीन फील्ड हाईवे वाले प्रोजैक्ट के अंदर टेक–अप कर लिये गये हैं। इस मामले में सरकार द्वारा एन.एच.ए.आई. को निरंतर पत्र व्यवहार किया जा रहा है कि अगर ग्रीन फील्ड प्रोजैक्ट के अंदर किसी प्रकार की देरी हो रही हो तो इस प्रोजैक्ट को कम्पलीट करवाया जाये क्योंकि यह केन्द्र सरकार से सम्बंधित सवाल है। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में यह बात दोबारा से ला देता हूं कि ये उनके दो फेज हैं इनके अंदर पहला फेज महेन्द्रगढ़ से मंदौला तक है और दूसरा फेज नारनौल से महेन्द्रगढ़ तक है। इन दो फेजिज के कार्य को अगर एन.एच.ए.आई. निकट भविष्य में टेक–अप नहीं करती तो प्रदेश सरकार जरूर डिवैल्प करेगी।

राव दान सिंह : स्पीकर सर, जो उप मुख्यमंत्री जी ने दो फेजिज की बात की है। इस सम्बन्ध में मुझे यह जानकारी मिली है कि सरकार की पहले यह मंशा थी कि यह सडक़ फिलहाल साढ़े 7 मीटर चौड़ी है इसकी चौड़ाई को 10 मीटर करके रखा जायेगा क्योंकि इसकी बगल में एक दूसरा 152–डी हाईवे निकल रहा है जो सिक्स लेनिंग रोड बन रहा है जो पनियाला मोड से जोड़ करके सीधा अम्बाला तक आयेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी वजह से इस सड़क के कार्य को रोका न जाये क्योंकि सरकार की पहले भी यह पॉलिसी है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वॉर्टर टू डिस्ट्रिक्ट हैडक्वॉर्टर हम फोर लेन से जोड़ेंगे। इस रोड पर एक सिरे में दादरी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वॉर्टर है और दूसरी तरफ नारनौल डिस्ट्रिक्ट हैडक्वॉर्टर है we are in between. मैं समझता हूं कि अगर इस सड़क के निर्माण कार्य को सरकार द्वारा अपनी प्रॉयरिटी पर लिया जायेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर एन.एच.ए.आई. से भी सरकार के स्तर पर सम्पर्क स्थापित किया जायेगा तो इस सड़क के

कार्य को निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जा सकता है। अध्यक्ष जी, यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है। धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य को तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि यह हाईवे फोर लेन के बजाये सिक्स लेन हो रहा है। इससे तो इनके इलाके की प्रगति की रफ्तार ही बढ़ेगी। जो इन्होंने बात रखी मैंने अभी उसी को ही बोला था कि पहले यह फोर लेन प्रोजैक्ट था लेकिन अब इसको एन.एच. 152– डी के अंदर लेकर सिक्स लेनिंग करने की प्रपोजल है। हम इस सम्बन्ध में एन.एच.ए.आई. से चर्चा कर चुके हैं। अगर एन.एच.ए.आई. इस प्रोजैक्ट को टेक–अप नहीं करती तो इस सड़क के फोर लेनिंग के कार्य को हम जल्दी से जल्दी कम्पलीट करवाने का कार्य करेंगे।

राव दान सिंह : स्पीकर सर, मैं इस सम्बन्ध में यह जानकारी देना चाहूंगा कि एन. एच. 152–डी इस सड़क से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार से ऐसा जगता है कि हमारे एरिया को बाई–पास किया जा रहा है। अगर हमारा एरिया एन.एच. 152–डी की वजह से इसमें नहीं आ रहा है तो सरकार के पास इतना प्रॉविजन तो होता ही है कि सरकार अपने खर्च पर इस सड़क के निर्माण कार्य को कम्पलीट करे। सरकार की डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जोड़ने की योजना है। यह प्रोजैक्ट इस योजना में भी शामिल होता है। इस सड़क के लिए लैण्ड एक्वॉयर की हुई है और दूसरी सारी औपचारिकतायें भी पूर्ण की जा चुकी हैं। अब सिर्फ रोड का निर्माण कार्य ही बाकी है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, पहले यह नैशनल हाई वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अन्तर्गत आता था लेकिन जब से नैशनल हाईवे 152–डी बनाने की योजना आई तो उन्होंने इस काम को होल्ड पर रख दिया। उसके बाद हमने उनको पत्र लिखा कि अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको डिनोटिफाई कर दीजिए हम इसको स्वयं टेकअप कर लेंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार आज भी वह नैशनल हाईवे है और उन्होंने वह काम को रोका हुआ है। इस प्रकार से उनको दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा अगर वे इसको डिनोटिफाई करेंगे तो हम इसको फोरलेन बनवा देंगे और अगर वे डिनोटिफाई न करके इस काम को दोबारा से शुरू करेंगे तो इसको सिक्स लेन बनायेंगे। इन दोनों में से जब एक काम हो जायेगा तो इसके ऊपर निर्णय कर लिया जायेगा।

Desilting of Canals

***12. Smt. Kiran Choudhry :** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) whether it is a fact that desilting work of irrigation canals in State has not yet been started and proper water is not reaching in canals for the Rabi Crop; if so, the reasons thereof; and

(b) the time by which the abovesaid work is likely to be started togetherwith the action taken by the Government against the Officers responsible for delay?

कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रका□ा दलाल) :

(क) नहीं, जी ।

(ख) इसलिए प्रश्न का यह भाग उत्पन्न ही नहीं होता ।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर सही तरह से न आ कर एक ही जवाब नहीं में दिया जाता है। इस बारे में यह कहना चाहती हूं कि सरकार हर साल नहरों की सफाई के लिए टैंडर निकालती है लेकिन सच्चाई यह है कि पूरी तरह से सफाई नहीं होती है। नहरों में 8 से 10 फीट तक घास–फूस भरी रहती है तथा किसानों को पूरा पानी नहीं मिल पाता है जिसके कारण उनको डीजल पर ज्यादा पैसा खर्च करके ट्यूबवैल चलाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि विभाग की तरफ से क्या ठोस कदम उठाए गये हैं जिसके कारण हमें यह बात दोबारा से न उठानी पड़े?

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कुल 1385 चैनल्स हैं, रबी तथा खरीफ की फसलों के समय इनकी नियमित तौर पर सफाई होती रहती है। इस साल 1165 चैनल्स की सफाई की जरूरत थी जिसमें से 685 चैनल्स की सफाई हमने मनरेगा के तहत करवाई है तथा 478 चैनल्स की सफाई कांट्रैक्टर के माध्यम से करवाई है। इस प्रकार से 1165 चैनल्स में से 1163 चैनल्स की सफाई हो चुकी है तथा दो चैनल्स जुई फीडर तथा जुई नहर की सफाई खरीफ की फसल के दौरान कर ली जायेगी।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, दोबारा से वही जवाब दिया जा रहा है कि सफाई करवा ली जायेगी। जो इस काम में कोताही बरतते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जिन कर्मचारियों या अधिकारियों ने इस काम में ढिलाई बरती है उन कितने कर्मचारियों या अधिकारियों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की है?

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, सफाई नहीं होने का विषय ही नहीं आया जब मैं बता रहा हूं कि 1165 में से 1163 चैनल्स की सफाई हो चुकी है और दो चैनल्स पर काम चल रहा था। जो मेन चैनल्स होते हैं उनमें यह भी देखना पड़ता है कि पानी की सप्लाई भी बाधित न हो और सफाई भी हो जाये क्योंकि लोगों को पीने का पानी भी उन्हीं चैनल्स के माध्यम से सप्लाई होता है। हमें पानी सप्लाई की सुचारू व्यवस्था भी देखनी होती है। चैनल्स की सफाई का काम भी उसी व्यवस्था के अनुसार चलता रहता है। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसमें सफाई की जरूरत हो और उसकी सफाई न हुई हो।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती हूं कि सिंचाई विभाग आपके पास है, जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने अपने काम में ढिलाई बरती है उनके खिलाफ आप सख्त एक्शन लें ताकि समय पर नहरों की सफाई हो सके और किसानों को रबी तथा खरीफ की फसलों के दौरान नुकसान न हो। आप जिस तरह से दूसरे विभागों में छापे मरवा रहे हैं उसी तरह से सिंचाई विभाग में भी छापे मरवाइये तथा देखिए कि नहरों की सफाई हुई है या नहीं हुई है।

.....

To provide necessary facilities in Stadium

***230. Shri Rajender Singh Joon :** Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide necessary facilities related to Athletic Track and other sports in Dr. Bhim Rao Ambedkar Stadium situated in Badli road in Sector-11, Bahadurgarh; and

(b) if so, details thereof?

@ मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) प्रश्न का यह हिस्सा, इसलिए, उत्पन्न नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र सिंह जून : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से शायद मंत्री जी ने प्रश्न को सही तरह से नहीं पढ़ा है इसलिए मैं इसको रिपीट कर देता हूं। मैंने पूछा है whether there is any proposal under consideration of the Government to provide necessary facilities related to Athletic Track and other sports in Dr. Bhim Rao Ambedkar Stadium situated at Badli road in Sector-11, Bahadurgarh; and if so, the details thereof? अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी स्पोटर्स की सुविधाएं नहीं होंगी, ऐथलैटिक का ट्रैक नहीं होगा, इंडोर हॉल नहीं होगा, बास्केट बॉल का कोर्ट नहीं होगा, टेनिस कोर्ट नहीं होगा, कुश्ती के लिए मैट नहीं होगा या ग्राउंड में घास नहीं होगी या खिलाड़ियों के लिए पीने के लिए आर. ओ. का पानी नहीं होगा तो खिलाड़ी देश के लिए किस प्रकार से खेलेंगे ? जब आप खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करेंगे तभी तो खिलाड़ी देश के लिए अच्छा खेलेंगे।

सरदार संदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस स्टेडियम की ये बात कर रहे हैं वह कांग्रेस की सरकार में 11 मार्च 2013 में पास हुआ था और वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस स्टेडियम पर दोबारा काम शुरू करवाया है। इस स्टेडियम के लिए 15.48 एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी जिसमें से 3.26 एकड़ जमीन प्राईवेट निकली और उसके बाद इस जमीन पर स्टेडियम बनाने के लिए लगभग साढ़े पंद्रह करोड़ रुपये का बजट पास हुआ था लेकिन जमीन कम होने के कारण इसके लिए केवल 10 करोड़ 12 लाख रुपये मंजूर हुए। इस स्टेडियम में ऐथलैटिक्स ट्रैक, ग्रास जोकि ऐट लेन का है, ऐथलैटिक्स पैवेलियन, क्रिकेट पिच और बाउंड्रीवाल भी है। उसके साथ ही अढ़ाई किलोमीटर की रेंज में एक ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम बहादुरगढ़ में है जो 9 एकड़ जमीन में बना हुआ है। वहां पर मल्टी परपज हॉल भी है, योगा मैंटर भी है, ऐथलैटिक्स ट्रैक भी है और साथ ही में हॉकी का मैदान भी है। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इस स्टेडियम में फैसिलिटीज नहीं है तो यहां पर जूडो, टी.टी., ऐथलैटिक्स और वेट लिफ्टिंग के कई खिलाड़ी मैडिलिस्ट कैसे बने हैं। माननीय सदस्य ने आर.ओ. लगाने की बात की है तो डैफिनेटली

.....

@ Reply given by the Minister of the State for Sports and Youth Affairs. मैं आर. ओ. के ऊपर भी काम करूंगा। आपके वहां स्टेडियम में हम आर.ओ. भी लगवाएंगे। अगर फैसिलिटीज की बात करें तो यहां सदन में जो प्रश्न आते हैं वह स्टेडियम से रिलेटिड ही आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा में बहुत से स्टेडियम्ज बने हुए हैं। हमें उन स्टेडियम्ज को मेनटेन भी करना है । हमें स्टेडियम्ज ही नहीं हमें यहां पर ऐथलैटिक्स और जितने भी ऐथलीट हैं, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए मैदान भी चाहिए। जो पैसा हम स्टेडियम बनाने में लगाते हैं वह पैसा मैं खिलाड़ियों के ऊपर लगाना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह जून : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जिस दूसरे स्टेडियम की बात कर रहे हैं और जिसमें उन्होंने प्राईवेट लैंड का जिक्र किया है वह प्राईवेट लैंड नहीं है बल्कि उस जमीन पर झुग्गियां पड़ी हुई हैं और वह सरकारी लैंड है। उस पर अभी केस चल रहा है। अगर वह जमीन खाली हो जाए तो वह सरकार की जमीन है। मंत्री जी ने जो फैसिलिटीज गिनवाई हैं मैं मंत्री जी से विनती करता हूं कि वह फैसिलिटीज इस स्टेडियम में भी दें क्योंकि बहादुरगढ़ के अन्दर 2 लाख 60 हजार के करीब पॉपुलेशन है लेकिन इस स्टेडियम के अन्दर इस तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं हैं जो मैंने आपको बताई हैं। वहां पर न कुश्ती हॉल है और न मैट है इसलिए मैं मंत्री जी से उस स्टेडियम में भी इस तरह की फैसिलिटीज देने का अनुरोध करता हूं।

सरदार संदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस स्टेडियम में टेनिस के दो कोर्ट, वॉलीवॉल के दो कोर्ट, बास्केट बॉल के दो कोर्ट, हैंड बॉल का एक कोर्ट और कबड्डी के दो कोर्ट हैं। इसके अलावा मल्टी परपज हॉल भी बनना था। जिस लैंड की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं कि उस जमीन पर केस चल रहा है मैं बताना चाहता हूं कि उसी के कारण यह मल्टी परपज हॉल नहीं बन पाया ऑदरवाईज इसका वहां बनाने का प्रावधान था।

.....

To Provide Electricity Connections under PAT

***120. Shri Sita Ram :** Will the Power Minister be pleased to statewhether there is any proposal under consideration of the

Government to provide electricity connections under PAT in Dhanies of Ateli Assembly Constituency; if so, the details thereof?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान जी, राज्य में पी.ए.टी. के साथ ढाणियों को बिजली कनेक्शन देने के लिए नीति दिनांक 06.03.2017 पहले से ही है।

श्री सीता राम : अध्यक्ष महोदय, क्या बिजली मंत्री जी बताएंगे कि अटेली विधान सभा क्षेत्र में ए.पी. फीडरों के अन्तर्गत जो लोग ढाणियों में रहते हैं वहां पी.ए.टी. ट्रांसफार्मर लगाकर उनको गांव की तर्ज पर 18 से 20 घण्टे बिजली देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आबादी बढ़ने की वजह से लोग गांव से निकलकर ढाणियों में जाकर बसने लगे हैं। जैसे हमारे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, नारनौल और महेन्द्रगढ़ जिलों के ज्यादातर लोग ढाणियों में बसने लगे हैं। जब गांव में आबादी बढ़ती गई तो हमने पैट ट्रांसफार्मर देने शुरू कर दिये। गुजरात की एक कम्पनी इन पैट ट्रांसफार्मर्ज को बना रही है। अभी हमने 1500 पैट ट्रांसफार्मर के लिए ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किया है । माननीय सदस्य के हल्के में भी जहां लगे हैं उनका ब्यौरा भी मैं दे रहा हूं। माननीय सदस्य के नारनौल जिले में ए.पी. फीडरों की संख्या 208 है जिनसे ढाणियों की आपूर्ति चल रही है। इन फीडरों पर पड़ने वाली ढाणियों की कुल संख्या 4214 स्थापित की है । उनमें ट्रांसफार्मर की संख्या 89 और शामिल ढाणियों की संख्या 2877 है।

श्री सीता रामः अध्यक्ष महोदय, मेरे अटेली विधान सभा क्षेत्र में कुल 80 फीडर्ज है जिनमें 34 फीडर्ज पर पैट ट्रांसफार्मर्ज लगे हुए हैं और 46 फीडर्ज पर यह अभी लगने बाकी है। यही नहीं जो पैट ट्रांसफार्मर्ज लगे हुए हैं, वह भी ठीक से आपरेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहां पर टैक्निशियंज नहीं हैं और इस अवस्था में पैट ट्रांसफार्मर्ज यदि खराब हो जाते हैं तो कईं–कईं दिन तक ठीक नहीं होते हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पैट ट्रांसफार्मर्ज के लिए टैक्निशियंज का प्रावधान करके खराब पड़े पैट ट्रांसफार्मर्ज को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाये?

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहां से भी हमारे पास पैट ट्रांसफार्मर्ज के संबंध में कोई डिमांड आती है, वहां पर हमने इनको जल्द से जल्द लगाने का काम किया है फिर भी यदि माननीय सदस्य

समझते हैं कि किसी पार्टिकुलर जगह पर पैट ट्रांसफार्मर्ज लगाने की जरूरत है या कहीं पैट ट्रांसफार्मर्ज खराब हैं तो माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय सदस्य को कोई समस्या नहीं आने दी जायेगी।

डॉ अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पैट ट्रांसफार्मर्ज यदि खराब हो जाते हैं तो उनको कोई ठीक करने वाला टैक्निशियन उपलब्ध नहीं होता है और इस प्रकार कईं–कईं महीने यह ट्रांसफार्मर्ज बंद पड़े रहते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाये ताकि नारनौल में जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है वहां पर इन ट्रांसफार्मर्ज को ठीक करने वाले टैक्निशियंज को डेप्यूट कर दिया जाये। इसका फायदा यह होगा कि यदि कोई पैट ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो इसको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त मेरी माननीय मंत्री जी से यह भी डिमांड है कि चूंकि महेन्द्रगढ़ जिले में बहुत सी ढाणियां हैं इसलिए यहां पर जितने ए.पी. फीडर्ज है उन पर भी जल्द से जल्द पैट ट्रांसफार्मर्ज लगा दिए जायें।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां तक पैट ट्रांसफार्मर्ज की बात है, के संदर्भ में माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे देश में पैट ट्रांसफार्मर्ज बनाने वाली कंपनी बहुत कम हैं। एक बार पुणे में भी इस तरह के ट्रांसफार्मर्ज बनाने के संबंध में ट्राई किया गया था लेकिन वह ट्राई सिस्टम एक तरह से फेल ही हो गया था। गुजरात की एक कंपनी है जो पैट ट्रांसफार्मर्ज बना रही है उन्होंने हमें पैट ट्रांसफार्मर्ज को ठीक करने के लिए अपने टैक्निशियंज भी दिए हैं अतः इन टैक्निशियंज की जहां पर जरूरत होगी वहां पर इन्हें तुरंत प्रभाव से भेजने का काम किया जा रहा है बावजूद इसके अगर फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो माननीय सदस्य इस बारे में पर्सनली बता सकते हैं यह हमारी जिम्मेवारी है और हम माननीय सदस्य को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे।

.....

Supply of Drinking Water

***156. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) Whether it is a fact that drinking water being supplied to villages Pinana, Tihar Malik, Bhadi, Jouli and Rolad of Gohana Assembly Constituency is not clean and adequate; and

(b) If so, the time by which adequate clean drinking water is likely to be supplied in abovesaid villages?

@ मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) व (ख) नहीं, श्रीमान।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि गांव जौली में 234 करोड़ 40 लाख रूपये का नहर आधारित जलघर के नवीनीकरण का कार्य प्रोग्रेस में है और इस कार्य पर अब तक 176 करोड़ 80 लाख रूपये खर्च भी हो चुके हैं और उम्मीद है कि नहर आधारित जलघर के नवीनीकरण का कार्य 31.12.2020 तक पूरा हो जायेगा।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की तरफ से जो जवाब दिया गया है मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और इस प्रकार के जवाब से यह भी लगता है कि शायद सरकार इस तरह के मामलों के प्रति ज्यादा सीरियस नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि गांव पिनाना, तिहाड मलिक, भडी, जौली तथा रौलद में स्वच्छ तथा पर्याप्त पीने के पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है और यहां पर पीने के पानी की बहुत शॉर्टेज है। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के संदर्भ में केवल मात्र जौली गांव से संबंधित ही उत्तर दिया गया है। ऐसा लगता है कि मेरे सवाल को पूरा पढ़ा ही नहीं गया है और मेरे प्रश्न में जो अन्य गांवों का भी जिक्र किया गया है, उन गांवों के संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, अस्वच्छ जल की वजह से दर्जनों बीमारियां पैदा हो जाती है और यही कारण है कि आज अस्वच्छ जल की वजह से बीमार हुए लोगों से अस्पताल भरे पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संदर्भ में पहले भी प्रश्न किया था। मेरे पास मेरे क्षेत्र के 16 गांवों की एक लिस्ट है। इन गांवों में हमारे समय के बने हुए पानी के टैंक्स हैं इसके अलावा कोई अन्य टैंक्स नहीं बनाये गए हैं। अब कहा जा रहा है कि 10 महीने में इन टैंक्स का रिनोवेशन होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर 10 महीने में रिनोवेशन का कार्य होगा तो बताओ हमारे जौली गांव के लोग इतने दिन तक कहां से पीनी पीयेंगे। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में हर आदमी को स्वच्छ पानी प्राप्त करने का राइट होना चाहिए। अब जब जौली गांव में पानी नहीं है तो क्या सरकार इनको पानी मोल लेकर पिलाने का काम करेगी। हर नागरिक को स्वच्छ पानी देना

सरकार का कर्त्तव्य होता है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के और भी बहुत से गांव है जहां पर पीने के पानी की पाइप लाइन नहीं है जिसकी वजह से लोगों को पीने का

.....

@ Reply by the Cooperation Minister

पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें ट्यूबवैल तो लगे हुए हैं लेकिन ट्यूबवैल पानी नहीं दे रहे हैं। कई जगहों पर तो अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा खराब हालत में भी पहुंच गया है। अतः सरकार को इस दिशा में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को अपने क्षेत्र के 16 गांवों की लिस्ट दे दूंगा जिनमें पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे बतायें कि इन गांवों में पीने के पानी की समस्या का समाधान कब तक हो जायेगा ? साथ ही यह भी अनुरोध है कि जो सवाल पूछा जाये सरकार की तरफ से उसे ध्यान से पढ़ा जाये और उसके बाद ही उसका उत्तर दिया जाये।

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गांव–वाइज अपना प्रश्न पूछा है। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि गांव पिनाना की इस समय आबादी 5737 है और यहां पर 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन के हिसाब से पानी दिया जा रहा है। यही नहीं यहां पर एक नहर आधारित जलघर तथा दो सैलो ट्यूबवैल्ज के माध्यम से भी पानी दिया जा रहा है। इसी तरह जहां तक बात गांव तिहाड़ मलिक की है, यहां पर वर्ष 2011 में 2482 जनसंख्या थी और वर्तमान में अर्थात वर्ष 2020 में यह जनसंख्या 2929 की हो चुकी है। यहां पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से जल आपूर्ति की जा रही है और यही नहीं यहां पर नहर आधारित जलघर और एक डीप ट्यूबवैल के माध्यम से भी पानी दिया जा रहा। जहां तक गांव भडी की बात है, यहां पर वर्ष 2011 में 387 जनसंख्या थी और वर्तमान में अर्थात वर्ष 2020 में यह जनसंख्या बढ़कर 457 हो गई है यहां पर भी 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से जल आपूर्ति करने का काम किया जा रहा है। जलापूर्ति योजना आदी को दिनांक 25.08.2009 को चालू किया गया था। पानी की आपूर्ति के लिए एक अलग से नलकूप लगाया गया है। गांव भडी में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। गांव की जलापूर्ति पर्याप्त रूप से की जा रही है और गांव में पीने के पानी की कोई शिकायत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जौली गांव की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम जौली की जनसंख्या 5963 व्यक्ति है तथा जौली गांव की वर्तमान वर्ष 2020 में जनसंख्या लगभग 7036 व्यक्ति हैं। गांव

की जल आपूर्ति 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। पानी की आपूर्ति के लिए 2 उथले नलकूप लगाए गए हैं जिनमें से एक जल घर में स्थित है तथा दूसरा गांव जौली में माइनर के समीप स्थित है। गांव जौली में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार ग्राम रौलद लतीफपुर की जनसंख्या 1921 व्यक्ति हैं तथा रौलद लतीफपुर की वर्तमान वर्ष 2020 में जनसंख्या लगभग 2267 व्यक्ति हैं। गाँव की जल आपूर्ति 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। पानी की आपूर्ति के लिए एक नहर आधारित जलघर तथा 1 उथला नलकूप लगा है। गांव रौलद लतीफपुर में पीने के पानी की कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, विभाग अपने नलकूप के साथ–साथ नहर आधारित जलघरों से आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता का परीक्षण नियमित रूप से करता है। अध्यक्ष महोदय, इन परीक्षण रिपोर्टों से पता चलता है कि गोहाना विधान सभा क्षेत्र के पिनाना, तिहाड़ मलिक, भडी, जौली और रौलद गांवों में पानी की आपूर्ति पीने योग्य हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, संबंधित विभाग के द्वारा माननीय मंत्री जी को गलत सूचना दी गई है। पिनाना गांव में माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिया जा रहा है लेकिन हकीकत यह है कि आधे गांव में पिछले 5 वर्षों में पानी की एक बूंद भी नहीं गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूँ कि आधे गांव में तो जलापूर्ति की पाइप लाइन ही नहीं है। माननीय मंत्री जी पता नहीं किस आधार पर स्टेटमैंट दे रहे हैं कि गांव में 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिया जा रहा है। गांव तेवड़ी, रत्नगढ़, भोला आदि आधे गांवों में तो जलापूर्ति की पाइप लाइन पूरी तरह से नहीं बिछी हुई है। पता नहीं माननीय मंत्री जी किस आधार पर 55 लीटर पानी देने की स्टेटमैंट सदन में दे रहे हैं? माननीय मंत्री जी इस बात की इन्क्वॉयरी करवा लें। भोला गांव के पानी में तो 2000 टी.डी.एस. आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को पानी के बारे में गंभीर चिंतित होना चाहिए ताकि लोगों को पीने का पानी सही मिले।

डॉ0 बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, पानी को लेकर यदि माननीय सदस्य की कोई दिक्कत है तो अपना कोई आदमी विभाग के पास भेज दें, विभाग के अधिकारीगण के साथ ज्वाईंटली इन्सपैक्शन करके यदि कोई भी दिक्कत होगी तो उस दिक्कत को दुरूस्त किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, फिर भी यदि कोई कमी पेशी रह जाती है तो वर्ष 2022 तक हर ग्रामीण घर में एक कार्यात्मक नल के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की दर से जल पहुँचाने अर्थात् 'हर घर

नल से जल' के लिए भारत सरकार द्वारा 'जल जीवन मिशन' के तहत पूरा कर लिया जायेगा।

श्री जगदी□ा नायर : अध्यक्ष महोदय, पानी की सारे हरियाणा को चिंता है। हरियाणा सरकार ने हसनपुर से रैनीवैल परियोजना शुरू की थी।

श्री अध्यक्ष : जगदीश जी, यह अलग प्रश्न है, इसीलिए आप बैठें।

.....

Payment of Sugarcane to the Farmers

***98. Smt. Shalley Choudhary :** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be please to state whather it is a fact the payment of the sugarcane of farmers is outstanding against Naraingarh Sugar Mill for the last few years; if so, the yearwise details thereof togetherwith the time by which the outstanding amount is likely to be paid?

कृशि एवं कियान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रका□ा दलाल) : पिराई सीज़न 2018–19 तक नारायणगढ़ चीनी मिल की तरफ गन्ना मूल्य की कोई राशि बकाया नहीं हैं पिराई सीज़न 2018–19 के लिए चीनी मिल ने 35,31,07,000 रुपये के अग्रीम तिथि के चैक गन्ना किसानों को जारी किए है, जिसमें से 29,82,07,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष राशि 5,49,00,000 रुपये का भुगतान दिनांक 17.03.2020 तक सम्भावित है।

श्रीमती भौली : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। पांच दिन पहले भी हमारे किसान अपनी इस मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। बार–बार उन्हें 6 महीने के अग्रिम तिथि के चैक दिए जाते हैं। इस बात पर माननीय मंत्री जी क्या रिप्लाई देना चाहते हैं?

श्री जय प्रका□ा दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि 5 करोड़ रुपये अग्रिम तिथि के चैक दे दिए गए हैं। माननीय सदस्या का यह भी बताना चाहता हूँ कि किसानों का शेष 5 करोड़ 49 लाख रुपये का भुगतान दिनांक 17 मार्च, 2020 तक हो जायेगा। सरकार भविष्य में गन्ना किसानों के लिए बहुत ही अच्छी नीति बना रही है ताकि गन्ना किसानों की कोई भी पैंडिंग पेमैंट न रहे।

श्रीमती भौली : अध्यक्ष महोदय, बार–बार सरकार द्वारा यही आश्वासन दिया जाता है लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक किसानों को गन्ने की अपनी पेमैंट नहीं मिली है।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्या को हाउस में आश्वासन दिया है कि गन्ना किसानों को 17 मार्च तक भुगतान कर दिया जाएगा ।

श्रीमती शकुंतला खटक : अध्यक्ष महोदय, हाउस में तो अनेक तरह की बातें कही जाती हैं ।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या हाउस से आश्वासन ही तो चाहती हैं ।

श्री अध्यक्ष : शकुंतला जी, आप तो सदन की पुरानी माननीय सदस्या हैं । आप जानती हैं कि विधान सभा की सरकारी आश्वासन समिति सदन में माननीय मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर काम करने के लिए ही बनाई जाती है ।

श्रीमती शैली : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अगर सरकार उनको भुगतान नहीं करती है तो आगे क्या कार्यवाही होगी ?

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर हम उनको भुगतान नहीं करते हैं तो हम भी यहीं हैं और माननीय सदस्या भी यहीं हैं । ये सदन में इस प्रश्न को दोबारा से लगा सकती हैं ।

श्रीमती शैली : अध्यक्ष महोदय, उन किसानों को पिछले 5 सालों से बार–बार यही कहा जा रहा है कि भुगतान कर देंगे लेकिन आज तक उनको भुगतान नहीं किया गया और इस कारण वे किसान धरने पर बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष : शैली जी, माननीय मंत्री जी आपको सदन में आश्वासन दे रहे हैं । आपको उन पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा ।

श्रीमती शैली : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि अगर सरकार इस समयावधि तक उनको भुगतान न कर पाये तो उस मिल को अपने अंडर ले ले ।

श्री अध्यक्ष : शैली जी, माननीय मंत्री जी ने आपके क्वैश्चन का स्पैसिफिक आंसर दिया है कि गन्ना किसानों को 17 मार्च तक पेमेंट कर दी जाएगी ।

श्रीमती शैली : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी उनको भुगतान करने की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं तो ठीक है । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : शैली जी, जब माननीय मंत्री जी ने सदन में भुगतान करने की बात कही है तो पूरी जिम्मेवारी के साथ ही कही है ।

.....

Problem of Drinking Water

***135. Shri Amarjeet Dhanda :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is problem of drinking water in the villages Kharak-Ramji, Sindhvi-Khera, Padhana, Nidana, Nidani, Shamlo-Khurd, Shamlo-Kalan, Gatauli, Gosain-Khera of Julana Assembly Constituency; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to make proper arrangement of drinking water in above said villages?

@ मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :
(क) श्री मान जी, गांव खरक रामजी, सिंधवी खेड़ा, शामलो खुर्द, शामलों कलां, गतौली, गोसांई खेडा में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन ग्रीष्म काल के चरम पर कभी–कभी गांव पदाना, निदाना व निदानी में कच्चे पानी की कमी हो जाती है।

(ख) सुंदर ब्रांच नहर से गांव पदाना, निदाना और निदानी में नहरी पानी उपलब्ध कराने का कार्य 3420.55 लाख रूपए की अनुमानित लागत से प्रगति पर है। जो कि 30.06.2020 तक पूरा होने की संभावना है, इस कार्य के निष्पादन के पश्चात् इन गांवों में पीने के पानी की समस्या का निवारण हो जाएगा।

श्री अमरजीत ढांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जुलाना में कुल 72 गांव हैं । मेरा गांव खरक रामजी है । मेरे हल्के 60 गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की बहुत समस्या है । वहां पर वाटर टैंक बना हुआ है लेकिन नहर से आने वाली पाइप लाईन टूटी हुई है और वह 2 बार बन भी चुकी है । मैं पिछले दिनों अपने .....

@ Reply given by the Coopration Minister

हल्के में धन्यवादी दौरे पर गया था तो सिंधवी खेड़ा, शामलो खुर्द, शामलो कलां, गतौली, गोसांई खेड़ा गांवों में लोगों ने मुझसे पीने के पानी की समस्या की शिकायत की । मेरे हल्के में स्वयं माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय भी गए थे । अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के को पीने के पानी और खेतों के लिए पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है । खेतों में किसान की फसल कभी पानी की कमी और कभी ज्यादा बारिश होने पर पानी की निकासी न होने की वजह से बर्बाद हो जाती है । वहां पर बारिश के न होने पर खेतों में सिंचाई की समस्या रहती है । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि जुलाना हल्के की पानी की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए ।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि गांव खरक रामजी की वर्तमान जनसंख्या 4814 है । इस गांव को पेयजल आपूर्ति 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से दी जा रही है । नहर आधारित जलापूर्ति योजना 2 गांवों के समूह नामतः खरक रामजी और ब्राहमण कलां के लिए गांव खरक रामजी में स्थित है । इस योजना को वर्ष 2007 में शुरू किया गया था । इस नहर आधारित जलापूर्ति योजना खरक रामजी के लिए सुंदर शाखा से नहरी पानी की व्यवस्था की जा रही है और इस गांव में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है । हाल ही में एक अनुमान जिसकी अनुमानित लागत 49.35 लाख रूपए है, से पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा किया गया है । गांव सिंधवी खेड़ा की वर्तमान जनसंख्या 3149 व्यक्ति है । इस गांव को पेयपल आपूर्ति 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से दी जा रही है । नहर आधारित जलापूर्ति योजना 2 गांवों के समूह नामतः सिंधवी खेड़ा और ब्राहमण खुर्द के लिए गांव सिंधवी खेड़ा में स्थित है । इस योजना को वर्ष 1970 में शुरू किया गया था । इस नहर आधारित जलापूर्ति योजना खरक रामजी के लिए, सुंदर रामजी के लिए सुंदर शाखा से नहरी पानी की व्यवस्था की जा रही है और इस गांव में पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं है । गांव पधाना और निदानी की वर्तमान जनसंख्या 8257 व्यक्ति है । इस गांव को पेयजल आपूर्ति 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से दी जा रही है । नहर आधारित जलापूर्ति योजना 2 गांवों के समूह नामतः निदानी और पधाना के लिए गांव निदानी में स्थित है । कभी–कभी ग्रीष्म काल के चरम पर नहरों में नहरी पानी की कमी हो जाने के कारण जलघर पर पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी उपलब्ध

नहीं हो पाता है जिसके परिणामस्वरूप इन गांवों में पेयजल उपलब्धता 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्तर से नीचे चली जाती है । यह कार्य 30.02.2020 तक पूरा होने की संभावना है । इस कार्य के पूर्ण होने के बाद इन गांवों में पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा । गांव नीदाना की वर्तमान जनसंख्या 5114 है । इस गांव को पेयजल आपूर्ति 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से दी जा रही है । नहर आधारित जलापूर्ति योजना गांव निदाना में स्थित है। कभी–कभी ग्रीष्मकाल के चरम पर नहरों में नहरी पानी की कमी हो जाने के कारण जलघर पर पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है जिसके परिणामस्वरूप इस गांव में पेयजल उपलब्धता 55 लीटर प्रति प्रतिदिन के स्तर से नीचे चली जाती है। इसके लिए सुंदर ब्रांच नहर से पधाना और नीदानी के जलघर को नहरी पानी उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है। जिसकी अनुमानित लागत 3420.55 लाख रुपये है जिसमें से 2847.35 लाख रुपये मूल अनुमान प्लस 573.20 लाख सप्लीमेंट्री अनुमान है। यह कार्य दिनांक 30.06.2020 तक पूरा होने की संभावना है। इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् इन गांवों में पीने की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी तरह से गांव शामलो खुर्द की वर्तमान जनसंख्या 2293 है। योजना की जल आपूर्ति की दर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से सप्लाई की जा रही है। गांव शामलो खुर्द को पेयजल आपूर्ति गांव में स्थित स्वतंत्र नहर आधारित जलापूर्ति योजना से की जाती है। इस योजना को वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। नहरी पानी की व्यवस्था सुंदर शाखा से की जाती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण शांत रहें। माननीय सदस्य का क्वैश्चन है और वे अपने क्वैश्चन का रिप्लाई ले रहे हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि अगर कोई माननीय सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों की बात पूछना चाहेगा तो उसकी सारी जानकारी तो देनी पड़ेगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः इसमें माननीय सदस्य ने पार्टिकुलर गांवों के नाम लेकर संबंधित जानकारी मांगी है।

श्री अमरजीत ढांडाः अध्यक्ष महोदय, वहां पर वॉटर टैंक तो बनने लग रहे हैं और पाईप लाईन भी बिछने लग रही है। इसके अतिरिक्त मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिकवेस्ट है कि वहां पर एक सबमर्सिबल पंप लगायी जाए।

.....

To Upgrade the Government Veterinary Dispensaries

***249. Shri Jogi Ram Sihag :** Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Veterinary Dispensaries of villages Sarsod, Satrod Khurd, Dhingtana, Niyana and Bhagana of Barwala Assembly Constituency as Government Veterinary Hospitals; and

(b) if so, the details thereof?

कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रका□ा दलाल) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) उपरोक्त के दृष्टिगत, उत्तर की आवश्यकता नहीं।

श्री जोगी राम सिहाग: अध्यक्ष जी, मेरा जो सवाल है, वह किसानों की आमदनी बढ़ाने से भी जुड़ा हुआ है। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि जो गांव पशु औषधालय बनाने की कंडीशन पूरी करते हैं, उनको पशु चिकित्सालय बनाने में क्या दिक्कत है ? दूसरा सवाल यह पूछा था कि मेरे हल्के के अन्दर 8 गांव ऐसे हैं जो पशु चिकित्सालय की कंडीशन पूरी करते हैं, परन्तु वहां पर पशु औषधालय भी नहीं है। एक तरफ तो सरकार का जोर है कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो वह दूसरी जगह पर अपना इलाज करवाने के लिए जा सकता है। माननीय मंत्री जी यह बताएं कि संबंधित गांवों द्वारा कंडीशन पूरी करने के बाद भी जबाव 'ना' में क्यों है ? मेरे हल्के के गांवों के लोग अपने बीमार पशुओं को ईलाज कहां पर करवाएंगे ? ढ़ाणी गारण गांव के अन्दर 3600 की आबादी है और 1200 घर है। इस गांव में कम से कम 4,000 पशु हैं परन्तु इस गांव में पशु औषधालय भी नहीं है। पशु चिकित्सलाय तो कहां से बनेगा? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे सवाल के जवाब में 'ना' कैसे की गयी है? मेरे सवाल का जवाब 'ना' में है और कह रहे हैं कि इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं?

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, गांव में पशु हॉस्पिटल खोलने के लिए जनसंख्या की कंडीशन 5,000 है और 2 किलोमीटर की परिधि में 3,000 पशु होने चाहिए। हमारी पॉलिसी के अनुसार छोटा चिकित्सालय खोलने के लिए गांव की आबादी 3,000 होनी चाहिए और 2,000 की पशुओं की आबादी होनी चाहिए।

माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में 11 पशु चिकित्सालय और 14 पशु औषधालय हैं। पंचायत जब एक एकड़ जमीन का प्रस्ताव दे देती हैं तो बजट के प्रावधान के हिसाब से हर साल नये–नये चिकित्सालय/औषधालय खोलते हैं। अगले साल में 40 नये पशु चिकित्सालय/पशु औषधालय खोलना प्रस्तावित है। बजट के हिसाब से जिन गांवों में ज्यादा जरूरत होगी तो उसी हिसाब से फैसला किया जाएगा।

श्री जोगी राम सिहाग: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के जिस गांव की आबादी 3,000 से भी ज्यादा है। क्या वहां पर पशु औषधालय भी नहीं खोला जाएगा ? माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब ना में दिया है।

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? मैंने कहा है कि अगले साल 40 पशु चिकित्सालय/पशु औषधालय खोलेंगे तो उसमें आपके विधान सभा क्षेत्र के गांवों में भी पशु औषधालय खोलने के लिए मैरिट पर विचार किया जाएगा।

.....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

.....

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र□नों के लिखित उत्तर

To Shift the Village Khukhrana

***271. Shri Balbir Singh :** Will the Power Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the atmosphere of village Khukhrana is being polluted by the ashes and wastage emitted from Panipat thermal plant and cement factory which are adjacent to this village; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the said village keeping in view of above said problem togetherwith the time by which it is likely to be shifted?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान,

(क) तथा (ख) जबकि पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) की यूनिट 1–4 तथा यूनिट–5 क्रमशः वर्ष 2015 एवं 2019 में बंद होने से प्रदूषण की समस्या कम

हुई है, गांव खुखराना को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके लिए विकास कार्य चल रहे हैं।

To Allot Residential Plots

***69. Shri Ram Karan :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to allot residential plots to Sikligar Community in Shahabad; if so, the details thereof ?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : जी नहीं, महोदय। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

.....

Aayushman Bharat Yojna

***186. Shri Bharat Bhushan Batra :** Will the Medical Education Minister be pleased to state

(a) the terms and conditions on which two shops have been allotted in the name of Amrit Pharmacy under Aayushman Bharat Yojna in the premises of PGIMS Rohtak; and

(b) whether any complaint has been received by the Government regarding irregularities in above said shops; if so, the details thereof together with the action taken by the Government so far?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान् जी,

(क) अमृत फार्मेसी स्टोर आयुष्मान भारत स्कीम के तहत नहीं स्थापित किये गये, बल्कि यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई Affordable Medicines and Reliable Implants for Treatment (AMRIT) के तहत एक पहल है। यह उन सभी दवाओं, प्रत्यारोपण, सर्जिकल लेख/डिस्पोजेबल्स सस्ती कीमतों पर प्रदान करता है, जो विभिन्न केन्द्रीय और राज्य शिक्षण अस्पतालों में निःशुल्क वितरित नहीं की जाती है।

ये स्टोर हिन्दुस्तान लाइफकेयर लिमिटेड (HLL Lifecare Limited), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक सी0पी0एस0यू0 द्वारा संचालित है। राज्य सरकार ने सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आने वाले रोगियों को और आम जनता के रोगियों को भी यह

सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये दुकाने जिन शर्तों पर पी0जी0आई0एम0एस0, रोहतक के परिसर में खोली गई हैं वे विभाग द्वारा अनुमोदित एम0ओ0यू0 के अनुसार निदेशक पी0जी0आई0एम0एस0 रोहतक और मैसर्स हिन्दुस्तान लाइफकेयर लिमिटेड (HLL Lifecare Limited) के बीच हस्ताक्षर होने उपरान्त किया गया है। जिसका अनुलंग्नक-**I** है।

(ख) एक शिकायत प्राप्त हुई है और निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

-259- ANNEXURE-I.

HARYANA S 493154

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TO SET UP, MAINTAIN & OPERATE 'AMRIT PHARMACY' IN PGIMS ROHTAK, HARYANA

This Memorandum of Understanding (MOU) is made on this 03rd August in the year 2018.

BETWEEN

DIRECTOR Post Graduate Institute of Medical Sciences, Rohtak referred as "PGMIS", which expression shall unless otherwise repugnant to the context shall mean and include their executors, administrators, legal representatives and all permitted assigns) on the FIRST PART

AND

HLL LIFECARE LIMITED, a Company incorporated under the Companies Act 1956 with Registered Office at HLL Bhavan, Poojappura, Thiruvananthapuram-695 012, Kerala, India, (hereinafter referred to as "HLL", which expression shall unless otherwise repugnant to the context shall mean and include its successors-in-interest and all permitted assigns) and represented by Manager(Retail Business) on the SECONDARY PART

For the purpose of this MoU, both "HLL" and "PGIMS" are collectively called "Parties" and individually as "Party".

WHEREAS HLL is in the business of setting up, maintain and operate Generic Pharmacies, AMRIT (Affordable Medicines and Reliable Implants for Treatment) Pharmacies, Lifecare Centers (Retail Outlet for Implants, Surgical, Pharmaceutical products and Opticals), Pathlabs and Diagnostic Imaging Services at different Centres across India under the instruction/direction of Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), Government of India.

WHEREAS "PGIMS" has requested HLL to set up, maintain and operate an "AMRIT Pharmacy" at "PGIMS" PGIMS , campus in pursuance of the letter stated above to provide drugs, surgical and implants to patients of "PGIMS" & general public based on valid prescription and to the hospital stores requirement at an affordable cost

AND WHEREAS HLL has agreed to set up, maintain and operate an AMRIT Pharmacy at "PGIMS" , campus and provide drugs, surgical and implants to patients of "PGIMS" & general public based on valid prescription and to the hospital stores requirements at an affordable cost.

The parties have discussed the matter and have reached an understanding which they now desire to reduce it into writing as follows

HLL agrees:

1. To set up, maintain & operate AMRIT Pharmacy inside the PGIMS , campus, spanning a total approximate area of 300 sq. ft. within the existing building (hereinafter referred as "Center").

2. To provide medicines (including vaccines and sera), surgical consumables, implants (Hearing Aids, Spectacles, Contact lens, Cardiac-implants, Ortho implants, etc.) to the patients of "PGIMS" & general public based on valid prescription and to the hospital stores requirements at an affordable cost.

3. To carry out required modification in the allocated space at PGIMS, by interior furnishing, electrical and HVAC works at HLL's cost.

4. To install proper cooling system and refrigerators fulfilling the storage conditions of the drugs.

5. To bear the costs for maintenance of equipments, manpower costs and running costs of the Center and the cost of consumables.

6. To install requisite Computerized Billing software for inventory management and to establish an electronic record keeping system for dispensing the medicines against the prescription with our existing software.

[illegible] ID cards and Vehicle passes to HLL employees employed at the Center for easy entry and parking inside "PGIMS".

To assign an official as one point contact between HLL and "PGIMS" for the smooth functioning of the Center.

7. To pay the bills to HLL on monthly basis within 30 days from the date of submission of bills of the items supplied to IPD and to other Stores Requirements of "PGIMS". The RTGS/NEFT/CHEQUE/Demand Draft should be in the name of M/s HLL Lifecare Ltd, HDFC Account no. 09960330000108

8. To establish mechanism for periodical review to ensure that:

   a) The product range is comprehensive and products are available across product range.

   b) The prices of drugs sold at the center are reasonable and significantly lower than the market prices.

9. To allow for extension of counters of medicine/implants within premises as and when required.

10. Both the parties will be bound by the terms and conditions of the agreement/MoU

Period of MOU

This MoU shall commence from the date of entering the agreement, and be valid for a period of 05 years,with provision for yearly review by the "PGIMS", unless otherwise terminated by either parties under intimation to the MoHFW, GoI or by the MoHFW, GoI, by way of issuing any direction.

Modification of Terms of MoU

The terms of this MoU can be modified by the parties on mutual consent.

Termination

Either Party may terminate this agreement by giving an advance notice of 90 days in writing to the Other Party, describing the reason behind such notice of termination with a copy to the MoHFW, GoI.

Dispute Resolution

In case of any disputes, both the parties agree to resolve it by mutual discussions.

-235-

Jurisdiction

The parties agree that the local courts of the District in which the PGIMS Rohtak is situated Rohtak Chandigarh shall have exclusive jurisdiction for all disputes and difference arising out of this Agreement.

ARBITRATION

All the questions and disputes arising out of the agreement or in interpretation of the words in the agreement or the right of entitlement of the parties, whatsoever between the parties shall be referred to a sole arbitrator appointed by the State Government of Haryana and the award of the arbitrator shall be final and binding on both the parties.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have caused these presents to be signed by their corporate, officers and affix the seal in the presence of the following witness on the day and year first above written.

Signed and Delivered for and on behalf of
PGIMS ROHTAK, HARYANA

By its Director(PGIMS, ROHTAK)

DIRECTOR
Pt. B.D. Sharma, PGIMS
Rohtak-124001 (Hr.)

In presence of

WITNESSES:

1.

2.

Signed and Delivered for and on behalf of
HLL LIFECARE LTD.
THIRUVANANTHAPURAM-695012, KERALA

03/08/2018

By its Manager
(Retail Business Division)

WITNESSES:

1.

2.

Pharmacist

3/8/2018

Annexure-II

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA V 242291

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TO SET UP, MAINTAIN & OPERATE 'AMRIT PHARMACY' IN PGIMS ROHTAK, HARYANA

This Memorandum of Understanding (MOU) is made on this 25 July, 2019.

BETWEEN

DIRECTOR Post Graduate Institute of Medical Sciences, Rohtak referred as "PGIMS", which expression shall unless otherwise repugnant to the context shall mean and include their executors, administrators, legal representatives and all permitted assigns) on the FIRST PARTY.

AND

HLL LIFECRE LIMITED, a Company incorporated under the Companies Act 1956 with Registered Office at HLL Bhawan, Poojappura, Thiruvananthapuram-695012, Kerala, India (hereinafter referred to as "HLL", which expression shall unless otherwise repugnant to the context shall mean and include its successors-in-interest and all permitted assigns) and represented by Manager (Retail Business) on the SECOND PARTY.

For the purpose of this MoU, both "HLL" and "PGIMS" are collectively called "parties" and individually as "Party".

WHEREAS HLL is in the business of setting up, maintain and operate Generic Pharmacies, AMRIT (affordable Medicines and Reliable Implants for Treatment) Pharmacies, Lifecare Centers (Retail Outlet for implants, Surgical, Pharmaceutical products and Opticals), Pathlabs and Diagnostic Imaging Services at different Centres across India under the instruction/ Direction of Ministry of Health and family Welfare (MoHFW), Government of India.

WHEREAS "PGIMS" has requested HLL to set up, maintain and operate an "AMRIT Pharmacy" at "PGIMS" PGIMS, campus in pursuance of the letter stated above to provide drugs, surgical and implants to patients of "PGIMS" & general Public based on valid prescription and to the hospital stores requirement at an affordable cost.

AND WHEREAS HLL has agreed to set up, maintain and operate and AMRIT Pharmacy at "PGIMS", campus and provide drugs, surgical and implants to patients of "PGIMS" & general public based on valid prescription and to the hospital stores requirements at an affordable cost.

The parties have discussed the matter and have reached an understanding which they now desire to reduce it into writing as follows:

HLL Agrees:

1. To set up, maintain & operate AMRIT Pharmacy inside the PGIMS campus, spanning a total approximate area of 600-800 Sq. ft within the existing building (hereinafter referred as "Center").
2. To provide medicines (including Vaccines and sera), surgical consumables, implant (Hearing Aids, Spectacles, Contact lens, Cardiac-implants, Ortho implants, etc.) to the patients of "PGIMS" & general public based on valid prescription and to the hospital stores requirements at an affordable cost.

3. To carry out required modification in the allocated space at PGIMS, by interior furnishing, electrical and HVAC works at HLL's cost.
4. To install proper cooling system and refrigerators fulfilling the storage conditions of the drugs.
5. To bear the costs for maintenance of equipments, manpower costs and running costs of the Center and the cost of consumables.
6. To install requisite Computerized Billing software for inventory management and to establish an electronic record keeping system for dispensing the medicines against the prescription with our existing software.
7. To employ trained pharmacist, dispensing chemists and billing staff as per retail FDA norms and comply all statutory requirements of FDA for efficient operation of the Center.
8. To ensure that the medicine product range is comprehensive and to make available all the essential drugs and medicines required for OPD, IPD as well as stores requirement of PGIMS.
9. To establish a mechanism to ensure the quality of the products supplied through the center.
10. To ensure that the prices offered are reasonable and significantly lower than the Market prices and same price structure will be adopted for patients of "PGIMS" and general Public.
11. To develop an effectively system for crowd management and to regulate the patient footfall.
12. To install electronic display system to communicate with general public and to provide sitting area for the patients.
13. To ensure that AMRIT Pharmacy is open 24 X 7 including Public holidays to provide uninterrupted services from the Center.

14. To ensure medicines, consumables and implants are supplied with the required time.
15. To ensure that availability and dispensing of narcotic/psychotropic drugs based on valid prescription.
16. To establish a system for checking spurious, adulterated and misbranded drugs.
17. To allow inspection by the Inspection committee of PGIMS can inspect the premises under the supervision of Medical Superintendent.

"PGIMS" agrees:

1. To provide a suitable built up area approximate area of 600-800 Sq. ft within the existing building on a rent free basis as directed by MoHFW, GoI with utilities like electricity, water etc. required for the successful functioning of the Center at PGIMS campus to be paid by HLL as per actual.
2. HLL bear the expenditure of publicity among the Patients (IP/OP) about the center and availability of Medicines, Surgical and implants.
3. To circulate the list of available medicines, Surgical and Implants among the doctors, Nurses and other "PGIMS" Staff.
4. To undertake a survey among the medical fraternity of the PGIMS provide a feed back to HLL about the required medicines for the center once in three months.
5. To issue ID cards and Vehicle passes to HLL employees employed at the Center for easy entry and parking inside "PGIMS".
6. To assign an official as one point contact between HLL and "PGIMS" for the smooth functioning of the Center.
7. To pay the bills to HLL on monthly basis within 30 days from the date of submission of bills of the items supplied to IPD and to other Stores Requirements of "PGIMS". The RTGS/NEFT/CHEQUE/Demand Draft

should be in the name of M/s HLL Lifecare Ltd., HDFC account No. 09960330000108.

8. HLL to establish mechanism to ensure that;
   a) The product range is comprehensive and products are available across product range.
   b) The prices of drugs sold at the center on reasonable and significantly lower than the market prices.
9. To allow for extension of counters of medicine/implants within premises as and when required.
10. Both the parties will be bound by the terms and conditions of the agreement/MoU.

Period of MOU

This MoU shall commence from the date of entering the agreement, and be valid for a period of 5 years with provision for yearly review by the "PGIMS", unless otherwise terminated by either parties under intimation to the MoHFW, GoI or by the MoHFW, GoI by way of issuing any direction.

Modification of Terms of MoU

The terms of the MoU can be modified by the parties on mutual consent.

Termination

Either Party may terminate this agreement by giving an advance notice of 90 days in writing to the Other Party, describing the reason behind such notice of termination with a copy to the MoHFW, GoI.

Dispute Resolution

In case of any disputes, both the parties agree to resolve it by mutual discussions.

Jurisdiction

The parties agree that the local courts of the District in which the PGIMS Rohtak is situated at Rohtak shall have exclusive jurisdiction for all disputes and difference arising out of this Agreement.

ABRITRATION

All the questions and disputes arising out of the agreement or in interpretation of the words in the agreement or the right of entitlement of the parties, whatsoever between the parties shall be referred to a sole arbitrator appointed by the State Government of Haryana and the award of the arbitrator shall be final and binding on both the parties.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have caused these presents to be signed by their corporate, officers and affix the seal in the presence of the following witness on the day and year first above written.

Signed and delivered for and
on behalf of
PGIMS, Rohtak, Haryana

27/12/19

By its Medical Superintendent
(PGIMS, Rohtak) For Director - PGIMS -
In presence of

Witness:
1. Satya N (Exptt MS)
2. S (OMS)

Signed and delivered for and
on behalf of
HLL LIFECARE LTD.
THIRUVANANTHAPURAM
695012, KERALA.

07/08/19

By its Manager
(Retail Business Division)

Witness:
1. Anil (Asstt. Pharmacist) 7/8/19
2. Amit Kumar (Pharmacist) 7/8/19

To Protect the Yamuna River

***201. Shri Bishan LaL Saini :** Will the Mines and Geology Minister be pleased to state the steps being taken by the Government to protect the Yamuna River in district Yamuna Nagar from impact of mining?

परिवहन मंत्री (श्री मूल चंद भार्मा) : श्री मान् जी, यमुना नदी में बोल्डर, ग्रेवल एवं रेत जैसे खनिज उपलब्ध हैं, जोकि निर्माण गतिविधियों में प्रयुक्त होते हैं। इनके उत्खनन के लिए खनिज अनुदान विभिन्न प्रतिबन्धों के अंतर्गत, जोकि सिंचाई विभाग की सहमति से तैयार किये जाते हैं ताकि नदी तल/नदी को बचाया जा सके तथा विभिन्न पर्यावरणीय चिंताओ को दूर किया जा सके, प्रतिस्पर्धात्मक बोली/ई–निलामी द्वारा प्रदान किये जाते हैं। नदी तल से खनिज उत्खनन के लिए अनुदान इस शर्त के साथ प्रदान किए जाते हैं कि खनिज का उत्खनन नदी तल के बीच वाले केवल 3/4 भाग से हो तथा अधिकतम उत्खनन साथ लगते तल से केवल 3 मीटर तक हो। इसके अतिरिक्त खनन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण संबंधी मंजूरी लेने उपरान्त ही किया जा सकता है। खनिज रियायत धारकों को हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड से स्थापना करने की सहमति तथा संचालित करने की सहमति भी लेनी होती है। इस प्रकार खनन कार्य यमुना नदी तथा पर्यावरण को बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की शर्तों के अधीन किए जाते हैं।

Shifting of Sainik School

***26. Shri Chiranjeev Rao :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to Shift Sainik School from Rewari to its newly constructed building in village Gothra of district Rewari: if so, the time by which it is likely to be shifted ?

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री ओम प्रका□ा यादव) : हाँ, श्री मान जी । सैनिक स्कूल को रेवाड़ी से स्थायी स्थान गोठड़ा टप्पा खोरी में स्थानान्तरण होने में लगभग 36 महीने का समय लगने की संभावना है।

.....

Status of Boosters

***118. Smt. Seema Trikha :** Will the Urban Local Bodies Minister pleased to state -

(a) the status of boosters installed by NBCC and Municipal Corporation in Badkhal togetherwith the number of boosters which are not functional; and

(b) whether any special arrangements have been made by the Government to supply water in the upcoming summer season togetherwith the details thereof ?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

महोदय, बड़खल विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम फरीदाबाद द्वारा 17 बूस्टिंग स्टेशन स्थापित किये गए हैं, जिनमें से 13 बूस्टिंग स्टेशन चालू हालत में हैं व दो बूस्टिंग स्टेशन मेवला महाराजपुर और लकरपुर गांव में निर्माणाधीन है । सैक्टर–41 के एक बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण पूरा हो गया है परन्तु ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी निर्माणाधीन होने के कारण अभी चालू नहीं है। सैक्टर–48 का एक बूस्टिंग स्टेशन बरसाती कुओं के पानी की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण प्रयोग लायक नहीं है और वर्तमान में सैक्टर–48 के पुराने बूस्टिंग स्टेशन के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है।

आगामी गर्मियों के मौसम में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए दादसिया क्षेत्र में 12 नए नलकूप स्थापित किए गए हैं और इन्हे मुख्य जल आपूर्ति प्रणालि से जोड़ने का कार्य निविदा प्रक्रिया में है। तीन अतिरिक्त नलकूप लाईन नंबर 4 से जोड़े जा रहे हैं जोकि सैक्टर–48 के बूस्टिंग स्टेशन को पानी की आपूर्ति करेंगे।

.....

Construction and Repair of Roads

*51. **Shri Pardeep Chaudhary :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the road from village Bhurewal to Mauli in the Kalka Constituency has not been constructed so far despite the announcement of the Hon'ble Chief Minister in year 2014-

15; if so, the reasons thereof togetherwith the time by which the said road is likely to be constructed ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) :हां, श्रीमान जी। इस सड़क के साथ संरक्षित वन भूमि के डाईवर्जन की मंजूरी के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका, जो कि 19.01.2020 को प्राप्त हुई है। कार्य के शुरू होने के बाद 18 महीने के अंदर पूर्ण होने की संभावना है, जिसे 4 महीने के अंदर शुरू किए जाने की सम्भावना है।

.....

To Start Cashless Medical Facility

***73. Shri Varun Chaudhary :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start cashless medical facility for Haryana Government Employees; if so, the time by which it is likely to be implemented togetherwith the details thereof ?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, कैशलैस चिकित्सा सुविधा 6 जीवन विनाशक चिकित्सा स्थितियों के लिए दिनांक 30.11.2017 से पहले ही दी जा रही है।

.....

अतारांकित प्र□न एवं उत्तर

2. Shri Mewa Singh: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Middle School, of Village Kaulapur in Ladwa Assembly Constituency;

(b) if so, the time by which it is likely to be upgraded?

□िक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल) : (अ) नहीं, श्रीमान।

(ब) इसलिए, प्रश्न नहीं उठता।

.....

Number of Minors Constructed

13. Dr. Krishan Lal Middha : Will the Chief Minister be pleased to state the number of minors constructed and rehabilitated in state for

making canal system effective during the period from 2015 to 2019 togetherwith the details of the amount spent on it ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, एक विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

श्रीमानजी, नहर प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए 2015 से 2019 की अवधि के दौरान 30105.66 लाख रू0 खर्च करके 206 माइनरों का पुनर्वास किया गया है । इसके अलावा 38 माइनरों के पुनर्वास का कार्य 6526.09 लाख रू0 की लागत से प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, खेड़ी गगन माइनर और नई बास माइनर नामक 2 नई माइनरों का निर्माण 179.94 लाख रू0 की लागत से वर्ष 2017–18 में किया गया ।

वर्श 2015 सें 2019 की अवधि के दौरान पुनर्वास की योजनाओं का वर्शवार ब्यौरा

क0 सं0	यूनिट	पुनर्वासित माइनरों की संख्या	खर्चा (रू0 लाख में)
2015–2016			
1	भाखड़ा जल सेवाएं यूनिट	11	1130.57
2	यमुना जल सेवाएं यूनिट (उत्तर)	07	717.76
3	उठान नहर यूनिट	24	3373.54
4	निर्माण यूनिट	03	559.16
2016–2017			
1	भाखड़ा जल सेवाएं यूनिट	11	2691.05
2	यमुना जल सेवाएं यूनिट (उत्तर)	11	1397.51
3	उठान नहर यूनिट	08	433.19
4	निर्माण यूनिट	01	88.25
2017–2018			
1	भाखड़ा जल सेवाएं यूनिट	17	3235.49
2	यमुना जल सेवाएं यूनिट (उत्तर)	10	955.56
3	उठान नहर यूनिट	08	425.14
4	निर्माण यूनिट	02	201.71
2018–2019			
1	भाखड़ा जल सेवाएं यूनिट	23	2870.25
2	यमुना जल सेवाएं यूनिट (उत्तर)	10	2229.88
3	उठान नहर यूनिट	22	3062.97
4	निर्माण यूनिट	04	568.62
5	यमुना जल सेवाएं यूनिट (दक्षिण)	02	255.42
2019–2020			
1	भाखड़ा जल सेवाएं यूनिट	21	3092.04
2	यमुना जल सेवाएं यूनिट (उत्तर)	09	2578.05
3	उठान नहर यूनिट	02	239.50
कुल पूर्ण हो चुकी योजनाएं (2015–2019)		**206**	**30105.66**

वर्श 2015 सें 2019 के दौरान जिन योजनाओं के पुनर्वास का कार्य प्रगति पर है, का वर्शवार ब्यौरा

क0 सं0	यूनिट	माइनरों की संख्या जिनका पुनर्वास कार्य प्रगति पर है	खर्च (रू0 लाख में)	कार्य पूरा होने की संभावित तिथि
2018–2019				
1	उठान नहर यूनिट	01	158.82	30.06.2021
2	निर्माण यूनिट	12	1329.73	30.06.2021
2019–2020				
1	भाखड़ा जल सेवाएं यूनिट	12	1407.68	30.06.2021
2	यमुना जल सेवाएं यूनिट (उत्तर)	08	3351.78	30.06.2021
3	उठान नहर यूनिट	01	14.14	30.06.2021
4	निर्माण यूनिट	04	263.94	30.06.2021
कुल योजनाएं जिनका कार्य प्रगति पर है (2015–2019)		38	6526.09	

वर्श 2015 सें 2019 के दौरान बनाई गई नई माइनरों का वर्शवार ब्यौरा

क0 सं0	यूनिट	माइनरों की संख्या	खर्च (रू0 लाख में)
2017–18			
1	भाखड़ा जल सेवाएं यूनिट	02	179.94
कुल नव निर्मित योजनाएं (2015–2019)		02	179.94

To Disburse Old Age Pension at the Door Step

6. **Shri Pardeep Chaudhary** : Will the Minister of State for Social Justice and Empowerment be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to disburse old age pension at the door step to seriously ill and weak old person; if so, the time by which the proposal is likely to be materialized?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (श्री ओम प्रका□ा यादव) : महोदय, वे लाभार्थी जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक हैं और विकलांगता के कारण श्य्याग्रस्त हैं वे वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ, सम्बन्धित बैंक/डाकघर को अपने द्वार पर पैंशन राशि का वितरण करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करके सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

.....

Total Grant released to Panchayats

22. Shri Kuleep Vats : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the total grant released for the development work in village Panchayats of Badi Assembly Constituency during the last 5 years togetherwith the details of the works for which the said grant has been released?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : पिछले पांच वर्षों में विकास एवं पंचायत तिभाग तथा एच.आर.डी.एफ. बोर्ड द्वारा बादली विधान सभा क्षेत्र के खण्ड बादली की 26, खण्ड झज्जर की 39 खण्ड मातनहेल की 5 तथा खण्ड साल्हावास की 27 ग्राम पंचायतों में कुल 323.59 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। यह राशि आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गउघाट, सामुदायिक भवन, स्कूल के कमरे, वाटर चैनल, आई.पी.बी. सड़क/गलियां/फिरनी, व्यायामशाला, एस.सी./बी.सी. /साामान्य/महिला चौपालें, स्पोर्टस स्टेडियम, पंचायत घर आदि के निर्माण तथा पंचायत घर, आदि निर्माण तथा पंचायत घर, शमशान घाट, कब्रिस्तान, एस.सी./बी. सी./सामान्य/महिला चौपालों, स्कूलों, हडडा रोडी, पशु हस्पताल, जोहडों आदि की चार दिवारी, शमशान घाट तथा कब्रिस्तान में शैडव रास्तों के निर्माण आदि विकास कार्यों हेतु जारी की गई है।

.....

Shortage of Doctors And Other Staffs

44. Shri Sita Ram Yadav : Will the Health Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is shortage of Doctors and other staff in Civil Hospital of Ateli;

(b) whether there is also a fact that the X-Ray Machine in said hospital is not functional for the last 6 months; and

(c) if so, whether there is any proposal under the consideration of Government to fill up the vacant post of Doctors alongwith to provide facility of ECG and minor operation in the abovesaid hospital togetherwith the time by which the shortage of staff and other facilities is likely to be met out?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) हां, श्रीमान् जी

(ख) एक्स–रे मशीन चालू हालत में है लेकिन रेडियोग्राफर प्रसूति अवकाश पर है।

(ग) चिकित्सकों के पदों को भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने उपरान्त भर लिया जाएगा जो कि प्रगति में है। अन्य अमले के लिए मांग पत्र भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा चुका है। ई.सी.जी. मशीन उपलब्ध है और चालू हालत में है। अन्य सभी चिकित्सा सुविधाएं जैसे 24X7 आपातकालीन सुविधाएं, माइनर आपॅरेशन, संस्थागत प्रसूतियां इत्यादि भी उपलब्ध हैं।

.....

To Construct Permanent Vegetable Market

55. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct any permanent vegetable market in Badhra; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रका□ा दलाल) : जी नहीं।

.....

To Upgrade Goriwala Sub-Tehsil

35. Shri Amit Sihag : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that an announcement was made by Hon'ble Chief Minister during the rally in 2017 to upgrade Goriwala Sub-Tehsil as Tehsil; and

(b) if so, the time by which it is likely to be upgraded?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : नहीं, श्रीमान् जी।

.....

To Set Up Health Centers

56. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up any Health Center for the workers in various

crushers zones of Badhra Assembly constituency; if so, the time by which it is likely to be set-up?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, जी।

Shortage of Drinking Water

24. Shri. Kuldeep Bishnoi: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is acute shortage of drinking water in Budak, Bandaheri, Kutia Kheri, Telanwali, Sundawas, Kharia, Dobhi, Bagla, Dhandoor and Bir Babran of Adampur Assembly Constituency; if so whether there is any proposal under consideration of the Government to supply canal based drinking water in the above said villages?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव बंदाहेड़ी, कुतिया खेड़ी, तेलनवाली सुन्दावास, खारिया, धोबी, बगला, ढांडूर और बीर बबरन में पीने के पानी की कमी नहीं है। हालांकि, गर्मी के मौसम के दौरान, गांव बुड़क में नहरी पानी की कमी हो जाती है। वर्तमान में गांव बुडक में मौजूदा नहर आधारित जलापूर्ति योजना के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जाती है जो कि 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से जलआपूर्ति के लिए बनाई गई थी। इस जलापूर्ति योजना का नहरी पानी का आउटलेट कनेक्शन बुडक सब माइनर के अंतिम छोर पर है जहां पर विशेष रूप से ग्रीष्म काल के दौरान सतत् पानी की कमी रहती है। इसके परिणामस्वरूप, इस पेयजल योजना को पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे सतत् नहरी पानी की कमी बनी रहती है। आवश्यक मात्रा में नहरी पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण, पेयजल आपूर्ति कम कर दी जाती है। जिसके कारण 70 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है।

नहरी पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्र स्तर पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के साथ विस्तृत परामर्श के पश्चात एक नहरी पानी के प्रबन्धन की परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 2554.15 लाख रूपए है, नाबार्ड योजना के तहत दिनांक 29.01.2020 को मंजूरी की गई है, जिसके अंतर्गत 7 जलघरों नामतः बुडक, गोरछी, सरसाना, बालसमंद नया व पुराना, बसरा, और कीर्तान के लिए नहरी पानी का प्रबन्धन किया जाएगा। इस परियोजना के तहत चौधरीवाली माइनर के RD 20000-L से नहरी पानी के उठान प्रस्तावित है। जहां

पर नहरी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित है। यह परियोजना की निविदा प्रक्रिया में है तथा यह प्रयोजना 31.12..2021 तक पूरा होने की संभावना है। इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात् नहरी पानी की उपलब्धता की कमी दूर हो जाएगी तथा मौजूदा नहर आधारित जल घर से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी।

इसके अलावा गांव सुन्दावास और बागला में समय बीतने के साथ पेयजल योजना के तहत बनाई गई संरचनाओं की क्षमता में कमी आ गई है। पेयजल योजना के अंतर्गत बनाई गई संरचनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमान जिनकी लागत 51.55 लाख रूपए और 226.10 लाख रूपए दिनांक 06.09.2018 तथा दिनांक 03.02.2020 को मंजूरी दी गई है। जिनके तहत कार्य क्रमशः 30.06. 2020 तथा 30.09.2021 तक पूरा होने की संभावना है। इन परियोजनाओं के तहत कार्य निष्पादन के पश्चात् इन गांवों में पीने के पानी की कमी का समाधान हो जाएगा।

To Construct Building of PHC

31. Shri Sri Krishan Hooda : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start construction work of PHC Building of village Baroda; if so, time by which it is likely to be started?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : हां श्रीमान जी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरोदा मोर जिला सोनीपत के भवन निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है जिसके लिए 360 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सरकार द्वारा 05.07.2019 जारी की गई है। इस भवन के निर्माण के लिए 09.09.2019 को लोक निर्माण विभाग द्वारा टेन्डर भी प्राप्त किया गया था। कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग सोनीपत की रिपोर्ट के अनुसार भवन की जगह बदल दी गई व मुख्य वास्तुकार हरियाणा से पुनः भवन का प्रारूप तैयार करवाकर इस शर्त के साथ अनुमोदित कर दिया गया कि भवन के लिए विवादित भूमि का मालिकाना हक जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा निश्चित किया जाएगा। मामला जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी सोनीपत के पास विचाराधीन है। भूमि के निश्चित होने के उपरान्त, भवन का निर्माण कार्य आरम्भ होने में तीन मास का समय लगेगा।

.....

Construction of Veterinary Hospitals

57. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state the time by which the construction work of Veterinary Hospitals in villages Rudrol, Shyam Kalan, Unn, Badhra, Badrai and Bhandwa of Badhra Assembly Constituency is likely to be completed?

कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रका□ा दलाल) : गांव श्यामकलां, बाढड़ा एवं भांडवा में पशु चिकित्सा संस्थाओं का निर्माण कार्य 2020–21 के दौरान करवाया जाएगा; जबकि, गांव रूदड़ोल, ऊन और बदराई में नई पशु चिकित्सा संस्था खोलने का मामला सरकार की नीति के अनुसार सम्भव नहीं है।

.....

To Re-construct the Road

30. Smt. Nirmal Rani : Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the road from village Sanpera to village Shahpur Taga in Ganaur Assembly Constituency is in very bad condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to re- construct the abovesaid road togetherwith the time by which it is likely to be re- constructed ?

कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रका□ा दलाल) : (क) जी हाँ।

(ख) इस सड़क की विशेष मरम्मत करने हेतू 43.22 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति 20.02.2020 को प्रदान कर दी गई है तथा यह कार्य 31.10.2020 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

.....

To Re-Construct/ Widen the Road

29. Shri Subhash Gangoli : Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state –

(a) whether it is a fact that road from village Kharal to village Ujhana of Narwana Assembly Constituency is in bad condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct and widen the above said road togetherwith the time by which it is likely to be reconstructed/ widened ?

कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रका□ा दलाल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ;

(ख) इस सड़क को पुनर्निर्मित तथा चौड़ा करने हेतू 221.03 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति 20.02.2020 को प्रदान कर दी गई है तथा यह कार्य 31.03.2021 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

.....

Number of Private Schools

48. Shri Shamsher Singh Gogi : Will the Education Minister to be please to state the following details of private schools opened in Assandh Assembly Constituency-

(i) the number of private schools imparting free education under Rule 134(A) of Haryana School Education Rules;

(ii) the total number of enrollments;

(iii) the total amount reimbursements to schools by the Government;

(iv) the total amount pending towards Government for reimbursement to private school togetherwith the reasons of delay?

□िक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : श्रीमान जी, विधानसभा क्षेत्र असंध की प्राईवेट स्कूलो से संबंधित सूचना निम्नानुसार है–

(i) हल्का क्षेत्र असंध, जिला करनाल में हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली के नियम 134–ए के तहत निशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले प्राईवेट स्कूलों की सख्या 31 है।

(ii) विधार्थियों की संख्या 485 है।

(iii) हरियाणा सरकार द्वारा प्राईवेट स्कूलों को वर्श 2015–16 से 2018–19 के दौरान राक्षि 13,07,200/– की प्रतिपूर्ति की गई है।

(iv) वर्श 2019–20 के लिये कोई मांग प्राप्त नही हुई है।

Construction of Park-cum-Vyayamshalas

58. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the time by which construction work of the Park-cum-Vyayamshalas announced by the Hon'ble Chief Minister in villages Ghasola, Unn, Balrod, Kakroli Sardara, Karirupa, Mandi Kehar, Nandha, Mehra, Arya Nagar and Mauri of Badhra Assembly Constituency is likely to be completed.

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : तालिका सदन के पटल पर रखी जाती हैं।

आर्य नगर बालरोड घासोला काकरोली सरदारा कारी रूपा मंडी केहर मेहरा मौड़ी नांधा उण में पार्क-कम-व्यामशालाएँ

क्रम संख्या	सीएम घोषणा कोड न॰	गाँव	स्वीकृत राशि	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि
1.	24283	आर्य नगर	4935000	प्रगति पर	31.5.2020
2.	24277	बालरोड	3330000	प्रगति पर	31.5.2020
3.	24275	घासोला	3330000	प्रगति पर	31.5.2020
4.	24278	काकरोली सरदारा	3678000	प्रगति पर	31.5.2020
5.	24279	कारी रूपा	4935000	प्रगति पर	31.5.2020
6.	24280	मंडी केहर	3242000	प्रगति पर	31.5.2020
7.	24281	मेहरा	3195000	प्रगति पर	31.5.2020
8.	24284	मौड़ी	4935000	प्रगति पर	31.5.2020
9.	24282	नांधा	4935000	प्रगति पर	31.5.2020
10.	24276	उण	3330000	प्रगति पर	31.5.2020

.....

विभिन्न मामले उठाना

12:00 बजे **श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, अब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करवाने से पहले हमें जीरो ऑवर में बोलने की अनुमति दी जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जब आपकी अनुमति होगी तभी तो माननीय सदस्य अपने हल्के की बात करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने पहली बार सबसे ज्यादा समय जीरो ऑवर पर बोलने के लिए दिया है और इस बात के लिए हमारी पार्टी आपकी बढ़ाई करती है लेकिन अब आप खुद ही इस पर किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, जीरो ऑवर पर बोलने के लिए कल हाउस में किसी भी माननीय सदस्य के पास कोई विषय नहीं था। इस बारे में मैंने कल हाउस में बोलने का काफी समय माननीय सदस्यों को दिया था। (शोर एवं व्यवधान) मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र की डिमांड पर ही बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य अपने–अपने मुद्दों पर ही बोलेंगे। We speak only on matters which are concerning to the entire State nothing else.

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि मैंने कल हाउस में सभी माननीय सदस्यों को जीरो ऑवर पर बोलने का बहुत समय दिया था, केवल सिर्फ दो माननीय सदस्यों ने इस महान सदन में अपने विषय पर चर्चा की थी बाकी माननीय सदस्यों ने विधान सभा क्षेत्र से रिलेटिड समस्या के बारे में जिक्र किया था।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की समस्या पर नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है किरण जी।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 2019 में हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के बारे में कहा था कि वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको एस.पी.ओ. (विशेष पुलिस ऑफिसर) के पद पर

नियुक्त किया था लेकिन उस समय यहां पर सदन में मुझे यह आश्वासन दिया था कि जो इनकी नौकरी और भविष्य है, वह सुनिश्चित की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी सदन में उपस्थित थे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रीमती किरण चौधरी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को क्यों हटाया गया था? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 साल से सत्ता में है और इसी हाउस में मुझे सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था, मैं इस बारे में पूछना चाहती हूं। Let me talk. I am talking positively and do not have any negativity. (शोर एवं व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : किरण जी, आप सदन में यह बात बतायें कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उन जवानों को गलत तरीके से हटा दिया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको नियमित करने का आश्वासन दिया था, आप इस बात को इस महान सदन में स्वीकार करो। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : किरण चौधरी जी, आप सदन में यह बतायें कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने बहुत गलतियां की हैं। इन्होंने हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को हटाने की गलती भी की थी (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : विज साहब, पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था कि हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को नियमित करने का काम किया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं किरण चौधरी जी को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस बात को मान रही है और हम इन जवानों को नियमित करने के बारे में भी विचार करेंगे लेकिन आप इस बात को मानो कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में इनको हटाने की गलती की है और इनकी जिंदगी नर्क बना दी थी। पहले कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी ही हाउस में इस तरह से बात करेंगे तो यह हाउस की मर्यादा के खिलाफ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : किरण जी, आप पहले सदन में यह बतायें कि हुड्डा साहब ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत गलतियां की हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय मंत्री जी की बहुत गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, प्लीज, आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि प्रदेश के जब से विज साहब गृह मंत्री बने हैं तब से इनका चेहरा और मोहरा बदल गया है परन्तु किसी कारणवश इनको सी.आई.डी. विभाग नहीं मिला है। विज साहब, अगर मान लो मैंने इन जवानों को हटाने का काम किया था तो आपने उस समय इस महान सदन में आवाज क्यों नहीं उठाई? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : हुड्डा साहब, मैंने इसी हाउस में बहुत आवाज उठाई थी लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार में तानाशाही अधिक थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार किसी को बोलने ही कहां देती थी? अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब हरियाणा के सबसे बड़े तानाशाह थे। हुड्डा साहब, आपके शासन काल के दौरान मेरे बोलने से पहले ही मुझे इस महान सदन से बाहर करवा दिया जाता था। मैंने हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को हटाने की आवाज उठाई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बि□ान लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को सदन से माफी मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, सभी सदस्य बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी माननीय सदस्य सदन में बैठे हैं या किसी सिनेमा घर में बैठे हैं। प्लीज, सभी माननीय सदस्य बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, जिस समय की अनिज विज जी बात कर रहे हैं आप उस समय का रिकार्ड निकलवाकर देख लें। हमारी सरकार के समय में इनको हाउस में बोलने का पूरा मौका दिया गया था। दूसरी बात मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को सेवा से बाहर क्यों निकाला गया था यह इनको अच्छी तरह से मालूम है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने उस समय सवाल उठाया था। स्पीकर सर, जो हमारी सरकार से पहले वाली

सरकार थी उसने हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की भर्ती की थी। उस समय कोई टैक्नीकल फॉल्ट था जिस कारण हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की भर्ती की फाईनैंशियल एप्रूवल हुई ही नहीं थी। हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के पदों की विधिवत सैंक्शन भी नहीं हुई थी इसलिए उनको सेवा से हटाना पड़ा था। हमने तो विभिन्न पदों पर भर्तियां की थी और कभी किसी को हटाया नहीं था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, आपका यह व्यवहार हाउस की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हाउस के नेता अपनी बात कहने के लिए खड़े हैं लेकिन आप उनको भी अपनी बात नहीं कहने दे रही हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी बैठ जायें और सदन के नेता को अपनी बात कहने दें।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैंने जो कहा है वह ठीक कहा है। (शोर एवं व्यवधान) ये अपनी सरकार के समय में इस विषय पर एक–एक घंटे का भाषण देते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप भी कृपया करके बैठ जायें और सी.एम. साहब को अपनी बात कहने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सैनी साहब, आप बार–बार बिना किसी कारण के एक मिनट में खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप ऐसा करके बार–बार सदन की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अभी आप बैठ जायें और मुख्यमंत्री जी को अपनी बात कहने दें।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, जीरो ऑवर का मतलब यह नहीं होता कि माननीय सदस्यों द्वारा सदन की मर्यादाओं को ही तोड़ दिया जाये। जीरो ऑवर में भी सदन की मर्यादाओं का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगर विपक्ष के माननीय सदस्य जीरो ऑवर में भी राजनीतिक मुद्दों पर ही बोलेंगे तो उनका कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आ पायेगा। अभी विज साहब ने जो हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के विषय को उठाया है मैं भी उसी विषय को उठाना चाहता हूं। उस समय यह विषय था कि हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को सरकारी सेवा से निकाल दिया गया था। अध्यक्ष्य महोदय, इस बारे में उस समय जो ऑब्जैक्शंज थे वे ऑब्जैक्शंज तो आज भी हैं। उन ऑब्जैक्शंज को दरकिनार करते हुए हमने यह सोचकर कि उनके जीवन का गुजारा होता रहे और उनके

परिवार का भरण पोषण भी किसी न किसी प्रकार से चलता रहे उनको अस्थायी तौर पर सेवा में रखने का निर्णय लिया है। क्योंकि उन सभी को उस समय सरकारी सेवा में रखा गया था इसलिए उनको पक्का न करके कोई बीच का रास्ता निकाला गया अर्थात् हमने यह निर्णय लिया कि उनको पक्का न करके उनको एक–एक साल के लिए सेवा का विस्तार देकर सरकारी सेवा में रखा जाये। इस सबके पीछे हमारी यही कोशिश थी कि उनसे कोई न कोई काम भी लिया जाये और उनके परिवार का भरण पोषण भी होता रहे। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने वर्ष 2016 में एक प्रकार से रियायत करके उनको सरकारी सेवा में रखा। आज अगर उस विषय को राजनीति के तौर पर विपक्ष के माननीय साथियों द्वारा यहां पर उठाया जायेगा तो वह किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं होगा। अगर ये कुछ कहना भी चाहते हैं तो इनको यह कहना चाहिए कि यह केवल एक विषय है जिसका जवाब मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर देते समय दूंगा लेकिन इस विषय पर राजनीति करने के लिए सदन के समय के एक घंटे अर्थात् जीरो ऑवर का प्रयोग करें और एकतरफा बोलते चलें जायें जिस बोलने का कोई आधार न हो तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरा कांग्रेस के साथियों को यह कहना है कि इनको इस विषय पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इनकी हरियाणा में 10 साल सरकार रही है। इन्होंने कोई काम किया हो और हमने उसको बदला तो उस बात का उत्तर हमसे पूछा जाये। जब इन्होंने उस भर्ती की पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही नकार दिया था उसके बाद हमने उस भर्ती की प्रक्रिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा और हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के हित में निर्णय लिया तो आज हमारे ऊपर कांग्रेस के साथियों द्वारा सवाल उठाये जा रहे हैं कि हम इस दिशा में हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को सरकारी सेवा में पक्का करने की दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़े? मैं यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार के विषयों पर जीरो ऑवर में राजनीति किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जायेगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा इस सम्बन्ध में मेरा इनसे यह भी कहना है कि फिर ये सही बात भी बतायें कि टैक्नीकल फॉल्ट के कारण हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के जिन जवानों को निकाला गया था हमने उनको सुविधा दी। विभिन्न सरकारी भर्तियों में उनको आयु

की सीमा की विशेष छूट प्रदान की। उनमें से कम से कम 40 परसैंट जवान पुलिस में भर्ती हो गये थे। मुख्यमंत्री जी को हाउस में इसकी जानकारी भी देनी चाहिए। आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान करने के बाद भी कुछेक जवानों की उम्र ज्यादा हो गई थी इसलिए वे सरकारी सेवा में नहीं जा पाये। मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस अच्छे काम के बारे में भी सदन में जानकारी दें। इनकी भर्ती की सारी की सारी गलती को माननीय मुख्यमंत्री को हमारे ऊपर नहीं थोपना चाहिए। मैं यह बात पुनः कहना चाहूंगा कि हमने उन जवानों में से बहुत से जवानों को सरकारी सेवा में रखा भी था।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से हुड्डा साहब को यह कहना है कि उनसे हमारा कोई विरोध नहीं हो रहा है। इन्होंने जिन जवानों को सरकारी सेवा में रखा वह बहुत अच्छा किया लेकिन हमने तो जो बाकी रह गये थे उनके भी बेहतर भविष्य के लिए कारगर कदम उठाये हैं। इस प्रकार से यह विषय एक तरह से खत्म हो गया था लेकिन आज फिर इस विषय पर राजनीति करते हुए यह कहना कि उन जवानों को हमने पक्का क्यों नहीं किया? इस मामले में मेरा यही कहना है कि अगर उन जवानों को पक्का किया जा सकता था तो हुड्डा साहब भी उनको पक्का कर सकते थे। वे पक्का होने वाले नहीं थे इसलिए उन सभी को टैम्परेरी बेसिज पर लगाकर के आगे उनका जीवनयापन सही ढ़ंग से हो जाये हमने इसका कोई रास्ता निकाला। जो पक्का करने का रास्ता हुड्डा साहब के टाईम पर नहीं निकल पाया वह हमारी सरकार के समय में कैसे निकल सकता है? कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि आज इस विषय पर कांग्रेस के माननीय साथियों द्वारा महज थोथी राजनीति ही की जा रही है। मैं इनको बार–बार यही बताना चाहूंगा कि जब ये अपनी सरकार के 10 वर्ष के शासनकाल के दौरान उनको पक्का नहीं कर पाये तो यह कार्य हमारी सरकार के समय में कैसे सम्भव हो सकता है? प्रश्न यह है कि जो काम सम्भव ही नहीं है उसको राजनीति करने का मुद्दा बनाना कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को किसी भी सूरत में शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी द्वारा यहां पर आज यह विषय महज इसीलिए उठाया गया है कि वे लोग धरने पर बैठे हैं और उनकी एक डिमाण्ड चल रही है। ये यहां पर उनके हित में अपनी आवाज उठाकर महज एक खबर ही बनाना चाह रहे हैं ताकि ऐसा करके ये उनकी सहानुभूति प्राप्त कर सकें। मेरा इनको बार–बार यही कहना है कि अगर ऐसी बात थी तो इनको अपनी पार्टी के 10 वर्ष के शासन काल के दौरान

उनको पक्का कर देना चाहिए था। मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि इनको ऐसा करने से किस ने मना किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यगण, कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि राजनीति करने के उद्देश्य से मैंने इस विषय को यहां पर नहीं उठाया है। मैंने यह कहा कि आपने उनको सरकारी सेवा में रखा। उसके बाद वे लोग हमारे पास आये कि उनके सिर के ऊपर तलवार लटकी हुई है। I was putting in a positive manner. Unfortunately, Mr. Vij has to intervene on everything which is very very unfortunate. He twists the entire debate in a different scenario. मैं मुख्यमंत्री जी को यह बता रही हूं कि हमने पिछली सरकार के समय में भी यह बात उठाई थी। मुख्यमंत्री जी भी वहां पर थे और राम बिलास शर्मा जी भी वहीं पर थे। उस समय दोनों ने यह आश्वासन दिया था कि yes, we will take it positively. अब उनके सिर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको हटाया जाये। वे सभी गरीब घरों के बच्चे हैं। मेरा यही कहना है कि सरकार उनकी सरकारी सेवा को सुनिश्चित करने के लिए कोई न कोई कारगर कदम उठाये ताकि उनकी रोजी रोटी निर्बाध रूप से चल सके और हर साल उनके सिर के ऊपर वह तलवार न लटकी रहे। मैं सिर्फ इतनी सी बात ही कहना चाहती थी। इसके अलावा मेरी इस मामले में कोई दूसरी इंटैंशन नहीं थी। There was no different intention at all.

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की तरफ से एक नई कैटेगरी बनी है ई.डब्ल्यू.एस.। उस कैटेगरी के लिए महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों ने सरकारी सेवा में भर्ती के लिए आयु में 5 साल की छूट प्रदान की है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हरियाणा में भी इस कैटेगरी को सरकारी सेवा में भर्ती में आयु में 5 साल की छूट प्रदान की जाये ताकि उन लोगों को फायदा हो सके।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को यह कहना चाहूंगा कि पहले यह पता चल जाये कि महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों की तरफ से आयु में कितने से कितने तक की छूट प्रदान की है उनमें नौकरी किस आयु तक दी जाती है तथा छूट देकर कितनी आयु की गई है। हरियाणा में सामान्य वर्ग के लिए 42 साल की आयु की सीमा तो पहले ही रखी हुई है। अगर कोई

अनुसूचित जाति का आवेदक है तो उसको 5 साल की छूट देते हुए 47 साल तक आवेदन करने की छूट है। इसलिए पहले यह पता लगा लिया जाये कि कितनी से कितनी उम्र तक छूट दी गई है। यदि वहां पर 30 साल से 35 साल या 35 साल से 40 साल तक की ही छूट प्रदान की गई है तो उसका तो फायदा ही नहीं है क्योंकि यहां पर पहले ही 42 साल की उम्र तक आवेदन किया जा सकता है।

श्री रामकुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जो बच्चे पुलिस की भर्ती से ओवरऐज हो गये हैं और वे ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी के हैं तो उनको 5 साल की छूट दे दी जाये तो उनको फायदा हो सकता है। जिस प्रकार से एस.सीज. के कैंडीडेट्स को छूट दी जाती है उसी प्रकार से ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी के कैंडीडेट्स को भी आयु में 5 साल की छूट दे दी जाये।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसी पॉलिसी हो तो आप बता दीजिए।

श्री रामकुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। हम केरल में गये थे तो हमने देखा कि वहां भी संस्कृत और अंग्रेजी पर ही जोर दिया जाता है लेकिन हरियाणा में संस्कृत को बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। वर्ष 2009 के बाद संस्कृत टीचर का कोई भी पद विज्ञापित नहीं हुआ है। पहले संस्कृत के बदले वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या पंजाबी विषय का विकल्प रहता था लेकिन अब म्यूजिक वगैरह बहुत से विषय जोड़ दिये गये हैं जिससे संस्कृत भाषा कमजोर हो रही है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि संस्कृत भाषा को खत्म किया जा रहा है क्योंकि संस्कृत के अध्यापकों को हैडमास्टर के पद पर पदोन्नत भी नहीं किया जाता है। संस्कृत के लैक्चरर के पदों के लिए शायद वर्ष 2016 या 2017 में पद विज्ञापित हुए थे, मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन अब भी उनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। जिस समय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जाटों को हरियाणा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया था उस समय श्री विनोद शर्मा जी ने यह बात उठाई थी कि पंजाबी, ब्राहम्ण इत्यादि पांच जातियों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाये। उस बात को हुड्डा साहब मान गये और उन्होंने इन जातियों को भी आरक्षण का लाभ देकर ई.बी.पी.जी. (Economically Backward Person in General Caste) कैटेगरी बनाई थी। उसके बाद खट्टर साहब ने भी उसको

प्रोमोट किया लेकिन बाद में वह केस कोर्ट में चला गया और कोर्ट में सही तरीके से प्लीड नहीं किया गया। अब तो हालात यह हैं कि ए.जी. की तरफ से इस केस की पैरवी करने के लिए भी कोई नहीं जाता है। आज ई.बी.पी.जी. कैटेगरी के 200 बच्चे सड़क पर ऐसे ही घूम रहे हैं बाकी तो सभी ज्वाइन कर गये लेकिन इनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस केस की अच्छी तरह से पैरवी की जाए। इसमें कुछ भी नहीं है, सरकार की तरफ से सिर्फ एक ऐफिडेविट देना है। सुप्रीम कोर्ट में इनके साथ जो होगा वह देखा जायेगा, इसलिए इनको ज्वाइन करवाया जाये। इसके अलावा मैं एक बात और यह कहना चाहता हूं कि दूसरे कई राज्यों में भी 70 प्रतिशत से अधिक रिजर्वेशन है, तो फिर यहां हरियाणा में ऐसा करने में क्या दिक्कत है? इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि इस कानून को एक बार दोबारा से स्टडी करके अच्छी तरह से पास किया जाये तथा कोर्ट में भी अच्छी तरह से प्लीड किया जाये। जिन जातियों को चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में आरक्षण दिया गया था उन्हीं जातियों के लिए यह प्रावधान रखा जाये। नौकरियों में आज बहुत भारी अन्याय हो रहा है। इन जातियों में भी बहुत से लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं। उनको अगर रिजर्वेशन का फायदा हो जाये तो बहुत अच्छी बात है।

श्री भारत भूशण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो एक्साईज पॉलिसी बनाई है उसके बारे में हर रोज अखबारों में आता है कि अब मोहल्ले व घरों में लोग शराब के ठेके खोल लेंगे। वे इसका स्पष्टीकरण दें। उन्होंने इस पोलिसी में जो शराब रखने की मात्रा निर्धारित की है वह बड़ा अजीब सा लगता है। उसमें उन्होंने कहा है कि 'The possession limit for an individual is as indicated in the following table' आपने एक व्यक्ति को 6 बोतल कंट्री लिकर की, 6 बोतल दूसरी शराब की, इण्डियन फॉर्न लिकर की 12 बोतल, बियर की 12 बोतल, रम की 6 बोतल, वाईन की 12 बोतल, वोडका की 6 बोतल अलाउ की हैं यह बात तो समझ नहीं आई।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, बतरा जी ने जो मुद्दा उठाया है मैं तो यह उम्मीद कर रहा था कि ये इस मुद्दे पर कल बात रखेंगे। इस एक्साइज पोलिसी में मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं परमिट किया है।

श्री भारत भूशण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो उप–मुख्यमंत्री जी की ही बनाई हुई एक्साइज पोलिसी पढ़ रहा हूं।

श्री दुश्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बतरा जी जो ये एक व्यक्ति द्वारा शराब रखने की मात्रा पढ़ रहे हैं मैं उनसे बताना चाहता हूं कि माननीय हुड्डा जी जब वर्ष 2005 में एक्साइज विभाग संभालते थे तो उस समय उनकी सरकार में यह मात्रा लिखी गई थी। वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2020 तक यह मात्रा इसी तरह निर्धारित है और वर्ष 2020–2021 की पोलिसी के अन्दर भी यह मात्रा सेम है। आईदर ऑप्सन होता है कि जो–जो आपने चीजें पढ़ी हैं उनकी इतनी–इतनी मात्रा वह अपने घर में रख सकता है। आज हम हायर सोसाईटी के तौर पर लोगों को कह सकते हैं कि सभी अपने घर के अन्दर ये व्यवस्था बना सकते हैं। मैं आपको इसकी कलैरिफिकेशन दे देता हूं कि पहले इसके लिए कोई परमिट नहीं लिया जाता था।

श्री भारत भूशण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज की एक्साइज पोलिसी के बारे में अखबार व प्रैस आपकी आलोचना कर रहा है। अगर एक गांव के अन्दर कोई आदमी अपने घर के अन्दर शराब की ये सभी मात्रा रखेगा तो उसके घर के अन्दर ही शराब का ठेका खुल जाएगा फिर उसके घर से चाहे रात के 12 बजे शराब की बोतलें ले लो। ये जरूरी नहीं है कि जो पहले चलता आ रहा था और वह किसी ने नोटिस नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें सुधार ही न किया जाए।

श्री दुश्यंत चौटाला : बतरा जी, हमने तो उस पोलिसी को और ज्यादा सख्त किया है। अगर इस मात्रा से बाहर किसी के पास शराब पकड़ी जाती है तो पहले उसके लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। मैं सदन में स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस प्रदेश में शराब की तस्करी में दिन प्रतिदिन वृद्धि आई है। उस चीज को रोकने के लिए हमने इस एक्साइज पोलिसी में डिस्टलरी के ऊपर भी पाबन्दी लगाई है। अगर कोई डिस्टलरी इल्लीगल तरीके से शराब भेजती है तो उसको पहली बार में एक लाख रुपये जुर्माना, दूसरी बार में अढ़ाई लाख रुपये जुर्माना, तीसरी बार में पांच लाख रुपये जुर्माना और चौथी बार में उसका लाईसैंस कैंसिल किया जाएगा। उसके साथ–साथ अगर कोई आम आदमी अपने घर में कोई शादी–विवाह के लिए, किसी जन्मदिन के लिए या किसी सोशल फंग्शन के लिए परमिट लेना चाहता है पहले तो इन्सपैक्ट्री राज बहुत हावी था जिससे परमिट दिये नहीं जाते थे और रात

को उनके शादी–विवाह के फंग्शन पर जाकर पुलिस वाले खड़े हो जाते थे। आज हमने सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक के लिए ऑन लाईन परमिट अलोट करने का काम किया है। तीसरी चीज जो मैं इस पोलिसी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसी सदन के अन्दर हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले सप्ताह हम कानून में बदलाव लाने का काम करें। आपकी कांग्रेस की सरकार में कानून बना था कि अगर कोई इल्लीगल तरीके से शराब की तस्करी करता हुआ पकड़ा गया तो वह बेलेबल है और उसको 15 दिन के अन्दर बेल मिल जाती थी। अब हम उसमें उस ऑफेंस को 6 महीने तक नॉन बेलेबल किया जाएगा और प्रदेश के अन्दर जो इल्लीगल शराब की तस्करी होती है उसको पूरी तरह से प्रतिबन्धित किया जाएगा।

श्री भारत भूशण बतरा : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब ये है कि उप–मुख्यमंत्री जी इस पोलिसी को लगातार रखना चाहते हैं। इस पोलिसी से एक व्यक्ति के पास इतनी शराब होगी और उप मुख्यमंत्री जी उसको हटाना नहीं चाहते हैं। वह उनकी मर्जी है। हम तो खुश हैं कि आप इसी पोलिसी को रखें इससे तो नं. 2 की शराब और बिकेगी और उससे क्राईम बढ़ेगा। मैं तो उप मुख्यमंत्री जी से बस यही पूछना चाहता हूं कि वे इस पोलिसी को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते? नई एक्साईज पोलिसी के पेज नं. 45 पर क्लॉज–12 तथा 14 में है कि 'The possession for an individual…' This is a possessopm.

श्री दुश्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बतरा जी को बताना चाहता हूं कि यह श्रीमती किरण चौधरी जी की बनाई हुई वर्ष 2012–13 की पोलिसी है उसमें लिखा है कि 'The possession limit for an individual will be as indicated..' आई.एम.एफ.एल. 6 बोतल, आई.एम.एफ.एस 12 बोतल, बियर 12 बोतल, रम 6 बोतल, वाईन 12 बोतल, वोडका जिन 6 बोतल, देशी 6 बोतल । इस पोलिसी से एक शब्द भी नहीं बदला गया । इसके ऊपर सिर्फ फाईन ज्यादा किया गया है। अगर कोई बिना परमिट के अपने घर में शराब रखता है तो उसको कानूनी तौर पर सजा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हुड्डा साहब के समय में भी यही आबकारी नीति थी। उनको मैं बताना चाहूंगा कि उस समय जब कोई फंग्शन या गैदरिंग होती थी तो लिकर का जो स्टॉक घर में रखा जाता था उस पर 1500 रूपये की लाइसेंस फीस लगाई जाती थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पिछले फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के अंदर इस फीस

को बढ़ाकर 15000 रूपये करने का काम किया था। यह रिकॉर्ड की बात है और इसे सबको मानना ही पड़ेगा। अब सरकार ने इस लाइसेंस फीस को 10000 रूपये करने का काम किया है। (विघ्न)

श्री दुश्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सरकार लाइसेंस फीस भी न लें? अध्यक्ष महोदय, हमने तो लिकर पर फीस बढ़ाने का ही काम किया है। क्या यह गलत है?

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, फीस लो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है but why this possession of a huge quantity? This is my question.(interruption)

Shri Dushyant Chautala: Speaker Sir, who made this law? (interruption)

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, had it been previously continued**?** (interruption)

Shri Dushyant Chautala: Speaker Sir, it has been made by the Congress Government and we have only made it stringent. (interruption)

श्री भारत भूशण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं सीधी सी एक बात कहना चाहता हूँ यह जो कुछ हो रहा है यह प्रोहिबिशन के भी खिलाफ है तथा महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय उपमख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि आज के दिन शराब की जबरदस्त तस्करी हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है अतः मैं यह पूछना चाहती हूँ कि इस तस्करी को किस प्रकार से रोकने का काम यह सरकार करेगी? अध्यक्ष महोदय, डिस्टिलरीज वाले एक ट्रक का लाइसेंस लेते हैं और उसकी एवज में 5–10 ट्रक निकाल देते हैं। This is the way it is happening. मैं पूछना चाहती हूँ कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोकेंगे? इस प्रकार के कार्य करके डिस्टिलरीज वाले हजारों करोड़ों रूपये कमा रहे है and this is happening at the cost of the revenue of the State.

श्री दुश्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय किरण जी खुद एक्साइज एंड टैकसेशन मिनिस्टर रही हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वे एक बार मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। जब वह बोल रही थी तो I did not disturb her. माननीय सदस्या ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। पिछले 120 दिनों के अंदर प्रदेश में कितनी जगह छापेमारी हुई, कितने ट्रकों को हमने पकड़ा, कितने वेयरहाउसिज को हमने रेड किया, कितने सबवैंड्स को बंद करवाया है, अगर यह सब डाटा माननीय सदस्या को चाहिए तो मैं उनको उपलब्ध करवा दूंगा। जहां तक बात है तस्करी को रोकने की तो नई आबकारी नीति के तहत हमने तस्करी को रोकने के लिए दो कदम उठाये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, सारा फेक प्रोग्राम हो रहा है। आपका होलोग्राम वाला सिस्टम भी फेक साबित होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह होलोग्राम वाला सिस्टम भी स्वयं इनकी सरकार के समय में ही आया था।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी सरकार के समय होलोग्राम सिस्टम लाया गया था तो इसका सही तरीके से प्रयोग करने का काम भी सरकार को करना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्या को एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हमने नई आबकारी नीति के तहत तस्करी को रोकने के लिए दो कदम उठाये हैं। पहली चीज होलसेल और रिटेल तक को मॉनिटर करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस का फार्मूला अपनाया जायेगा। अब होलोग्राम की जगह क्यू.आर. कोडिंग के माध्यम से बोतल के डिस्टिलरी से निकलने तथा उसके आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने तक का सारा प्रोसेस ट्रेस किया जायेगा। हर वैंड पर पी.ओ.एस. सिस्टम लगाने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत अगर रसीद नहीं दी जायेगी तो पांच हजार रूपये का जुर्माना किया जायेगा और यही नहीं डिस्टिलरीज को मॉनिटर करने के लिए माननीय सदस्या को यह भी बताना चाहूंगा कि हमने अब यह निर्णय ले लिया है कि हरियाणा प्रदेश में आगे से डिस्टिलरी के नए लाइसेंस नहीं दिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को यह जानकर खुशी होगी कि माननीय सदस्या की सरकार जो लिकर के क्षेत्र में जो 42 लाख प्रूफ लीटर कैपेसिटी की क्षमता को

बनाकर गई थी हमने उस क्षमता के एक–एक ड्रॉप को मॉनिटर करने के लिए हर डिस्टिलरी पर फ्लो मीटर लगाने का भी काम किया है। जैसे ही ई.एन.ए. का एक ड्रॉप किसी डिस्टिलरी में बनेगा और उसको जैसे ही बोटल तक ले जाया जायेगा तो उसकी फ्लो को पूरे तौर पर मॉनिटर किया जायेगा और यही नहीं अगर मान लो इस सारे प्रोसेस की रिर्पोटिंग कोई नहीं करता है तो सी.सी.टी.वी. कैमराज को डिस्टिलरीज, वेयरहाउसिज तथा वैंड्ज में लगाने का प्रोविजन भी इस पॉलिसी में डाला गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि यह सब प्रावधान हमारे समय में भी होते थे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, सही बात तो यह है कि इन्हीं लोगों ने ही चोरों को रास्ते दे रखे थे लेकिन अब हमने उनको पकड़ने का काम करने जा रहे है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय,.....(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, सारी बात तो माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने बता दी है और उसके बावजूद भी आप उठकर बोलने लग जाती हैं। आप यह बतायें कि आप क्या विशेष बात पूछना चाह रही हैं?

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रही हूँ कि क्या डिस्टिलरीज मालिक एक ट्रक का लाइसेंस लेंगे और उसकी एवज में 5–10 ट्रक निकाल देंगे? इस तरह की घटनाओं को सरकार कैसे रोकेगी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यह जो आबकारी नीति आई है यदि इसको पुरानी पॉलिसी के हिसाब से देखें तो इन्होंने एक कदम आगे इस प्रकार से बढ़ने का काम किया है कि जैसे हमारे समय में पंचायत प्रस्ताव पास करती थी तो गांव में ठेका नहीं खुलता था, इन्होंने पंचायत के स्थान पर ग्राम सभा का प्रावधान शामिल कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, जैसाकि बताया गया है कि 600–700 गांव ऐसे हैं जहां पर ग्राम सभा या पंचायत ने ठेके खोलने के लिए मना कर दिया और वहां पर ठेके नहीं खुलेंगे लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने घरों में शराब का स्टॉक रखने के लाइसेंस देने की नीति बना दी। अगर यह बात लागू हो जाती है तो शराबबंदी की तरफ जो यह सरकार कदम बढ़ाना चाहती थी, क्या वह सार्थक

होगा? शराब का स्टॉक रखने के लाइसेंस देने की नीति लागू करके सरकार ने एक तरह से शराब तस्करी की दिशा में कदम बढ़ाने का ही काम किया है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि अगर शराब को लेकर इतनी अच्छी नीति सरकार ने बनाई है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बराला जी बार–बार इसको लेकर बयानबाजी क्यों करते हैं? सरकार को इस नीति के बारे में अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी समझाना चाहिए क्योंकि बराला जी कहते हैं कि इस नीति को बदलना पड़ेगा। कम से कम अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को तो इस नीति के संबंध में समझा लेना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब इस बात की चिंता न करें। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष को समझा लेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यदि प्रदेश अध्यक्ष को समझा लेंगे तो यदि कल के अखबार में उनका बयान आ जायेगा कि नीति ठीक है तो हम समझेंगे कि सरकार ने अपने नेता को समझा लिया है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो आज पता चला है मैं वही बात सदन को बता रहा हूँ। इस पोलिसी में लिखा है कि ये जो लिमिट्स हैं they were enhanced by the Congress Government in 2007-08. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007–08 के बाद पॉलिसी बनी है तो हमने उसमें कुछ न कुछ सुधार किया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस पार्टी के सारे काम देखकर करेंगे तो बहुत अच्छा राज करेंगे। सारी बातें अगर हमारी ही माननी है तो हमें ही सत्ता की कुर्सी पर बिठा दें।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब की सरकार ने न जाने कितन अच्छे काम किए हैं, जिन्हें जनता को भी नहीं पता है। अगर जनता को हुड्डा साहब के अच्छे कामों का पत चल जायेगा तो कांग्रेस पार्टी के नेता कहीं के भी नहीं रहेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से कहता हूँ कि हमें ही सत्ता की कुर्सी पर बिठा दें। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूँ कि सरकार की इस नीति के कारण गांवों में शराब की स्मगलिंग बढ़ेगी और प्रदेश के युवाओं के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। (विघ्न)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, मैं न तो शराब पीता हूँ और न ही पिलाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शराब पीने वालों से और पिलाने वालों से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने इस बारे में परमिट ले रखा है या नहीं ले रखा है (हंसी)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रदेश में शराब बंदी कर रखी थी। बाद में टूरिज्म वगैरह में शराब खोलने की परमीशन दी थी। उस समय कुछ विधायक भी कह रहे थे कि चौधरी साहब आप गलत खोल रहे हैं। इस पर चौधरी बंसी लाल ने कहा कि न तो मैं शराब पीता हूँ, न ही पिलाता हूँ और न ही सिगरेट पीता हूँ। उस समय चौधरी प्रताप सिंह दौलता विधायक हुआ करते थे उन्होंने चौधरी बंसी लाल जी से कहा कि आपको शराब पीने की क्या जरूरत है आप तो एम.एल.एज. का खून पीते हैं। वही काम श्री अनिल विज जी कर रहे हैं। (हंसी)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं तो शाकाहारी हूँ, इसलिए खून नहीं जूस पीता हूँ बल्कि खून तो हुड्डा साहब पीते हैं। (हंसी)

श्री मामन खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा मेवात पिछड़ा हुआ इलाका है। चाहे शिक्षा, पीने के पानी, रोजगार, किसानों की आय की आमदनी या किसानों की फसल की सिंचाई की बात हो, सभी क्षेत्रों में मेरा निर्वाचन क्षेत्र फिरोजपुर झिरका पिछड़ा हुआ है। मेरे फिरोजपुर झिरका में बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री के नाम से एक नहर जाती है। इसमें दो माइनर भी हैं एक माइनर शादीपुर माइनर है और दूसरी उमरा माइनर है।

श्री अध्यक्ष : मामन जी, जब आपको माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका मिलेगा तभी आप अपने हल्के की समस्याओं और डिमाण्ड्ज पर विस्तार से चर्चा कर लेना।

श्री मामन खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोलने के लिए सिर्फ दो मिनट का ही समय लूंगा। वर्ष 1982–83 में ये नहरें बनी थी लेकिन 20 साल तक इन नहरों में पानी नहीं आया। इन नहरों पर लगभग 34 गांव लगते हैं। इन नहरों पर वर्ष 1982–83 में तीन मोटर पम्प लगाए गए थे। आज 37 वर्षों के बाद इन पम्पों में खराबी आनी शुरू हो गई है कभी कुछ टूट जाता है कभी कुछ टूट जाता है। इतना बुरा हाल है कि हमारा इलाका पिछड़ा होने के बावजूद भी किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा है। इन नहरों के साथ–साथ एक कच्चा लंडवा

नाला और एक कच्ची कुमिटी आकेड़ा ड्रेन है, जब भी हमारे इलाके के लोग इनमें पानी देने की बात करते हैं तो सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि इन ड्रेनों में पानी नहीं दिया जाता है। पहले सरकार यू.पी. से 1000 क्यूसिक पानी लेती थी लेकिन अब वह घटकर 600 क्यूसिक हो गया है । इसमें से 280 क्यूसिक पानी राजस्थान को दिया जाता है और 130 क्यूसिक पानी बनारसी डिस्ट्रिब्यूट्री के लिए दिया जाता है । उसमें से भी घटाकर हमें सिर्फ 70–80 क्यूसिक पानी दिया जाता है जबकि कहा जाता है कि हमें 130 क्यूसिक पानी दिया जा रहा है । मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारे किसानों को पूरा पानी मिलना चाहिए, मोटर पम्प बदले जाने चाहिएं, केबल फुंकी हुई है उसको बदला जाना चाहिए । वहां पर लगे हुए पम्प 37 साल पुराने हैं और सरकार उनको अब भी चला रही है । अतः इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । धन्यवाद ।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ होगा ।

डॉ. कमल गुप्ता (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी इस अभिभाषण के लिए बधाई देता हूं जिन्होंने इसमें हरियाणा के 70 प्वायंट्स को रखवाया है और उनमें हरियाणा का विजन रखा है । उसमें पंडित दीन दयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावाद का दर्शन है । उसमें अत्योदय का वर्णन है जिसके माननीय मुख्य मंत्री महोदय भारतीय जनता पार्टी के संयोजक रहे हैं और उन्होंने समाज की अंतिम पंक्ति जैसे विकलांग, गरीब विधवा, असहाय का भी ध्यान रखने का विजन दिया है । उन्होंने उसमें हरियाणा के विकास का विजन दिया है । उन्होंने डिवैल्पिंग हरियाणा को डिवैल्प्ड हरियाणा में कंवर्ट करने का विजन दिया है । हरियाणा को संपूर्ण देश से सड़क, रेल, हवाई जहाज के माध्यम से कैसे जोड़ा जाए इसमें इसका विजन दिया है । ये सब विजन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस अभिभाषण में देने का प्रयास किया है । अगर गरीबों की बात करें तो गरीबों में 1.18 लाख लोगों को दीनदयाल आवासीय योजना के माध्यम से आवास देने का विजन दिया गया है । दूसरा, आयुष्मान योजना के तहत आम गरीब लोगों को हॉस्पिटल में 5 लाख रूपये तक की सहायता दी गई

है। इसमें गरीब वर्ग की कैसे सहायता की जाए, का विजन दिया गया है । श्रम योगी मानधन योजना के तहत 25–40 वर्ष तक के मजदूरों को 50–200 रूपये प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है । इसमें एक किस्त केन्द्र सरकार देगी और एक किस्त हरियाणा सरकार देगी । इसका लाभ लेने के लिए मजदूर को केवल पहली किस्त देनी होगी और जब वह 60 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी 3 हजार रूपये पैंशन बनेगी । सरकार ने यह एक बहुत ही सराहनीय काम किया है । आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शुद्ध एवं पौष्टिक आटा वितरण का काम, अनेक प्रकार के मजदूरों को 10 रूपये प्रति थाली भोजन देने का काम, ये गरीब लोगों की सहायता करने का काम है । इससे सरकार ने अभिभाषण में अपनी मंशा जाहिर की है । माननीय मुख्य मंत्री महोदय मुफ्त इलाज योजना के तहत 7 प्रकार की हैल्थ सर्विसेज को मुफ्त देने का इसमें वर्णन किया गया है । बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सरकार ने हरियाणा में सैक्स रेश्यो को सुधारकर 834 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों से 923 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों तक पहुंचा दिया है और इसके प्रति अपना विजन भी दिया है । सरकार ने व्यापारियों के लिए व्यापारी सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना की शुरूआत की है। व्यापारियों को जो बिजनेस में नुकसान होता है, उसका बीमा किया जाता है । इस प्रकार दोनों चीजों का बीमा किया जाता है। पहले व्यापारियों का इस प्रकार का कोई बीमा नहीं किया जाता था। इसका प्रिमीयम भी सरकार भरेगी। यह व्यापारियों के लिए बहुत ही सराहनीय काम है। दूसरा जो उनको जी.एस.टी. का रिफंड मिलता था, वह रिफंड तुरंत देने की बात की गयी है और वह उनके अकाउंट में सीधा जाएगा। इस प्रकार से व्यापारियों के लिए इतना बड़ा लाभ हमारी सरकार ने किया है। अगर विकास और कनैक्टिविटी की बात करूं तो 34,400 करोड़ रुपये की लागत से के.एम.पी. एक्सप्रैस वे की तर्ज पर पलवल से लेकर सोनीपत तक रोड बनाया जाएगा है। इसका विजन भी दे रखा है। इससे उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा की आपस में कनैक्टिविटी हो जाएगी। दिल्ली को बाईपास करके जिस तरह से के.एम.पी. एक्सप्रैस वे बनाया गया है, उसी तर्ज पर यह रोड बनाया जाएगा। इसके लिए 34,400 करोड़ रुपये के बजट की योजना है। दूसरा जीन्द से हांसी तक 60 किलोमीटर रेलवे लाईन बिछायी जाएगी और तीसरा करनाल से यमुनानगर तक 61 किलोमीटर रेल की लाईन बिछायी जाएगी। इसके साथ–साथ काले खां से करनाल तक का एलिवेटिड रेल लाईन बिछाने की योजना का विजन भी दिया गया है। यह

रेलवे लाईन 133 किलोमीटर बनायी जाएगी। इसके अलावा सड़कों का जाल बिछाया गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, उसमें चाहे दिल्ली से हिसार तक जाने की बात हो, चाहे हिसार से चण्डीगढ़ जाने की बात हो। इस बारे में पहले की सरकारों के समय की बात करें तो इन स्थानों तक पहुंचने में 5–6 घंटों का टाईम लगता था, परन्तु अब अढ़ाई घंटों में इन स्थानों पर पहुंच जाते हैं। अब वह कांग्रेस पाटी की सरकार नहीं है जो किसानों को 1 व 2 रुपये का चैक मुआवजे के तौर पर देती थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में किसानों को मुआवजा दिया जाता था तो **1–1** और 2–2 रुपये के चैक दिये जाते थे। हमारी सरकार ने किसानों को मिनिमम 500 रुपये का चैक दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में न तो सड़कों की कनैक्टिविटी थी, न रेलवे की कनैक्टिविटी थी और न ही एयर की कोई कनैक्टिविटी थी। ये लोग बताएं कि 50 साल में इसकी पार्टी की सरकार ने क्या किया ? मैं तो एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के समय में बहुत बड़े–बड़े प्रोजैक्ट बनाये गये थे, परन्तु उन पर किया कुछ नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज, कोई भी माननीय सदस्य बीच में टीका–टिप्पणी न करें।

डॉ0 कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के समय में बहुत बड़े–बड़े प्रोजैक्ट बनाये और पत्थर लगा दिये कि यहां से बम्बई जाने की सड़क बनायी जाएगी और यहां से कलकत्ता तक जाने की सड़क बनायी जाएगी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सड़क बनाती है तो विपक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि ये तो हमने शुरू की थी। कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी शुरू नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गोगी जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

डॉ0 कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इस तरह से पत्थर लगाने से कोई कार्य पूरा नहीं होता है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रोजैक्ट को बनाने की स्वीकृति लेने में टाईम लगता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या तो प्रत्येक दिन कई–कई मिनट बोलती हैं, एक–दो मिनट मुझे भी बोल लेने दें। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कह रहा हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कुछ नहीं किया और भारतीय जनता

पार्टी की सरकार कुछ करती है तो ये कहते हैं कि यह हमने सोचा था। सोचने से क्या होता है आपने किसी काम को पूरा तो नहीं किया ?

श्री शमशेर सिंह गोगी: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार की कनैक्टिविटी भी इनकी सरकार में ही शुरू हुई है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, शकुंतला जी आप बैठ जाएं।

डॉ0 कमल गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, कोयला घोटाला, पनडूब्बी घोटाला और 2जी, 3जी और 4जी घोटाले भी इनकी सरकार के समय में ही हुए थे। सी.एल.यू घोटाला भी इनकी सरकार के समय में ही हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी सरकार के समय में हुए घोटालों का जिक्र नहीं करना चाहता था, परन्तु अभी माननीय सदस्या ने खुद ही घोटाले की बात की है तो इसलिए मैं इनकी सरकार के समय में किये गये घोटालों की जानकारी दे रहा हूं। (विघ्न)

श्रीमती शकुंतला खटक: अध्यक्ष महोदय,..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शकुंतला जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय,.....(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के समय में एस.सीज./बी. सीज. कैटेगरी की स्कीम्ज के पैसों के घोटाले हुए हैं, उनकी जांच करवायी जाए।(विघ्न)

श्री जयवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने सफाई कर्मचारियों को 15,000 रुपये मासिक तनख्वाह देने की बात की थी, परन्तु अब उनको केवल 9,000 रुपये मासिक के हिसाब से दिये जा रहे हैं।

डॉ0 कमल गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार कहती थी कि वे किसानों के भले के ठेकेदार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनको बीच में डिस्टर्ब न करें। अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर दूसरे माननीय सदस्य भी बोलेंगे। इस प्रकार से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती।

डॉ0 कमल गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019–20 में जो हरियाणा सरकार ने सरसों की खरीद की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह बताएं कि ये कांग्रेस–कांग्रेस क्यों कह रहे हैं ? ये हमारी तरफ देखकर अपनी बात क्यों कह रहे

हैं ? माननीय सदस्य को चेयर को संबोधित करके बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं तो चेयर की तरफ देखकर बोल रहा हूं, परन्तु मेरी सीट का मुंह इनकी तरफ है जिसके कारण विपक्ष के माननीय सदस्यों को लगता है, उनकी तरफ देख रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मार्केटिंग सीजन वर्ष 2019–20 के दौरान 6 लाख 19 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई। इसके अलावा 13 हजार 156 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद भी की गई और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की पूरी राशि किसानों के खातों में सीधे जमा भी करवाई गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बि□ान लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से मानीय सदस्य को कुछ कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज बीच में डिस्टर्ब न करें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, फसल खरीद में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ''किसान पंजीकरण पोर्टल (मेरी फसल मेरा ब्यौरा) के माध्यम से 6 लाख 40 हजार से अधिक किसानों का पंजीकरण किया गया। अध्यक्ष महोदय, चालू वित्त वर्ष के दौरान 93 लाख 60 हजार मीट्रिक टन गेंहू की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई और 64 लाख 69 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। अब मैं ''भावांतर भरपाई योजना'' के बारे में बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी इन लोगों ने ''भावांतर भरपाई योजना'' हरियाणा प्रदेश में देखी थी। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के तहत पहले किसानों को 4 फसलों की खरीद पर लाभ दिया जाता था।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, प्लीज, आप वाईंड–अप कीजिए।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, अब हमारी सरकार ने 12 नई सब्जियों और तीन प्रकार के फलों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने भू–रिकॉर्ड को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने का काम किया है। इसके अलावा गांवों को ''लाल डोरा मुक्त'' करने का एक पायलट प्रोजैक्ट 25 दिसम्बर, 2019 को करनाल जिले के गांव सिरसी में शुरू किया गया है और लाल डोरा के भीतर स्थित भूमि और सम्पत्तियों की रजिस्ट्री करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने

2.20 लाख पशुओं का बीमा करने का काम भी किया है और साथ ही हमारी सरकार ने पशुओं में दूध की उपलब्धता को बढ़ाने का भी काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश में 1 लीटर 85 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति मिलता है जिससे पूरे देश में हरियाणा प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, प्लीज, आप वाईंड–अप कीजिए।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात जल्दी ही वाईंड–अप करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि न्यू आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग, स्टेट मैडीकल लैब और ऑन–लाइन ट्रांसफर की बातें तो बहुत करनी थी परन्तु अब मैं अपने हल्के से संबंधित कुछ बातें सदन में कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा बढ़ेगा तो पश्चिम हरियाणा बढ़ेगा, अगर पश्चिम हरियाणा बढ़ेगा तो पूरा हरियाणा बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि हिसार में ऐलिवेटिड रोड का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि हिसार का जो मेन बाजार है वहां पर काफी भीड़ लगी रहती है। हिसार जिले में 8 रेलवे क्रॉसिंग हैं इनको भी मुक्त करने का काम किया जाये और हिसार जिले में जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है उसको और तेजी से बढ़ाया जाये। अध्यक्ष महोदय, हिसार जिले में 17 किलोमीटर की पाइप लाइन है वह पूरी तरह से गल चुकी है क्योंकि वह पाइप लाइन पिछले 50 सालों से नहीं बदली है इसलिए इस पाइप लाइन को बदलने के लिए लगभग 23 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस काम को भी जल्दी से जल्दी करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, हिसार जिले की महावीर कालोनी में जो वाटर वर्क्स बना हुआ है उसकी रैनोवेशन पर 22 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा इसलिए उसकी भी रैनोवेशन जल्दी से जल्दी करवाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, हिसार को डिवैल्प करने के लिए हाई क्वालिटी की मैडीकल फैसिलिटी देने के लिए हिसार में 300–400 एकड़ में मैडीसिटी बनाने का काम करे। अध्यक्ष महोदय, रामधन फार्म में 1 हजार एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है, उस जमीन पर आई.एम.टी. बनाने का काम करें। इसके अलावा एक नया बस स्टैंड भी बनाया जाना चाहिए क्योंकि पुराना बस स्टैंड शहर के अंदर आ जाता है इसलिए मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि अन्य जगह पर नया बस स्टैंड का निर्माण करने का काम किया जाये। इस नये बस स्टैंड का जिक्र कल हाउस में मेरे क्वैश्चन ऑवर में

भी आया था। अध्यक्ष महोदय, हिसार जिले में एक नया अस्पताल भी बनाने का काम किया जाये। शमशान घाट में एल.पी.जी. का भी प्रावधान किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से प्रार्थना है कि हिसार जिले में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड बनाया जाये। हमने इसके लिए जमीन भी लोकेट कर रखी है। इसके अलावा मैं हाई क्वालिटी एजूकेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे हिसार जिले में 4 यूनिवर्सिटीज हैं और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उन यूनिवर्सिटज में से एक यूनिवर्सिटी को इन्टरनैशनल लैवल तक बनाया जाये ताकि विदेशों से भी लोग हमारे यहां पर आयें और वे लोग यहां पर रहें। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी सरकार यह सब विकास करेगी तो मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश फलेगा और फूलेगा। धन्यवाद।

श्री सोमवीर (दादरी) : माननीय अध्यक्ष जी, दादरी के अंदर मैंने पहले भी मैडीकल कालेज की स्थापना की मांग रखी थी। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि वहां पर आज की तारीख में केवल मात्र तीन ही डॉक्टर हैं। इस प्रकार से वहां पर डॉक्टर्ज की बहुत ही ज्यादा कमी है। इसको ध्यान में रखते हुए मेरी आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि दादरी में मैडीकल की सुविधा में ज्यादा से ज्यादा सुधार जल्दी से जल्दी किया जाये क्योंकि वहां पर दादरी जिले का क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत ज्यादा है और उसके हिसाब से सुविधा बहुत ही कम है। मेरी सरकार से बार–बार यही प्रार्थना है कि हमारी इस समस्या का समाधान किया जाये। धन्यवाद।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया सर्वप्रथम तो इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। सर, इससे पहले कि मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलना शुरू करूं मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे सदन के अंदर लगता है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सत्तापक्ष सपोर्ट नहीं करना चाहता। आप देखें कि सत्ता पक्ष के अधिकतर माननीय सदस्य हाउस से बाहर हैं। मंत्री परिषद् में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दो राज्य मंत्री ही सदन में उपस्थित हैं। यह कोई असूल नहीं है। जब यहां पर कोई माननीय सदस्य सरकार के विरोध में तथ्य प्रस्तुत करेगा तो उसका जवाब कौन देगा? (शोर एवं व्यवधान)

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : स्पीकर सर, बतरा साहब हर बार रूल्ज़ एण्ड प्रोसीजर की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि रूल्ज़ एण्ड प्रोसीजर के तहत हाउस का कोरम पूरा है। माननीय सदस्य एक बहुत ही प्रशिक्षित और वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिए सदन में इनको ऐसी बातें करके बिना वजह सदन का समय खराब नहीं करना चाहिएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आप बोलना शुरू करें।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मैंने सत्ता पक्ष की हाउस में उपस्थिति के सम्बन्ध में ऑब्जैक्शन किया है वह एक सीरियस ऑब्जैक्शन है। Speaker should direct that all the Ministers should be present in the House.

Mr. Speaker : Batra Ji, it is not mandatory in the Rules. You know very well.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सुशासन की बात की है। मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि इस समय सारे के सारे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। जब से हरियाणा बना तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जितना भ्रष्टाचार हुआ उतना कभी नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में भ्रष्टाचार ने सारे के सारे रिकार्ड तोड़ दिये हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में भ्रष्टाचार ने सारी सीमायें तोड़कर रख दी हैं। चाहें हम किसी भी फील्ड को उठाकर देख लें और किसी भी डिपार्टमैंट का रिकार्ड उठाकर देख लें सभी जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर मिलेगा। इसके बाद मैं प्रदेश में जो लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति है उसके ऊपर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रदेश के किसी भी वर्ग को कोई इंसाफ नहीं मिला है। सरकार के स्तर पर "बहुजन हिताये, बहुजन सुखाये" की बात की जाती है। हकीकत में ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में इस समय सरकार नाम की कोई भी चीज नहीं है। सबसे पहले तो मैं सबसे बड़े स्कैंडल की बात करना चाहूंगा। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी रोहतक में भिवानी स्टैण्ड के पास ओल्ड पुलिस स्टेशन में मल्टी लैवल पार्किंग का इनोग्रेशन

करके आये थे। उससे पहले वहीं पर उसी जगह पर ओल्ड पुलिस स्टेशन के अंदर वहां से थाना को दूसरी जगह शिफ्ट करके हुड्डा साहब के मुख्यमंत्रित्वकाल में कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान वहां पर पार्किंग और साथ में एक कांपलैक्स की घोषणा हुई थी। उस समय वहां पर लोगों ने इसका एतराज किया था। उस समय पब्लिक ने यह मांग उठाई थी कि उन्हें वहां पर मल्टी लैवल पार्किंग चाहिए। उस समय इस काम की 32 करोड़ रूपये में अलॉटमैंट हुई थी। लोगों के एतराज के बाद हुड्डा साहब ने फाईल पर यह ऑर्डर पास किया कि वहां पर मल्टी लैवल पार्किंग का निर्माण किया जायेगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया था लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी तो पी.पी.पी. मोड के अंदर उसी कांपलैक्स और उसी पार्किंग का उद्घाटन कर दिया और उसी का टैण्डर दे दिया। स्पीकर सर, मैं इस मामले को आपके सामने तथ्यों के साथ रखूंगा। पी.पी.पी. मोड के अंदर सबसे पहले तीन कम्पनियों का कंसोरियम बनाया गया। उनमें से एक कम्पनी है रिचा इण्डस्ट्रीज लिमिटिड है। यह कम्पनी 15.09.1993 को रजिस्टर्ड हुई। यह लिमिटिड कम्पनी है। उसके बाद रिचा कृष्णा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी 01.01.2019 को रजिस्टर्ड हुई। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि टैंडर की आखिरी तारीख 8 जनवरी, 2019 थी और कम्पनी का रजिस्ट्रेशन 01.01.2019 को करवाया गया। उसके बाद एक और कम्पनी का सहारा लिया गया जो वर्ष 2016 में रजिस्टर्ड हुई। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस मैटर है। 150 करोड़ रुपये की जमीन इस सरकार ने कितने रुपये में बेची इसकी भी इनवैस्टीगेशन होनी चाहिए। पी.पी.पी. मोड का जो टर्म एण्ड कंडीसन का डोकुमैंट था उसके अनुसार कम्पनी कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। उसके अनुसार न तो 01.01.2019 को रजिस्टर्ड कम्पनी उसमें कवर होती है और न ही वर्ष 2016 में रजिस्टर्ड कम्पनी इसमें कवर होती है। दूसरे नियम के अनुसार 31 मार्च, 2018 तक पिछले 5 वर्षों में सालाना टर्न ओवर 20 करोड़ होना जरूरी था तथा कम्पनी की नेट वर्थ 5 करोड़ होना जरूरी था। अध्यक्ष महोदय, बड़ा इंट्रस्टिड सवाल रहा कि रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड कम्पनी जो वर्ष 1993 में रजिस्टर्ड होती है, जिस दिन वो बिड में साथ में कंजोर्टियम बन कर जब पी.एस.वी. बनाते हैं उस समय वह कम्पनी दिवालिया के प्रोसैस में थी। न्यायधीश श्री आर.पी. नागरथ ने उस पर आई.आर.पी. (Interim Resolution Processor) नियुक्त कर दिया था। इसके बारे में यही कहा जाता है

कि कम्पनी के ऊपर एक बंदा बैठा दिया गया जो कम्पनी का सारा सिस्टम देखेगा। उसके बाद कम्पनी के डायरेक्टर की पॉवर समाप्त हो जाती हैं और कम्पनी कुछ नहीं कर सकती है, कम्पनी कोई रेजोल्यूशन पास भी नहीं कर सकती है। जो कुछ भी करेगा आई.आर.पी. करेगा। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने उस कम्पनी को बिड में शामिल होने के लिए कैसे अलाऊ कर दिया? उसके बाद जो कम्पनी 01.01.2019 को बनी उसी कम्पनी को फ्रंट करके रिचा कृष्णा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी और आई.एन.डी. सेनेटरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी ने 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत की पार्टनरशिप कर ली। कहां गई वह 5 साल की कंडीशन, किस बात की प्रजातंत्र और पारदर्शिता की बात सरकार करती है? अध्यक्ष महोदय, इससे भी गम्भीर बात यह है कि जिस रिचा कृष्णा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को आगे करके टैंडर दिया गया उसकी कैपिटल वैल्यू सिर्फ 1 लाख रुपये और अधिकृत पूंजी केवल 10 लाख रुपये है। इस समय यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोपोजल को फाइल पर एप्रूव किया है। उसके बाद क्या हुआ कि इस सारी प्रोप्रटी को जो कि लगभग 2400 मीटर जगह है, 99 साल के लिए पी.पी.पी. मोड पर लीज पर दे दिया गया। अध्यक्ष महोदय, उप–मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या सरकार 99 साल की लीज की प्रोप्रटी बिना कैबिनेट की मंजूरी के दे सकती है? सरकारी प्रोप्रटी आप पी.पी.पी. मोड पर एक कम्पनी को जो वहां पर मल्टी लेवल पार्किंग और कमर्शियल कॉम्पलैक्स बना रही है, उसको 99 साल की लीज क्या कोई एच.ओ.डी. दे सकता है? मेरे मुताबिक तो मुख्यमंत्री भी नहीं दे सकता जब तक कैबिनेट उसको एप्रूव न कर दे। यह जमीन सरकार ने केवल 2 करोड़ रुपये अप फ्रंट प्रिमीयम जिसको हम पगड़ी कहते हैं, के भुगतान के साथ 2 लाख 24 हजार 112 रुपये सालाना किराए पर दे दी। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर 1300 गज कमर्शियल उस कम्पनी को अलाऊ कर दिया।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आप वाइंड अप कीजिए।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, अभी तो यह पहला सकैंडल आया है। अभी तो और भी बहुत से स्कैंडल्स के बारे में मैं बताने वाला हूं और आप अभी से कह रहे हैं कि वाइंड अप कीजिए।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आपकी पार्टी की तरफ से बोलने वाले और भी सदस्यों की लिस्ट दी गई है जिनको 6–6 मिनट बोलना है। अगर बतरा जी और अधिक समय लेंगे तो आपकी पार्टी का ही टाईम कंज्यूम करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप इनको टाईम दे दीजिए, हम बाकियों के नाम वापिस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, इनको कितना समय और बोलने दें? आखिर कोई समय लिमिट तो होगी।

श्री भारत भूशण बतरा : अध्यक्ष महोदय, समय की लिमिट क्या बतानी है। यह सरकार अपवादों से भरी सरकार है और आप मुझे बोलने का समय नहीं देना चाहते।

श्री अध्यक्ष : बाद में आपके बाकी सदस्य यह न कहें कि हमें टाईम नहीं मिला। आपका समय बतरा जी ले रहे हैं।

श्री भारत भूशण बतरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने रिकॉर्ड के मुताबिक जो कहा है उसको मैं सभी को संक्षेप में बता दूंगा। इसमें सरकार ने कहा कि इस पर 17 करोड़ रुपये लागत आएगी। इसमें 2 करोड़ रुपये तो अप फ्रंट प्रिमियम हो गया और 2 करोड़ रुपये किराया बनता है यानि यह प्रोपर्टी 21 करोड़ में आ गई जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपया है अर्थात जिसकी कीमत वहां 14 लाख रुपये गज है। चाहे आप वहां आज जाकर सर्वे करवा लें कि वहां पर जमीन की कितनी कीमत है? वहां 150 करोड़ रुपये की प्रोपर्टी में लोगों को पार्किंग के लिए 65 कार और 250 टू व्हीलर खड़े करने की इजाजत मिलेगी जोकि सरकार का यह सबसे बड़ा घपला है। इसी के साथ सबसे बड़ी जरूरी बात एक और है जो देखने लायक है। उप मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं। सरकार ने वहां पर डिप्टी कमिशनर या जो भी कॉरपोरेशन का आदमी होगा उसने इसकी 70 हजार रुपया प्राईम और 25 हजार रुपया नॉन प्राईम कीमत असैस की है। कम से कम वहां पर जमीन की जो रजिस्ट्रियां होती हैं उतनी कीमत तो उस जमीन की होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने रोहतक में भिवानी स्टैंड देखा होगा वह प्राईम स्पॉट है और वहां पर इतना बड़ा घपला हुआ है। इसकी अब स्पीकर साहब इंकवायरी करवाएंगे या सरकार से इसकी रिपोर्ट मांगेंगे, क्या कार्यवाही करेंगे क्योंकि यहां कोई जवाब देने वाला तो बैठा नहीं है पर जब मुख्यमंत्री जी अभिभाषण पर बोलेंगे तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वे इस बात का जवाब जरूर दें। इसके बाद है शुगर मिल घोटाला। पानीपत के

शुगर मिल की क्षमता को 1800 टन से बढ़ाकर 5000 टन तक कर दिया गया है और करनाल की शुगर मिल की क्षमता को 2200 टन से बढ़ाकर 3500 टन कर दिया गया है। आपने पानीपत के शुगर मिल की क्षमता को 5000 टन बढ़ा दिया है जबकि पानीपत में रोजाना 5000 टन के हिसाब से गन्ने की पिराई के लिए अगले 10 साल में गन्ना पैदा नहीं हो सकता है लेकिन इन्होंने उस शुगर मिल की क्षमता को बढ़ा दिया है।

श्री महिपाल ढ़ांडाः अध्यक्ष महोदय, बतरा जी को पता ही नहीं है कि पानीपत में गन्ना कितना है।

श्री भारत भूशण बतरा : अध्यक्ष महोदय, जब इंकवायरी की बात आई तो पानीपत शुगर मिल का चेयरमैन इस बात के लिए रिजाईन कर गया है।

श्री महिपाल ढ़ांडा : अध्यक्ष महोदय, हमारे पानीपत का किसान आज भी अपने गन्ने को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व पातड़ा तक लेकर जाता है। बतरा जी, आपको ये आंकड़ा किसने बनाकर दे दिया है? आप यहां पर तुगलकी बात पढ़ रहे हैं। क्या आप किसानों के हितेषी हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री हरविन्द्र कल्याण : अध्यक्ष महोदय, करनाल के शुगर मिल की 30 साल पुरानी क्षमता चली हुई है और वहां का गन्ना इतना एक्सैस में है।

श्री भारत भूशण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पानीपत शुगर मिल की बात की है और ये करनाल में पहुंच गये। मैंने पानीपत शुगर मिल की क्षमता को 5000 टन बढ़ाने के बारे में बात कही है। आपकी करनाल के शुगर मिल की क्षमता तो 3500 टन हुई है। आप पानीपत के अन्दर 5000 टन गन्ना दिखा दें।

श्री महिपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, आप इसकी रिपोर्ट मंगवाईये।

श्री भारत भूशण बतरा : अध्यक्ष महोदय, जो पैसे खाने वाले थे वह पैसे खा गये हैं लेकिन इनके पल्ले कुछ नहीं आया। सीधी सी बात तो यही है।

श्री महिपाल ढांडा : बतरा जी अगर आपने वैसे कुछ बोलना है तो बोल लीजिए।

श्री भारत भूशण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों पर आधारित बोलता हूं। ये तो इस समय हमारे मंत्री डॉ. साहब बैठे हैं जो बहुत ही शरीफ व ईमानदार मंत्री हैं वे इस बात की पूरी जानकारी करवाएंगे। उसके बाद सब कुछ पता लगेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि नैशनल डिवैल्पमैंट कोरपोरेशन ने 14 बड़ी–बड़ी फैक्ट्रियों को इजाजत दी है कि आप शुगर मिल इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें टर्मज एण्ड कंडीशंज लगाई गई जिसमें तीन कम्पनियां क्वालिफाई कर गई हैं। जो

नैशनल फैडरेशन है वह इस बात के लिए किसी हालत में भी गलत रिक्मैंडेशन नहीं करती है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी और आखिरी बात है वह मैं बताना चाहता हूं इसके अन्दर मुद्दे तो और भी बहुत ज्यादा हैं लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि टर्मज एण्ड कंडीशन के मुताबिक सबसे पहले जो एक्साइज और जी.एस.टी. लगेगा वह मशीन इंस्टोल करने वाले पर लगेगा और वही बियर करेगा उसमें सरकार बियर नहीं करेगी लेकिन इसमें रिकॉर्ड के मुताबिक सरकार ने बीयर किया हुआ है। इस तरह से 18 प्रतिशत और 7 प्रतिशत यानी टोटल 25 प्रतिशत अर्थात 700 कुछ करोड़ रुपये का घोटाला तो यहीं पर खड़ा हो गया है। सरकार इस बात के लिए क्या जस्टिफाई करेंगी? अध्यक्ष महोदय, निविदाओं व कांट्रैक्ट को अगर आप पढ़ेगे तो इसमें वह सारी चीजें मिल जायेंगी

13:00 बजे

जो मैं सदन में बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, अर्बन लोकल बाडीज के अधीन 'अमरूत' नाम की एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रदेश को 2565 करोड़ रूपये दिये थे लेकिन जिस काम को पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को करना चाहिए था उस काम को अर्बन लोकल बाडी ने करवाया। अध्यक्ष महोदय, यह सबसे बड़ी ऑब्जैक्शन की बात है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस संबंध में आगे बताता हूँ। हमारे प्रदेश में एक हाई पावर्ड परचेज कमेटी है जिसमें सभी बड़ी बड़ी कंपनियां चाहे वह सुप्रीम है, जिंदल है या और कोई कंपनी है, अपने अपने टैंडर लगाती हैं और हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी इन सभी बड़ी–बड़ी कंपनियों से प्राप्त सारे टैंडर्ज को देखती है और रेट फिक्स वगैरह होने के बाद कांट्रैक्ट वगैरह होता है उसके पश्चात संबंधित डिपार्टमैंट्स को इंस्ट्रक्शंज जारी होती है कि फलां जगह से सारी पाइपें खरीदी जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, जब एक बार डी.आई. पाईप्स के रेट्स मुकर्रर हो गए तो बावजूद इसके जब डी.आई. पाइप खरीदने के लिए ठेकेदार को लैटर दिया गया तो उसमें रेट को 25 प्रतिशत बढ़ा दिया गया। इसी प्रकार सीवरेज के कांट्रैक्ट को भी नैगेशियेशन में 30 परसेंट अबोव कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह कहां का इंसाफ है? (विघ्न)

पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री (श्री अनूप धानक): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि वे कौन से कांट्रैक्ट में 30 परसेंट अबोव की बात कर रहे हैं? मैं यह बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी हाई पावर्ड परचेज कमेटी का एक सदस्य हूँ।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो बात मैं बता रहा हूँ यह इनके मंत्रालय से संबंधित नहीं है। मैं वर्ष 2018–19 की हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बात कह रहा हूँ। इस सरकार को बने हुए जुमा–जुमा तीन–चार महीने ही हुए हैं। अभी तक तो इस सरकार की हाई पावर्ड परचेज कमेटी की कोई बैठक तक नहीं हुई है। अतः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को मुझे अपनी बात रखने देनी चाहिए।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपने आपको ज्यादा पढ़ा–लिखा समझते हैं। उन्हें किसी मंत्री के साथ बात करने को लहजा पता होना चाहिए और जहां तक उन्होंने कहा कि सरकार को जुमा–जुमा तीन–चार महीने बने हुए हैं और ऐसे में हाई पावर्ड परचेज कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि नई सरकार की हाई पावर्ड परचेज कमेटी की अब तक दो मीटिग्ज आलरेडी हो चुकी हैं। (विघ्न)

श्री अनूप धानकः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बतायें तो सहीं कि डी.आई. पाईप्स के क्या रेट्स मुकर्रर हुए थे? (शोर एवं व्यवधान) क्या माननीय सदस्य इन सभी बातों से जुड़े कागजातों को पेश कर सकते हैं?(शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में वर्क आर्डर की बात कर रहा हूँ। अगर सत्ता पक्ष के लोग इस तरह काउंटर करेंगे तो मेरे लिए सारी बात कहना मुश्किल हो जायेगा लेकिन जहां तक बात कागजात को पेश करने की है तो यदि अध्यक्ष महोदय आप मुझे समय दें तो इन कागजातों को मैं आपके समक्ष भी प्रस्तुत कर सकता हूँ । मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो डी.आई. पाईप्स के रेट्स हाई पावर्ड परचेज कमेटी ने मुकर्रर किए थे उसके अबोव बाद में जो रेट संबंधी आर्डर हुए वह सभी कागजात मेरे पास हैं जिसमें लगभग 18 परसेंट फालतू रेट पर आर्डर दिया गया। मैं इन सभी कागजात को कभी भी स्पीकर साहब की टेबल तक पहुंचा सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सीवरेज पाइप के लिए जो हाई पावर्ड परचेज कमेटी ने रेट फिक्स किया था उसके रेट भी तयशुदा रेट से ज्यादा करने का काम करके सैंट्रल गवर्नमैंट से प्राप्त पैसे का मिसयूज किया गया था। मेरा निवेदन है कि इन सबकी इंक्वॉयरी जरूर होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक दूसरे विषय पर आता हूँ। वर्ष 2015–16 में 29 करोड़ 74 लाख रूपये खर्च करके पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट द्वारा एक कंपनी के माध्यम से 40 एम.एल.डी. क्षमता

का एक सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट डॉ. कमल गुप्ता जी के शहर हिसार में लगाया गया था। इसके पश्चात इसी कंपनी को करनाल के अंदर 50 एम.एल.डी. क्षमता का सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाने का ठेका दिया गया। इस कार्य पर 72 करोड़ रूपया खर्च हुआ। अध्यक्ष महोदय, कहां पहले 29 करोड़ 74 लाख रूपये का काम दिया गया और बाद में इसी कंपनी को 72 करोड़ रूपये का का दे दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह सब रिकॉर्ड के आधार पर बात बता रहा हूँ। अब मैं शीरे के विषय पर अपनी बात रखता हूँ। शुगर मिल में शीरा बनता है। सरकार के पिछले पांच साल के कार्यकाल में शुगर मिल में शीरे के संबंध में भी बहुत बड़े–बड़े घोटाले हुए हैं और उन घोटाले के अंदर एक मर्यादा यह भी कहती है कि जो व्यक्ति जिस विभाग का मंत्री हो तो उसे उस विभाग में कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। यह बात ठीक है कि हर आदमी को अपना कारोबार करने का हक है। लेकिन जिस विभाग का मंत्री हो उस विभाग में उसको बिजनेस नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से इस बात को जरूर उनसे पूछन चाहूगां कि जिस व्यक्ति के बारे में पहले से पता था कि उसका शीरे का बहुत बड़ा व्यापार है तो उसको अपने मंत्रिमण्डल में सहकारिता मंत्री क्यों बनाया गया? जिस चीज का माननीय पूर्व मंत्री जी बिजनेस करता है उसी विभाग का मंत्री बना दिया गया और उसके बाद बड़े–बड़े घोटाले उजागर हुए। 80 हजार टन का घोटाला पानीपत शुगर मिल में शीरे का हुआ है पता ही नहीं चला कि इतनी मात्रा में शीरा कहां चला गया? जमींदारों को कैसे लूटा गया इस बात का खुलासा कैथल में धर्म कांटे में लगी चिप से साबित हो गया था। इस संबंध में किसानों की तरफ से एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी लेकिन बाद में इन्क्वॉयरी हुई या नहीं हुई इस बात का भी पता नहीं। इस मामले में किसानों का नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस समय उप मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं और उनका सारा खानदान किसानों का मसीहा होने की बात करता रहा है क्या वे इस बात की इन्क्वॉयरी करवायेंगे? अध्यक्ष महोदय, शीरे को लेकर एक माफिया बन गया है। पिछले 4 साल के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश में 200 रुपये टन के हिसाब से ज्यादा शीरा नहीं बेचा गया। जनवरी, 2020 में शीरे 811 रुपये प्रति टन के हिसाब से बिका है। यह रिकॉर्ड की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं रिकॉर्ड की बात सदन में कह रहा हूँ । आप देखेंगे कि दिनांक 25.04.2018 को शीरे का भाव 161 रुपये प्रति टन

था और दिनांक 25.04.2018 को ही 185 रुपये प्रति टन हो गया था। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद रोहतक के हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी की फर्म को ठेका दिया गया था। इस फर्म को 32 लाख टन शीरा उठाने का 167 रुपये प्रति टन के हिसाब से ठेका दिया गया था। फिर उसी फर्म को 1.20 लाख टन का टैंडर 216 रुपये प्रति टन के हिसाब से दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, फिर उसके बाद उसी फर्म को 1.20 लाख टन का टैंडर 456 रुपये प्रति टन के हिसाब से दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, टर्म एण्ड कंडीशन के मुताबिक देखेंगे कि इस फर्म को सब जगह 90 दिन के अंदर और दिनांक 22.02.2019 को टैंडर अलॉट हुआ और 165 दिन में शीरा उठाने की मोहलत दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, दूसरा टैंडर 5 महीने से पहले या 5 महीने के बीच में आ गया और उसकी कीमत 651 रुपये प्रति टन के हिसाब से तय की गई। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के घोटाले उजागर हुए हैं। जिस माल को उठाने के लिए साढ़े पांच महीने की जगह 60 दिन देते तो सरकार को फायदा होता और वह माल नहीं उठता तो सरकार को ज्यादा फायदा होता। क्या उनकी सरकार होने का माननीय पूर्व मंत्री ने यही फायदा उठाया कि किसानों को नुकसान पहुँचाया? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उसके बाद चुनाव आ गए। चुनाव के बाद शुगर मिलों के लिए मामला बढ़िया हो गया। उसके बाद 575 रुपये प्रति टन के हिसाब से नया रेट आ गया। अध्यक्ष महोदय, आखिरी टैंडर 70 हजार टन 811 रुपये प्रति टन के हिसाब से तय हुआ है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय कल माननीय सदस्यों से बड़ी अच्छी बात पूछ रहे थे कि आप बताइये कि सरकार का रिवैन्यू कैसे बढ़े ? मेरा कहना है कि सरकार का रिवैन्यू लूटा दिया गया है । अगर सरकार घाटे में रहेगी तो चलेगी कैसे ? यह आत्मा की आवाज है कि जो व्यक्ति सरकार का, किसान का, पब्लिक का पैसा खाता है उसको भगवान भी माफ नहीं करता । किसी को भी किसानों का, आम लोगों का पैसा नहीं खाना चाहिए । जो ऐसा करेगा भगवान उसका नाश कर देगा ।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आप कन्क्लूड कीजिए ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, ऑफैंस 2 तरह के होते हैं – पहला पर्सनल क्राइम और दूसरा, क्राइम अगेंस्ट पब्लिक । मर्डर, डावरी, डैथ आदि पर्सनल क्राइम होते हैं और फिरौती मांगना, रोडरेज करना, लूट–खसौट आदि क्राइम अगेंस्ट पब्लिक में आते

हैं। अगर क्राइम अगेंस्ट पब्लिक बढ़ता है तो यह सरकार का फेल्योर दर्शाता है । मेरे प्रश्न के जवाब में सरकार ने विधान सभा में क्राइम अगेंस्ट पब्लिक का डाटा दिया था । उस डाटा के अनुसार पिछले 5 सालों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है । अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि इसकी इंकवायरी करवाएं और वह इंकवायरी भी not less than the rank of I.G.P. होनी चाहिए । सरकार को ऐसे मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज करवानी चाहिए । अगर एफ.आई.आर. झूठी साबित होती है तो वह इनवेस्टिगेशन के बाद खत्म हो जाएगी । वह इंकवायरी not less than the rank of I.G.P. से होनी चाहिए । इसमें भ्रष्टाचार और क्राइम हुआ है । अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इसकी टाइम बाउंड इंकवायरी करवाई जानी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री असीम गोयल (अम्बाला भाहर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मुझसे पहले कई माननीय साथियों ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने–अपने विचार रखे हैं । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, पहले की सरकारें जिस प्रकार से दीन–ए–इलाही के सिस्टम से चलती थी । उस समय कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता था और उस समय क्षेत्रवाद, जातिवाद के नाते से सरकारें चलती थी लेकिन अब जन–जन की भावना को आगे रखकर जनता की आवाज को प्रमुखता से उठाया जा रहा है फिर चाहे विकास की बात हो या फिर क्षेत्रवाद को खत्म करने की बात हो या फिर भाई–भतीजावाद को खत्म करने की बात हो । हमारी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय के माध्यम से इन सब मामलों में एक नई मिसाल पैदा की है । **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सबसे पहले कृषि की बात करूंगा । आज हमारे सामने उन्नत बीजों का एक अति महत्वपूर्ण विषय है । पुराने समय में हम पढ़ते थे और बुजूर्ग भी कहते थे कि जो बोओगे, वही पाओगे। हमारी सरकार उन्नत बीजों के माध्यम से किसान भाईयों को जागरूक करने के लिए लगी हुई है कि आप अपनी फसल के समय अपने खेत में उन्नत बीजों का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त एफ.पी.ओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाईजेशन) को बढ़ाने की बात की गयी

है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की तर्ज पर हमारी सरकार ने इन एफ.पी.ओज. को आगे बढ़ाने का काम किया है ताकि बिजाई के समय किसान भाई को पता चल सके कि किस समय पर बिजाई की जाए। फसलों के पालन पोषण के लिए किस चीज की आवश्यकता है, खेत की ऊपजाउ ताकत बढ़ाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है और मंडियों में उनकी फसलों का सही दाम उन्हें मिल सके। एफ.पी.ओज. के माध्यम से आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों ने नयी मिसालें कायम की हैं। हमारी सरकार भी वर्ष 2020 तक 1,000 ऐसे एफ.पी.ओज. खोलेगी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं परसों एफ.पी.ओ. के एक कार्यक्रम में गया था। उन्होंने नॉर्दन प्रोड्यूसर फार्मर्ज ऑर्गेनाईजेशन के नाम से एक ब्रान्ड रजिस्टर्ड किया है। उन्होंने एक नयी टैक्नीक के माध्यम से वहां लगभग पूरे हरियाणा से चाहे मशीनरी की एग्जिबिशन की हो, चाहे उन्नत बीजों की बात हो। चाहे रासायनिक खाद को कम करके जैविक खेती को बढ़ाने की बात हो। उन्होंने जिस प्रकार की एग्जीबिशन लगवायी है, वह प्रंशासनीय कदम है। हम अपने स्वास्थ्य के प्रति तो बहुत गम्भीर होते हैं और हम अपने शरीर के लिए मल्टी विटामीन लेते हैं, लेकिन हम रासायनिक खाद और पेस्टिसाईड्स के माध्यम से अपनी इस धरती को बीमार करने के लिए लगे हुए हैं। अधिक उपज के चक्कर में हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके धरती को बीमार कर रहे हैं। उसकी पैदावार खाकर हम खुद भी बीमार हो रहे हैं और गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार की योजनाएं हैं। इसके लिए मैं आदरणीय माननीय मुख्य मंत्री जी और पूरी सरकार का धन्यवाद करता हूं और हम विरासत के तौर पर अपने बच्चों के लिए उन्नत जमीन छोड़ें ताकि वे अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। हम अपनी उपज को बढ़ाने के लिए जमीन को जहरीली कर रहे हैं। अगर पराली अवशेष प्रबन्धन की बात करें तो हमारे बुजूर्ग कहते थे कि यह धरती नहीं है, बल्कि हमारी मां है। इसलिए पराली जलाना अपनी मां की कोख में आग लगाने के समान है। हमारी सरकार किसानों को नये–नये उपाय बताकर जागरूक करने के लिए लगी हुई है। आदरणीय राज्यपाल महोदय जी ने अपने अभिभाषण में जलशक्ति अभियान का जिक्र किया है। निश्चित रूप से अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन पानी का अन्धाधुंध दोहन और पानी का अन्धाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी सरकार ने पानी के संचयन और संरक्षण के लिए नयी–नयी नीतियां बनायी हैं। हर घर नल

से जल और अटल भू जल योजना, जो भारत सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये से चलायी हैं, जिसमें 7 राज्यों को लिया गया है। यह हमारे लिए गर्व और हर्ष की बात है कि इन 7 राज्यों में हरियाणा राज्य को भी शामिल किया गया है। फ्लड इरीगेशन की बजाए सप्रिकंलर और ड्रीप इरीगेशन की विधि को बढ़ावा देना, फसलों के चक्रीकरण को बढ़ावा देना, ये हमारी सरकार की अन्य ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जो किसान भाईयों और उन्नत बनाने में सहयोग करेंगी। सर, आदरणीय वन मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। एक ऐसी अदभूत योजना चलायी है जिसमें हम कहते हैं कि पेड़ हो रहे हैं कम, सांसे हो रही है कम, आओ पेड़ लगाये हम। हम पंचायती जमीन पर सफेदे और पॉपलर लगाकर हर 3–4 साल के बाद उनको काटने का काम करते हैं। पहली बार सरकार ने कहा कि हम पंचायती जमीन पर फलों के बाग लगाएंगे। जिससे पर्यावरण में कार्बन की मात्रा को घटाने के सहयोग मिलेगा और इससे संबंधित पंचायतों को एक निश्चित इन्कम होगी। लगभग 30–40–50 साल तक वे फलों के पेड़ जमीन पर रहेंगे जिससे पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा धन बेटी, जल और वन हैं। अध्यक्ष महोदय, हम पहले जमाने में रोटी, कपड़ा और मकान तक की ही बात करते थे लेकिन आज हम इसके अलावा स्वास्थ्य, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी और हैल्थ एजूकेशन की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा स्वास्थ्य, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी और हैल्थ एजूकेशन तीनों फैक्टर देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत जरूरी हो गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 119 ब्लॉकों में संस्कृति, मॉडल और विद्यालय खोलने का एक अनूठा निर्णय लिया है ताकि आम व्यक्ति के बच्चों तक भी उन्नत शिक्षा को आसानी से पहुंचाया जा सके। हमारी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए और लैगिंक समानता को कम करने के लिए प्रदेश में सरकार ने ''मातृत्व वंदना योजना'', ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना'', ''समेकित बाल विकास योजना'', ''पूरक पोषाहार कार्यक्रम'' और ''पिंक बस'' चलाने जैसी सुविधाएं मुहैया करवाने का काम किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे हरियाणा प्रदेश में चाहे महिला थाने खोलने की बात हो, चाहे खेलों के अंदर बेटियों को बढ़ावा देने की बात हो और चाहे 11 लाख बी.पी.एल. परिवार की बेटियों को सैनेटरी नैपकिन देने की बात हो, इन सब बातों के माध्यम से आज हमारे प्रदेश में बेटियों को हर दिशा में और हर कदम में सरकार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन में यह बात कहना चाहूंगा किः–

''यह मीरा की अमर भक्ति है
कभी मर नहीं सकती है,
ये झांसी की रानी है,
कभी डर नहीं सकती,
सुषमा स्वराज, कल्पना चावला और गीता फौगाट,
यह सब बेटियां हैं,
कौन कहता है कि बेटियां,
कुछ कर नहीं सकती''।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इस प्रकार से बेटियों को आगे बढ़ने के लिए विभिन्न योजनाओं में समावेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का समय अधिक नहीं लूंगा लेकिन मैं एक बात जरूर इस महान सदन में कहना चाहूंगा कि कल राव साहब ने इस महान सदन में हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को लेकर बात कही गई थी कि भारत एक भारतीय एक का नारा लगाना चाहिए। मैं अपने साथी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारत माता की जय का नारा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे भारत की छवि साम्प्रदायिक देश की बनती है। (विघ्न)

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने यह बात कभी नहीं कही। (विघ्न)

श्री भारत भूशण बत्तरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय सदस्य की ठीक नहीं है। (विघ्न)

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री बत्तरा जी को कहना चाहूंगा कि यह बात अपने नेताओं को समझायें। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस बात का वर्णन नेट पर भी मिल जायेगा। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : असीम जी, सदन में किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी न करे। (विघ्न)

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष टुकड़े–टुकड़े गैंग

का समर्थन करने जाते हैं और टुकड़े–टुकड़े गैंग कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा–अल्लाह–इंशा–अल्लाह। ऐसे लोगों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाते हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : असीम जी, प्लीज, आप कंकलूड कीजिए। (विघ्न)

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वोट लेने के लिए टुकड़े–टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि संसाधनों के ऊपर अल्पसंख्यकों का पहला हक है, यह बात ऑन–रिकॉर्ड है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : असीम जी, प्लीज आप कंकलूड कर लीजिए। (विघ्न)

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की बात का जवाब दे रहा हूं। कल इस महान सदन में राव साहब ने कहा था कि हमें हरियाणा एक हरियाणवी एक के स्थान पर भारत एक भारतीय एक का नारा लगाना चाहिए। मैं तो इन लोगों को इनके नेताओं की ही बात बता रहा हूं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भारत की ए.बी.सी.डी. सिखाकर आयें, उसको भारत के संस्कार और संस्कृति सिखाकर आयें और भारत क्या है, इस बारे में भी उसको सिखायें। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : असीम जी, प्लीज, आप कंकलूड कर लीजिए। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : उपाध्यक्ष महोदय, देश और प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम आदि होते हैं तब भी इनके नेता भारत माता की जय के नारे नहीं लगाते हैं। अगर इनके किसी भी नेता ने भारत माता की जय के नारे लगाये हैं तो बता दें।

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम–अप करते हुए इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि –

घुटनों पर झुके लोग, कोहनी पर टिके लोग,
बरगद का मुकाबला करते हैं गमलों में लगे लोग।

इनके मुंह से भारत और भारतीयता की बात शोभा नहीं देती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : असीम जी, आप कृपया करके कंक्ल्यूड करें।

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने 70 प्वायंट्य अपने अभिभाषण में रखे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : असीम जी, आप कृपया करके कंक्ल्यूड करें।

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय राज्यपाल महोदय ने 70 प्वायंट्स अपने अभिभाषण में रखे हैं। ये 70 के 70 विचार बिंदु इस हरियाणा प्रदेश को भारतवर्ष का नम्बर एक राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार की संकल्पबद्धता को जाहिर करते हैं। मैं इसके लिए पूरी सरकार का और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, सरकार के सभी सक्षम मंत्रियों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि–

परिदों को मिलेगी एक दिन मंजिल ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं,
जो रहते हैं दुनिया में चुपचाप अक्सर उनके हुनर बोलते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री भारत भूषण बतरा : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के पूर्व प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर यहां सदन में नकारात्मक टिप्पणी करने से पहले माननीय सदस्य को कम से कम 10 बार सोचना चाहिए क्योंकि उनको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा जी तक भी अपना गुरू कहते हैं। उन्होंने ही इस हिन्दुस्तान को इतनी बड़ी इकोनॉमी दी थी। वे 10 साल हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री रहे और पूरे हिन्दुस्तान को हर क्षेत्र में इतना ज्यादा आगे लेकर गये। अगर हम यहां पर मोदी जी के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी करें तो क्या इनको अच्छा लगेगा?

श्री राकेश दौलताबाद (बादशाहपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में बोलने के लिए अवसर प्रदान किया सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष जी, आज के दिन एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टैंट फील्ड है। जिसकी बेहतरी के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। मेरा मानना यह है कि सरकारें आ रही हैं और सरकारें जा रही हैं लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में कोई विशेष सुधार नहीं हो पा रहा है। मेरा इस मामले में यह कहना है कि स्कूल

टीचर्ज पर जो अननेसैसरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैशर है वह इसका सबसे बड़ा कारण है। आर.टी.आई. का जवाब देना हो, चुनाव में ड्यूटी, जनगणना, छात्रों के लिए आधार पंजीकरण, बैंक खाता खुलवाना और फैसिलिटी मैनेजमैंट इत्यादि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको करने में टीचर्ज लगभग–लगभग सारे का सारा साल ही लगे रहते हैं। इस मामले में मेरा यही सुझाव है कि हमें कोई न कोई ऐसी व्यवस्था ईजाद करना चाहिए जिसमें हम टीचर्ज से सिर्फ अध्यापन का ही कार्य करवायें। इसके अलावा मैं सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि एच.एस.वी.पी. केवल मात्र गुरूग्राम का ही 1000 करोड़ रूपये का भुगतान नहीं कर पा रहा है। अगर यह रकम ऐसे ही खड़ी रही तो इसके ऊपर उसको टैक्स भी देना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि एच.एस.वी.पी. की बकाया राशि का भुगतान जल्दी से जल्दी करवाने के लिए सरकार के स्तर पर क्या योजना बनाई जा रही है? एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो यूरोपियन संघ है उसके अंदर वेस्ट से एनर्जी बनाने के सिस्टम को बंद करके अब रि–साईकल करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैं गुरूग्राम से बिलॉग करता हूं जहां पर जो एयर पॉल्यूशन लैवल है वह ऑलरेडी पीक पर है। अगर वहां पर वेस्ट से एनर्जी बनाई जायेगी तो उससे और भी ज्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा इसलिए मेरा यह सुझाव है कि 65 परसैंट वेस्ट को हमें खाद बनाने के लिए यूज करना चाहिए और जो बाकी सॉलिड वेस्ट होगा उसको रि–साईकल करने के लिए हमारा फोक्स होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मेरा यह मानना है कि जो बल्क वेस्ट जैनरेटिड प्रेमिसिज हैं जो नये गुरूग्राम में अधिक हैं जिनके लिए नगर निगम, गुरूग्राम में बहुत सख्त कानून है कि उनको अपने वेस्ट को रिसाइकिल करना पड़ेगा लेकिन वे इस कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर वे इस कानून का पालन नहीं करते हैं तो एम.सी.जी. की तरफ से उन पर पैनल्टी का प्रावधान है लेकिन उन पर पैनल्टी भी नहीं लगाई जा रही है इसलिए इस बारे में सख्ती करने की जरूरत है ताकि प्रदूषण पर लगाम लग सके। इसी प्रकार से बरसाती नालों में अनट्रिटिड वेस्ट जा रहा है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। सैक्टर–9 का जो एस.टी.पी. है वहां पर अनट्रिटिड वेस्ट अभी भी बरसाती नाले में जा रहा है जो कि इल्लीगल है। पिछले 5–6 सालों से इसी प्रकार की एक्सरसाइज हो रही है। बार–बार अधिकारियों को बताने के बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। गुरूग्राम के सैक्टर 58 से लेकर सैक्टर–115 तक ये 57 सैक्टर बनते हैं जो जी.एम.डी.ए. के अधीन आते हैं लेकिन जी.एम.डी.ए. के

पास इन सैक्टर्स से कचरा उठाने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार से तो ये सैक्टर्स कचरे का ढेर बन जायेंगे। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि एम.सी.जी. के पास जो भी टूल है उससे ही काम चला कर वहां से कचरा उठवाया जाये। इसके अतिरिक्त मैं एक विषय और उठाना चाहूंगा कि गुरूग्राम के मास्टर प्लान में एक बहुत बड़ा बोटलनेक है जिसके कारण विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। कोर्टों में केस जाने के बाद सालों साल लटकते रहते हैं। इसके लिए कोई इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए जिससे कोर्ट में केस न जाएं और मास्टर प्लान की बोटलनेक खत्म हो तथा विकास के कार्य हों। इसी प्रकार से जो अनएप्रूव्ड कालोनीज हैं उनमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसका कारण यह है कि तहसील में पैसा लेकर रजिस्ट्रियां हो रही हैं। इस बारे में मेरा एक सुझाव यह है कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक साथ दिल्ली की सभी कालोनियों को रजिस्टर्ड किया है उसी प्रकार से अगर हम भी कालोनियों को एप्रूव करेंगे तो उससे रेवेन्यू भी आयेगा और विकास भी होगा। साथ ही साथ तहसील में जो भ्रष्टाचार होता है उस पर भी अंकुश लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू मिनिस्टर यहां पर बैठे नहीं हैं मैं आपके माध्यम से उनके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि मंत्री जी ने नवम्बर, 2019 में गुरूग्राम और फरीदाबाद नगर निगमों का ऑडिट करवाने की घोषणा की थी, वह किस प्रक्रिया में है उस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। इन दोनों जगहों पर बहुत ज्यादा करप्शन है। इनकी ऑडिट रिपोर्ट यथाशीघ्र उपलब्ध करवाई जाये। धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली (टोहाना): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रखने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। पिछले 2 दिन से सदन में हमारे वरिष्ठ सदस्यों द्वारा किसान और किसानी की बात करते हुए मैं सुन रहा हूं। हमारे प्रदेश का किसान कैसे खुशहाल हो, कैसे उसकी आमदनी बढ़े इस बारे में मैं अपने साथी सदस्यों की बातें सुन रहा था। आज सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है इसके लिए मैं सरकार और मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। 25 दिसम्बर, 2020 को सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है तथा उस दिन सरकार अपना सुशासन रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करेगी, उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार द्वारा किये गये जनहित में जो कार्य हैं उन पर भी सरकार ध्यान देगी। किसान की आमदनी कैसे दोगुनी

हो, किसान कैसे खुशहाल हो इस पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि किसान अन्नदाता है जो पूरे देश और प्रदेश का पालनपोषण करता है? लेकिन जो सरकार के प्रयास पिछली सरकार में रहे और उनसे पिछली सरकारों में भी रहे लेकिन आज किसान की हकीकत में जो स्थिति है यहां सभी सदस्य बैठे हैं हम सभी उससे परिचित हैं। सरकार जो भी सुविधा किसान को उसकी खेती बाड़ी के लिए देना चाहती है उसके लिए सरकार के प्रयास भी रहे हैं। पिछली सरकार भी किसानों के लिए बीमा योजना लेकर आई कि अगर किसान का खेती में नुकसान होता है तो उसका मुआवजा मिले । किसान की इंकम कैसे बढ़े उसके लिए फसल चक्र अपनाया जाए। मेरी तरफ से सरकार को एक सुझाव है क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं और एक स्वतंत्रता सेनानी का पौत्र हूं। एक किसान को किन–किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मैं उनसे भलीभांति परिचित हूं। पहले बड़े–बड़े जमीनदार होते थे। अब अगर हम रोहतक से चलकर हमारे फतेहाबाद जिले को क्रोस करते हुए सिरसा की तरफ जाएं तो जमीने बंट चुकी हैं। किसान के पास जो मलकियत पहले मुरब्बे के मुरब्बे होते थे वह कनालों से शुरू होकर अब एकड़ों में आ गये हैं। आज किसान जितना पेस्टिसाईड यूज करता है उससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है । अगर मैं अपने फतेहाबाद जिले की बात करूं तो हमारा नहरों का एरिया है। पहले फसल चक्र होता था उसमें दलहन की फसल भी होती थी, गन्ना और गेहूं की फसलें भी होती थी तथा धान की फसल की भी एक मात्रा थी। अब हमारा पूरा जिला केवल दो ही फसलों पर रह गया है गेहूं और धान। हमें किसानों को जागरूक करना होगा। उसके लिए जो बागवानी और वैजीटेबल की स्कीम्ज हैं उन पर हमें और काम करने की जरूरत है क्योंकि किसान फसल चक्र को बनाना चाहता है। जिसके लिए मैं एक उदाहरण बागवानी पर देना चाहूंगा कि अगर हम एक एकड़ में अमरूद का बाग लगाते हैं तो तकरीबन 50 हजार रुपये के आस–पास खर्चा आता है। इसमें सरकार ने प्रयास किये हैं और किसानों को सब्सिडी दी है लेकिन वह बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाए। दूसरा अगर किसान सब्जी की खेती में जाना चाहता है उसमें भी सरकार ने बहुत सी सब्जियों के रेट निर्धारित किये हैं। वह भी सरकार का एक अच्छा प्रयास है जो पिछली सरकारों में नहीं हुआ था। आज मौजूदा सरकार ने किसानों की आलू, टमाटर या कोई और सब्जी की फसल है उसका एक रेट निर्धारित किया है। मैं तो सदन के माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले किसान की फसल की कोस्टिंग तय की

जाए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई किसान एक एकड़ में आलू की खेती करता है तो उसकी मिनिमम कोस्ट 20 से 25 हजार रुपये आती है क्योंकि उसका बीज ही इतना महंगा होता है । जब किसान की फसल का दाम दिया जाता है तो शायद वह उस भाव के हिसाब से उतना ही दे दिया जाता है। जैसे एक एकड़ में करीब 100 टन के हिसाब से आलू पैदा होता है तो किसान को उस भाव के हिसाब से उतना ही दे दिया जाता है इसलिए हम ऐसी स्कीम्ज लेकर आएं जिससे किसान को मिनिमम श्योरिटी मिले ताकि वह फसल चक्र की तरफ जा सके। उससे हमें तीन–चार फायदे होंगे। अगर बागवानी आएगी तो पर्यावरण भी अपने आप ठीक होगा और फसल चक्र से अनाज में भी शुद्धता आएगी क्योंकि आज पेस्टिसाईड का ज्यादा यूज होता है। उसके लिए भी किसान को जागरूक करने की जरूरत है। मैं सदन के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि सबसे पहले किसान की जागरूकता के लिए किसान मेले लगाने होंगे और सरकार द्वारा किसान को जो स्कीम्ज दी जाती हैं उनमें इजाफा करना होगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो क्योंकि एक शिक्षित समाज ही मजबूत समाज का निर्माण कर सकता है। अभी पिछले दिनों जो पूर्व बजट पर चर्चा की गई थी उसमें हमारे जो सरकारी स्कूल्ज हैं उनके हालात हमारे सभी साथी जानते हैं कि उनकी हालत क्या है क्योंकि उनमें बच्चे पढ़ने के लिए जा ही नहीं रहे हैं। सरकारी स्कूल्ज में कहीं 28 बच्चे हैं और कहीं 30 बच्चे हैं। उसमें सरकार प्रयास भी कर रही है लेकिन सरकार इतनी मजबूर हो चुकी है जिसके कारण सरकार करीब एक हजार स्कूल्ज बन्द करने जा रही है। आज कुछ परिवार ऐसे हैं जो प्राईवेट स्कूल्ज की फीस नहीं दे सकते हैं। आज प्राईवेट स्कूल्ज में दिन प्रतिदिन तरक्की होती जा रही है । अगर मैं अपने टोहाना हल्के की बात करूं तो पहले वहां केवल एक प्राईवेट स्कूल था आज वहां 25 प्राईवेट स्कूल्ज बन चुके हैं। ऐसी व्यवस्था हम सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं कर पाते। यह सोचने तथा गहन विचार का विषय है क्योंकि बिना शिक्षित समाज के मजबूत राष्ट्र और प्रदेश का निर्माण नहीं हो सकता है और इसी प्रकार यदि हम सबको साथ लेकर चलेंगे तो तभी हम अपने देश–प्रदेश व समाज का सही ढंग से उत्थान कर पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कई सरकारी स्कूल बड़े अच्छे ढंग से भी काम कर रहे हैं। इन स्कूलों में एस.सीज./बी.सीज. परिवारों के बच्चों को मिड–डे मील व अन्य कईं प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं। मैंने कई सरकारी स्कूलों में जाकर देखा है कि वहां पर बड़े अच्छे ढंग से काम हो रहा है परन्तु बावजूद इसके मैं यह जरूर कहना

चाहूंगा कि हमें सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को जरूर सुधारना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खेलों की बात है निःसंदेह खेल नीति में काफी सुधार आया है। माननीय खेल मंत्री जी सदन में बैठे हैं मैं उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारे हलके में एक स्टेडियम बना हुआ है। स्टेडियम की इस बिल्डिंग को बने हुए एक साल का समय बीत चुका है परन्तु बावजूद इसके आज तक इसमें स्टॉफ व अन्य दूसरे प्रकार की किसी सुविधा का इंतजाम नहीं किया गया है। अगर आगामी 2–3 साल तक यह बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी रही तो निश्चित रूप से यह खंडहर का रूप धारण कर लेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस स्टेडियम में स्टॉफ व अन्य दूसरी प्रकार की सुविधाओं का प्रबंध किया जाये ताकि हमारे हलके की जो खेलों में उभरती हुई प्रतिभायें हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सिविल अस्पताल की भी एक बड़ी भारी समस्या है। वर्ष 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और वर्ष 1966 में हरियाणा अस्तित्व में आया था। हरियाणा प्रदेश के टोहाना हलके का संबंध उन बड़ी–बड़ी राजनीतिक ताकतों के साथ रहा है जिनकी शुरू से ही देश और प्रदेश की सत्ता में विशेष भागीदारी रहती आई है। इतने महत्वपूर्ण मेरे हलके टोहाना के अस्पताल को आज महज रैफर अस्पताल के रूप में जाना जाता है जोकि बहुत ही गम्भीरता का विषय है। मेरा निवेदन है कि इस अस्पताल को 100 बैड की क्षमता के अस्पताल के तौर पर विकसित किया जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी जब पिछली सरकार में मेरे हलके में विभिन्न प्रोग्रामों में भाग लेने गए थे तो अनेकों घोषणायें भी करके आये थे जिनमें एक कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा थी और दूसरी टोहाना अस्पताल को 100 बैड की क्षमता करने की घोषणा थी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि इन घोषणाओं को भी पूरा करने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं किसानों से जुड़े हुए मामले पर अपनी बात रखता हूँ। हमारे यहां किसानों ने नहरों के साथ–साथ ट्यूबवैल लगा लिए थे जिसके कारण नहरी विभाग की तरफ से इन किसानों को नोटिस थमा दिए गए हैं। एक किसान जब अपनी फसल को पालने के लिए एक ट्यूबवैल लगाता है तो उसका करीबन 8–10 लाख रूपये खर्चा आता है। आज विभाग ने इन किसानों को जो एकाएक नोटिस थमा दिए हैं इसकी वजह से हमारे क्षेत्र के किसान काफी चिन्तित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन किसानों ने अपनी मलकीयत जमीन में ही ट्यूबवैल लगा रखे हैं लेकिन चूंकि नहर इनकी मलकीयत जमीन के बहुत नजदीक है, इसलिए

नहरी विभाग ने इनकी मलकियत जमीन में नहर के साथ लगे ट्यूबवैल की एवज में इन्हें नोटिस थमा दिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पहले नहरें कच्ची होती थी और नहर में जो पानी आता था उसको जमीन द्वारा सोख लिया जाता था। ऐसी सूरत में यदि नहर के साथ कोई ट्यूबवैल लगाता था तो उसको नहरी विभाग द्वारा इसलिए प्रतिबंधित किया जाता था कि कहीं नहर के साथ लगते ट्यूबवैल, नहरी पानी को न खींच लें और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नहर से दूर ट्यूबवैल लगाने के कुछ नियम बना दिए गए थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों को जो यह नोटिस दिए गए हैं इन नोटिसिज को वापिस लेकर किसानों को राहत देने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के विषय पर अपनी बात रखूंगा। हमारा क्षेत्र डॉर्क जोन में आता है इसलिए यहां पर किसानों को जो भी बिजली के कनेक्शंज दिए जाते हैं उसके लिए एक एन.ओ.सी. रिक्वायर्ड होती है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दलालों ने बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों से 3 से 5 लाख रूपये तक की राशि लेकर अवैध रूप से एन.ओ.सी. प्रोवाइड करवाकर 142 बिजली के कनेक्शंज लगवाने का काम किया था। जब इस संबंध में आर.टी.आई. के माध्यम से जानकारी मांगी गई तो बिजली विभाग के अधिकारियों ने अपने आपको बचाने के लिए उन 142 किसानों के बिजली के कनेक्शंज काट दिए जिन्होंने अवैध तरीके से एन.ओ.सी. प्राप्त करके बिजली के कनेक्शन लिए थे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे किसान भाई आने वाले समय में धान लगाने की बात कह रहे हैं यदि इस प्रकार से उनके बिजली के कनेक्शन कटे रहे तो मैं समझता हूँ कि यह उनके लिए बहुत दिक्कत की बात होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हलके की और भी बहुत सी समस्यायें है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : बबली जी, आप अपनी समस्यायें लिखकर भी दे सकते हैं। आपका बोलने का समय पूरा हो गया है। अतः आप प्लीज अपनी सीट पर बैठिए।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली: उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है मैं अपने हलके की दूसरी समस्यायें लिखकर संबंधित माननीय मंत्रियों को दे दूंगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री विनोद भ्याना (हांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार का

विजन सदन के पटल पर रखा है। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा और जजपा की सरकार किसान, मजदूर, व्यापारी और युवा के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से जाहिर होता है कि सरकार वर्ष 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने वर्ष 2020 'सुशासन संकल्प वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस संकल्प के जरिए सरकार सभी विभागों में हरियाणा के नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरा वर्ष ध्यान देगी, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए कितने हर्ष की बात है कि सरकार नये जनादेश के साथ सभी क्षेत्रों में निरन्तर कार्यरत है। मार्केटिंग सीजन 2019–20 के दौरान 6 लाख 19 हजार मीट्रिक टन सरसों की रिकॉर्ड खरीद की गई। इसके अलावा 13 हाजर 156 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद भी की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की पूरी राशि किसानों के खातों में सीधे जमा कराई गई। खरीद में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'किसान पंजीकरण पोर्टल (मेरी फसल मेरा ब्यौरा) के माध्यम से फसलों की अधिकतम मात्रा में खरीद करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। बाजार में उपज के भाव कम होने की स्थिति में 'भावांतर भरपाई योजना' के तहत किसानों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मशीनों पर 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान करके लगभग 1672 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किये गये हैं। फसल अवशेषों के स्थान पर ही प्रबंधन के लिए लगभग 5228 किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपकरण प्रदान किए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के जो किसान मूलधन की अदायगी समय पर करते हैं उन्हें बिना किसी ब्याज के फसली ऋण प्रदान किये जा रहे हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान लगभग 5 लाख किसानों को 127 करोड़ 88 लाख रुपये की ब्याज राहत दी गई है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले ऐसे किसानों, जो ऋण की अदायगी न करने के कारण डिफाल्टर हो गये थे, उन्हें बड़ी राहत पहुँचाने के लिए पहली सितम्बर, 2019 से एकमुश्त निपटान योजना शुरू की गई है। बेहतर जल प्रबंधन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 6000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 'अटल भूजल योजना' शुरू की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना में सात राज्यों को शामिल किया गया है,

हमें इस बात की खुशी है कि हरियाणा भी इसमें शामिल है। यह योजना हरियाणा के जल संकट वाले चयनित 36 खंडों में लागू की जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार भू– रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटलाइज कर रही है ताकि भू–स्वामी किसी भी समय अपनी सम्पत्तियों और भू–रिकॉर्ड का ब्यौरा ऑन–लाइन प्राप्त कर सके। अब किसानों को पटवारी के पास और तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही प्रशंसनीय है। सरकार राज्य के पशुधन को उच्चकोटि की पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य में लगभग 2.20 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। सरकार पहली सितम्बर, 2019 से राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम शुरू किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार एक संयुक्त टीके का उपयोग करके राज्य में गायों और भैंसों को मुंह–खुर की बीमारी से मुक्त बना रही है। सरकार हर किसान को पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्राथमिकता दे रही है। हर खेत को पानी पहुँचाने के लिए सभी टेलों तक पानी पहुँचाने का अभियान शुरू किया गया है। सरकार राज्य में सभी श्रेणियों के उपभोक्तओं को पर्याप्त और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध करवा रही है। 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना के तहत 4463 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि पिछले तीन वर्षों में दोनों बिजली वितरण निगमों की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां 30.02 प्रतिशत से घटकर 17.45 प्रतिशत रह गई है। इससे बिजली वितरण कम्पनियां काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई हैं । पिछले 2 वर्षों के दौरान बिजली वितरण कम्पनियां लाभ में भी रही हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है कि बिजली के रेट घटाए गए हैं । सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वचनबद्ध है । सरकार ने अपने हल्कों का विकास करवाने के लिए प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ रूपये प्रदान करने का वायदा किया है । इससे प्रदेश सरकार की सोच और नीति सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक का पता चलता है । सरकार ने अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को नियमित करने का काम किया है । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : विनोद भ्याना जी, अब आप वाइंड अप कर लीजिए ।

श्री विनोद भ्याना : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने सभी को आवास उपलब्ध करवाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय जन आवास योजना शुरू की है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के

नेतृत्व में हमारी सरकार ने बच्चों को मैरिट पर नौकरी देकर एक बहुत अच्छा और बड़ा काम किया है । मैं इसे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं और इसके लिए हरियाणा सरकार को धन्यवाद देता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि मेरे हल्के के युवाओं को रोजगार देने के लिए हांसी में कोई बड़ा उद्योग लगाया जाए । हांसी में किसी समय हैफेड का एक बहुत बड़ा स्पिनिंग मिल होता था । उसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने बंद कर दिया था । इस वजह से वहां पर हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे । उपाध्यक्ष महोदय, हांसी में सरकार की लगभग 300 एकड़ जमीन खाली पड़ी है । अगर सरकार वहां पर कोई बड़ा उद्योग लगाना चाहे तो उसे इसके लिए जमीन भी ऐक्वायर नहीं करनी पड़ेगी । हांसी शहर नैशनल हाइवे 9 पर स्थित है । वहां पर हांसी–रोहतक रेल लाइन का काम भी बड़ी तीव्र गति से चल रहा है । अगर वहां पर कोई भी उद्योग स्थापित किया जाए तो वह बहुत अच्छे ढंग से चलेगा । उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्रीमती शैली : उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने आपको सदन में बोलने के लिए विधायकों के सीरियलवाइज नाम दिए हुए हैं । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गीता जी, हम नई चुनकर आई महिला सदस्य को सदन में बोलने का मौका दे रहे हैं । अतः आप उनको बोलने दें ।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने आपको सीरियलवाइज नाम दिए हुए हैं । अब तक सदन में आई.एन.सी. पार्टी का केवल एक माननीय सदस्य बोला है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गीता जी, हम आपको भी सीरियलवाइज बोलने का मौका देंगे । आपकी पार्टी का सदन में केवल एक नहीं बल्कि कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं । अतः अब आप नये सदस्य को बोलने दीजिए । (विघ्न)

श्रीमती शैली (नारायणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा और अपने हल्के की कुछ समस्याएं आपके सामने रखना चाहती हूं । मैं सबसे पहले अस्पताल के बारे में बात करना चाहती हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगी कि नारायणगढ़ में एक सिविल हॉस्पिटल है । इसमें सरकार द्वारा डॉक्ट्र्स की कुल 43 स्वीकृत पोस्ट्स हैं

लेकिन वहां पर केवल 3–4 डॉक्ट्र्स ही पोस्टेड हैं । अतः मेरा निवेदन है कि वहां पर डॉक्ट्र्स की संख्या को बढ़ाकर पूरा किया जाए और आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाई जाएं । वहां पर कोई भी विशेषज्ञ नियुक्त नहीं है । वहां पर मरीजों को ज्यादा तकलीफ होने पर रैफर करके चंडीगढ़ या पंचकूला भेजा जाता है । अतः मेरा निवेदन है कि वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए । उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों की बात करना चाहूंगी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगी कि मेरे हलके में सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है। इसके बारे में मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी लिखकर दिया हुआ है कि हमारी सड़कों को जल्दी ठीक करवाया जाए। तीसरी बात मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगी कि नशे की समस्या जो पूरे हरियाणा के अन्दर है और हमारा हरियाणा प्रदेश भी नशे की गिरफ्त में आ चुका है। आज हमारे क्षेत्र नारायणगढ़ के बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। इस पर सरकार ध्यान दे। चौथी बात बुढ़ापा पैंशन के बारे में है। मैं बुढ़ापा पैंशन के बारे में उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगी कि जो बुढ़ापा पैंशन विधवाओं/बुजुर्गों को बैंकों के माध्यम से गांवों में दी जाती है। इसके बारे मैं मैं कहना चाहूंगी कि इसमें बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगो को यह छोटी समस्या लगती है, लेकिन हम गांवों में जाकर देखें तो हमारे बुजूर्गों को पैंशन लेने के लिए आने–जाने में काफी दिक्कत होती है। मैं चाहूंगी कि बैंक का एक कर्मचारी संबंधित गांवों में जाए और वहीं उनके गांवों में बुजूर्गों को पैंशन दी जाए। पांचवी बात गरीबों के राशन के बारे में कहना चाहूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, जो गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है, उसमें पहले गेहूं दिया जाता था, परन्तु अब आटा दिया जाता है लेकिन उस आटे की क्वॉलिटी अच्छी नहीं होती है। गांवों में संबंधित सभी लोगों की मांग है कि आटे की जगह पर लोगों को गेहूं दिया जाए ताकि उसको साफ करके उसका यूज किया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, उनको खराब आटा दिया जाता है। उस आटे को संबंधित लोग हमें दिखाते हैं और उस आटे को पशु भी नहीं खाते हैं, इसलिए सरकार द्वारा राशन में दोबारा से गेहूं दिया जाए। इसके अतिरिक्त मैंने शुगर मिल के बारे में क्वैश्चन लगाया था। किसानों को आश्वासन तो बार–बार दिये जाते हैं कि उनके गन्ने की फसल की पेमैंट जल्दी दे दी जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक हर वर्ष किसान धरने पर बैठे रहते हैं और हरियाणा प्रदेश के

इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसानों को अपने गन्ने की फसल की पेमैंट लने के लिए काफी दिनों तक नदी में बैठना पड़ा और सरकार द्वारा उनको आश्वासन दिया गया था कि उनकी गन्ने की फसल की पेमैंट कर दी जाएगी, लेकिन आज तक किसानों को पिछले साल की उनकी फसल की पेमैंट नहीं की गयी है। इस साल फिर किसानों की गन्ने की फसल का बकाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि आश्वासन तो बार–बार दिये जाते हैं, परन्तु किसानों को उनकी फसल की पेमैंट नहीं दी जाती है। अगर मिल मालिक किसानों को उनकी फसल की पेमैंट नहीं करते हैं तो सरकार उनको अपने अधीन ले। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री नयनपाल रावत (पृथला): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के नीतिगत फैसले लिये हैं जिसमें मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी और अन्य सभी को बहुत सारी राहत मिली है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, के तहत सरकार पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को शिक्षा फ्री में दे रही है, स्टाई फंड, मुफ्त इलाज और बहुत सारी दूसरी सुविधाएं भी दे रही है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। एक छोटा सा सवाल माननीय उद्योग मंत्री जी के लिए है। यानी माननीय उप मुख्य मंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के लिए है। उद्योग हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इससे न केवल टैक्स मिलता है बल्कि बेरोजगारी भी काफी हद तक कम होती है। हर साल 20–30 दिनों तक पाल्यूशन के नाम पर उद्योगों को एक महीने के लिए बन्द कर दिया जाता है। जबकि उद्योगों से पाल्यूशन केवल 21 प्रतिशत तक ही होता है और बाकी 79 प्रतिशत पाल्यूशन अन्य कारणों से ही होता है। इसलिए यह हथोड़ा केवल उद्योगों पर न चलाया जाए। दूसरी बात यह है कि मेरा पृथला विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ–साथ एक औद्योगिक एरिया है जिसमें लगभग 700 से 1000 तक छोटी–बड़ी कम्पनियां हैं। इन कम्पनियों के मालिकों ने अपनी 10 प्रतिशत ई.डी.सी. जमा करवा दी है, परन्तु उनके लिए अभी भी बिजली, सड़क, सीवर और पानी की समस्या है। मैं चाहता हूं कि सरकार उनकी सीवर, बिजली और पानी की समस्या को खत्म

14:00 बजे

करके जो बकाया ई.डी.सी./आई.डी.सी. बनती है, उसको उनसे प्राप्त करें। दूसरा जो फायर स्टेशन है वह काफी दूर है। जब पृथला विधान सभा क्षेत्र में कोई ऐसी घटना हो जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में काफी देर लग जाती है इसलिए फायर स्टेशन पृथला की कंपनियों के लिए लगाया जाये। इसी तरह से फरीदाबाद में मारुति की मदर यूनिट लगाई जाये क्योंकि फरीदाबाद का क्षेत्र बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर मारुति कम्पनी 1 हजार एकड़ जमीन प्लांट लगाने के लिए और चाहती है इसलिए हम उस कम्पनी को जमीन प्रोवाईड करवाकर देंगे ताकि वहां पर प्लांट लगाया जा सके, जिससे सरकार का रैवेन्यू बढ़ेगा और वहां के स्थानीय बेरोजगारों युवकों को रोजगार के साधन भी मिल सकेंगे। यही मेरी छोटी सी मांग थी। धन्यवाद।

श्री संजय सिंह (सोहना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने हमारे प्रदेश के 70 बिन्दुओं पर विशेष तौर पर ध्यान दिया है। मैं इस महान सदन में कुछ बिन्दुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया कि आने वाले समय में किसानों की आमदनी दोगुनी होगी जिससे हमारे हरियाणा प्रदेश का किसान खुशहाल होगा। इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सभी किसानों को समय पर पानी देने की एक विशेष व्यवस्था भी की है, इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मेवात जिले में बेरोजगारों को रोजगार देने की सबसे पुरानी मांग थी जिसको पूरा करने का काम किया गया। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने मेवात के किसानों को ध्यान में रखते हुए मेवात कैनाल फीडर की जो हमारी वर्षों पुरानी मांग थी उसको भी 1150 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेवात के लिए घोषणा करने में एक मिनट का भी समय नहीं लगाया। मुझे यह बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस पर भी काम चालू हो गया है। इसके साथ–साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसानों को पिछली सरकारों के समय में खराबे का मुआवजा नहीं दिया गया था, उनको मुआवजा देने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन में यह बात भी कहना चाहूंगा कि पहले किसानों के साथ छलावा और धोखा

करके उनको मात्र योजनाओं का ढोंग दिखाकर वोट हथियाने का काम किया जाता था। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही पहले दो महीने में जो ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब हुईं थीं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार ने घोषणा भी की थी कि जिन किसानों की फसलें ओलावृष्टि से खराब हुई हैं उनको मुआवजा दिया जायेगा लेकिन उस घोषणा को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा करके 1100 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को दिया गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ''मेरी फसल मेरा ब्यौरा'' के माध्यम से किसानों की फसलों को खरीदने का काम करेगी। आज डिजिटलाइज का जमाना है और मेरा मानना है कि पुराने समय में जो हमारी पुरानी प्रथाएं हुआ करती थीं, जब कोई व्यक्ति अपनी बेटी का रिश्ता लेकर किसी दूसरे परिवार में जाता था तो सबसे पहले यह पूछा जाता था लड़के के नाम कितनी जमीन आती है और बाद में नौकरी के बारे में पूछा जाता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी बात को ध्यान में रखते हुए डिजिटलाइज योजना जो किसानों के लिए मुहैया करवाई है कि किसान कहीं पर भी चला जाये चाहे वह अपने देश में किसी भी स्थान पर हो या प्रदेश में किसी भी स्थान पर हो या फिर वह विदेश में कहीं पर भी बैठा हो अगर वह अपनी जमीन की पूरी डिटेल देखना चाहता है तो एक बटन दबाते ही उस किसान की सारी जमीन की डिटेल उसके सामने आ जायेगी। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' का नारा दिया था उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पूरा करके दिखाया है। मैं इस बात को इस महान सदन में उदाहरण के रूप में बातना चाहूंगा कि जनवरी माह में हरियाणा पुलिस की भर्ती की गई थी उसमें एक हजार महिला सिपाही की भी भर्ती हुई थी, मैं समझता हूं कि ऐसा भी पहली बार हरियाणा प्रदेश में हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में एक हजार महिला सिपाही की जो भर्ती हुई है उससे मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने की बात साकार हो सकेगी। यह एक बहुत ही अच्छा डिसीजन सरकार के स्तर पर लिया गया है। मैं माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बतरा जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां पर बहुत ही अच्छी–अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने उनकी पार्टी की सरकार के समय में जो–जो भ्रष्टाचार के मामले

हुए थे उनको भी उजागर किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, जो सोहना विधान सभा क्षेत्र है वह एक ऐसा विधान सभा क्षेत्र है जोकि हर मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो उप–मण्डल कार्यालय हैं। इन दोनों उप–मण्डलों में मिनी सचिवालय की बिल्डिंग नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि इन दोनों उप–मण्डलों में मिनी सचिवालय का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाया जाये। इसी के साथ–साथ जो तावडु 84 का क्षेत्र है उसमें एक बड़े बस स्टैण्ड का निर्माण भी जल्दी से जल्दी करवाया जाये। वह एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला क्षेत्र है लेकिन वहां पर अभी तक भी बस स्टैण्ड की सुविधा नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर हुड्डा के दो सैक्टर बनाने की घोषणा की थी। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस बारे भी वहां पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही शुरू करवाई जाये। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री नीरज शर्मा जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रखेंगे।

श्री नीरज शर्मा (एन.आई.टी., फरीदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में बोलने के लिए जो अवसर प्रदान किया सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदय जी, हमारी पार्टी ने आज जो लिस्ट आपको दी है उसके मुताबिक आपको मुझे बोलने का समय देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : गीता जी, जो मेरे पास आपकी दिनांक 24.02.2020 की लिस्ट है उसके अनुसार राव दान सिंह और श्री भारत भूषण बतरा जी के बाद अब श्री नीरज शर्मा जी का नम्बर है।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आज 25.02.2020 की लिस्ट की बात कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : गीता जी, अगर ऐसी बात है तो आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए थी कि आज आपकी पार्टी के उन्हीं

माननीय सदस्यों को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया जाये जो आज दिनांक 25.02.2020 की लिस्ट में हैं और 24.02.2020 की लिस्ट को टेक–अप न किया जाये लेकिन इस प्रकार की कोई पूर्व सूचना हमें नहीं मिली है। इसके अभाव में ही हम दिनांक 24.02.2020 की लिस्ट को ही टेक–अप कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अभी आप बैठे क्योंकि मैंने श्री नीरज शर्मा जी का नाम अनाउंस कर दिया है इसलिए पहले उनको बोल लेने दें उसके बाद आपकी पार्टी द्वारा जो लिस्ट आज दी गई है उसके मुताबिक आपकी पार्टी के माननीय सदस्यों को बोलने के लिए समय दे दिया जायेगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष जी, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आज दिनांक 25.02.2020 की लिस्ट के मुताबिक आपको मुझे बोलने के लिए समय देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः गीता जी, आपकी पार्टी की तरफ से कल बोलने वालों की लिस्ट दी गई थी हमने आज की दी हुई लिस्ट भी उसी के साथ जोड़ दी है। अगर आप कल की दी हुई लिस्ट को रिजैक्ट करने के लिए कहती हैं तो हम आज की लिस्ट के अनुसार बुलवा देंगें। हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने आज के वक्ताओं की अपनी नई लिस्ट दी हुई है आप उसके अनुसार बुलवा दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैडम गीता भुक्कल और नीरज शर्मा जी का यह जो इतना बड़ा मामला बन रहा है आप इनको बोलिए कि ये फैसला कर लें और बतरा जी से पूछ लिया जाये कि किस रूल के तहत किस सदस्य का नम्बर कब आयेगा? (हंसी)

श्री नीरज शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बताया गया है कि हरियाणा में 26 लाख 97 हजार परिवारों को पी. डी.एस. के द्वारा आई.टी. समर्थित उपकरण लगाए और 1.19 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ा गया। मैं समझता हूं कि इस सारे कार्य में सरकार का कई सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा। आई.टी. का भी और जो हम गरीब को राशन देते हैं जो हम महंगी दर पर खरीदते हैं और आगे सस्ती दर पर देते हैं, उसका जो अंतिम छोर तक फायदा पहुंचना चाहिए था वह फायदा नहीं पहुंचा है। सरकार इस पर ध्यान दे तथा मशीनों को टाईम–टाईम पर चैक करवाए। **(इस समय श्री अध्यक्ष**

पदासीन हुए।) अध्यक्ष महोदय, जो भी डिपो धारक है उसकी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जाए कि प्रति यूनिट कितना राशन मिलना है और कब मिलना है? कहने को तो सरकार यह कह रही है कि अगर आपका आधार लिंक्ड राशन कार्ड है और आपको राशन मिल रहा है तो आप पूरे हरियाणा में कहीं से भी राशन ले सकते हैं। अब सरकार नई योजना ला रही है कि हम 12 स्टेट्स को आपस में जोड़ सकते हैं लेकिन हकीकत यह है कि मान लीजिए जवाहर कालोनी में जो कि मेरी विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरा डिपो धारक है और अगर मैं डबुआ कालोनी में जाऊं तो वह भी मुझे राशन नहीं देता है। ब्लॉक और तहसील तक की तो बात ही दूसरी है। यह पूरे हरियाणा की स्थिति है। मैं समझता हूं कि जब उपभोक्ता के लिए एक जागरूकता बोर्ड डिपो धारक के सामने लग जायेगा तो कोई शक नहीं रहेगा कि हर उपभोक्ता को उसका राशन मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जिले से मैं अपनी पार्टी का इकलौता विधायक हूं इसलिए आपको मेरा विशेष ख्याल रखना चाहिए और मुझे बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाये। शायद यदि यह सरकार सत्ता में है तो फरीदाबाद की वजह से हैं क्योंकि वहां इनकी पार्टी के आठ–आठ विधायक हैं परंतु मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं कि सदन में यह चर्चा नहीं होनी चाहिए कि पहले यह हो रहा था । पहले यह हो रहा था। The two wrong things can never make one right thing. जो पहले हो रहा था उसके लिए जनता ने दोबारा थोड़ी चुना है। मुख्यमंत्री जी, आपने यह कहा था कि हम अच्छा करेंगे और बढ़िया करेंगे लेकिन अभी बेहतरी की गुंजाईश है। शायद ये मेरे साथी बोल नहीं पाते पता नहीं क्या कारण है। जबकि बहन सीमा त्रिखा जी सबसे सीनियर हैं दूसरी बार की विधायक हैं। सर, एक शख्स ने जिल्लेइलाही का नाम लिया था। उस जिल्लेइलाही के समय जाजिया कर लगता था। आज हम फरीदाबाद में कहीं से भी किसी भी कोने से घूसें । हम बात तो बहुत करते हैं के.जी.पी., के.एम.पी., सोहना रोड और एलिवेटिड रोड की लेकिन क्या आज फरीदाबाद में एक भी ऐसा रास्ता है जहां से हम बिना जाजिया कर दिये जा सकते हैं? हम रोड टैक्स और हाऊस टैक्स दे रहे हैं। हम डिवैल्पमैंट चार्ज भी दे रहे हैं। गाड़ियों के इंश्योरैंस का पैसा भी हम दे रहे हैं लेकिन हम फरीदाबाद के वासियों को सरकार से मिल क्या रहा है केवल प्रदूषण के नाम पर कैंसर? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमें एक रास्ता तो ऐसा दे दो जहां हम बिना पैसे के फरीदाबाद के अन्दर घुस सकें। दूसरा आज मुझे विधान सभा में एक बहुत अच्छी

जानकारी मिली कि अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं नाम नहीं ले रहा हूं जी सिर्फ उदाहरण ही दे रहा हूं कि एक–एक बूंद शराब की मैपिंग होगी। उप मुख्यमंत्री जी, अगर आप यह मैपिंग पानी की दृष्टि में भी कर दें तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि हरियाणा के हर आदमी को साफ और स्वच्छ पानी का वितरण होगा। मैं अभी खुद की निजी यात्रा पर अहमदाबाद गया था वहां मैं स्काडा सिस्टम देखकर आया हूं। शहरों में पानी की इतनी कमी नहीं है। उससे ज्यादा पानी की चोरी है। जो भी जल पर आधारित उद्योग हैं और जिनको महंगे रेट पर पैसा मिलता है आधे से ज्यादा पानी वे चुरा लेते हैं। हम यहां 90 विधान सभाओं के प्रतिनिधि बैठे हैं । मैं सभी को एक बात कहूंगा ध्यान रखना आपके मोहल्ले में हो सकता है पानी न आए। अगर आपके मोहल्ले में सर्विस स्टेशन है तो उसका एक दिन भी पानी नहीं रूकेगा। उसके पास कहां से पानी आ रहा है। कहीं न कहीं सिस्टम में लिकेज है। अहमदाबाद के अन्दर लोगों को जो पीने का पानी मिलता है वह बिल्कुल स्वच्छ मिलता है। वहां आर.ओ. में भी पानी की वेस्टेज नहीं होती है।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : शर्मा जी, गुजरात की तारीफ तो आपने भी कर दी है कि वहां पर स्वच्छ पानी मिल रहा है।

श्री नीरज भार्मा : सर, मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अहमदाबाद की बात कर रहा हूं। वैसे जो अच्छा काम है उसकी अच्छाई करनी चाहिए उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तीसरा बिजली के ऊपर बात हो रही थी। डी.एच.बी.वी.एन. के अन्दर लाईन लोस कम है। यू.एच.बी.वी.एन. के अन्दर लाईन लोस ज्यादा हैं। इसमें मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि यह लाईन लोस क्यों है ? जैसे गुड़गांव में स्मार्ट ग्रिड सिस्टम है वह हमारे फरीदाबाद में भी लागू कीजिए। हम बिजली का पूरा पैसा देते हैं। हमें 24 घण्टे बिजली चाहिए। हम सस्ती मंदी वाली बात नहीं करते हैं। तीसरी बात अध्यक्ष महोदय, हर चीज कॉट्रैक्ट पर चलती जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, आपको बोलते हुए 5 मिनट हो गये हैं।

श्री नीरज भार्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अपना पर्सनल उदाहरण दे रहा हूं कि एक साल से आई.टी. डिजिटलाईजेशन आया जिससे मेरे मोबाईल पर बिल आता था कि साहब अपका इतना बिल है क्या मैं उसको भर दूं। इस तरह से साल भर मैंने बिजली का बिल भरा आज एक साल के बाद मेरे खुद के ऊपर छप्पर फाड़ दिया कि आपका ये 1 लाख 70 हजार रुपये का बिल है। मैं एक एम.एल.ए.

होकर खुद धक्के खा रहा हूं। बिजली विभाग में चिट्ठी लिख रहा हूं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। मैं कहता हूं कि साल भर में विभाग ने मेरा हर महीने बिल क्यों नहीं दिया? विभाग कहता है कि आपका एवरेज का बिल था। मैंने कहा अब तो मीटर भी मेरे घर के अन्दर नहीं है। अब तो मीटर भी बाहर लगा हुआ है । उसका पैसा भी मैंने खुद भरा है फिर मेरा एवरेज का बिल क्यों आ रहा है? विभाग कहता है कि मीटर रीडर की गलती है। मैंने कहा कि उस पर कार्यवाही कौन करेगा? उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुवर। मैंने कहा उसके ऊपर सुपरवाईजर कौन है कहने लगे कि कॉन्ट्रैक्टर। अध्यक्ष महोदय, क्या यह कॉन्ट्रैक्टर की सरकार है? जब एक एम.एल.ए. के साथ ये स्थिति है तो एक आम आदमी के साथ यह स्थिति क्या बनेगी?

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, आप समअप कीजिए।

श्री नीरज भार्मा : सर, मैं समअप कर रहा हूं । 10 मिनट का समय है मैं 10 मिनट में ही समअप करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे वह रास्ता बता दीजिए, वह दरवाजा बता दीजिए जहां पर जाकर मुझे राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, आज दीपक मंगला जी सदन में नहीं हैं उन्होंने कल सदन में सरकार की बहुत तारीफ की और संजय जी ने भी बहुत तारीफ की लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में लिखी हुई पंक्तियों के आधार पर ही किसी बात की तारीफ करता हूँ। सदन में साफ तौर से लिखा गया है कि 'सभा में या तो प्रवेश न किया जाए, यदि प्रवेश किया जाये तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाए क्योंकि वहां न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है।' अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में कुछ भी बोलने से पहले इन पंक्तियों का हमेशा ख्याल रखता हूँ। सदन में लिखी हुई इन बातों को सदन का हर सदस्य पढ़ता है और मैं भी इन पंक्तियों को जरूर पढ़ता हूँ। अध्यक्ष महोदय, दीपक मंगला जी ने तीन बार यहां सदन के पटल पर बोला कि दुधोला गांव में विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी खुल गई है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि मैं तो चंडीगढ़ में वैसे ही धक्के खा रहा हूँ? अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में हुड्डा साहब मेरे सैक्टर 55 में एक अस्पताल की बिल्डिंग बनाकर गए थे लेकिन यह अस्पताल आज तक चालू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय मैंने राज्यपाल महोदय को इस यूनिवर्सिटी के संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी है क्योंकि वह इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। यही नहीं जिस मंत्री के अधीन यह यूनिर्वसिटी आती है, उस मंत्री से भी मैं मिल चुका हूँ। अध्यक्ष महोदय, अब

सदन में विज साहब मौजूद नहीं है। हम तो उन्हें धाकड़ मंत्री सोचते थे। मैं आज सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या सदन में दीपक मंगला जी ने जो बोला है क्या वह सच है? क्या हकीकत में हमारे यहां हस्पताल है? अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी चाहे एक खोलो या दो खोलो बस मेरे हस्पताल की बिल्डिंग खाली करवाकर इसे चालू करवा दो। हमारे यहां एक बी.के. नाम से अस्पताल है जोकि हम सबके बहुत काम आता है लेकिन इसमें वेंटीलेटर मशीन की सुविधा नहीं दी गई है। अध्यक्ष महोदय, यह अस्पताल 30 लाख की आबादी को कैटर करता है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरे हलके के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन अब मैं सिर्फ एम्पलॉयमैंट के विषय पर अपनी आखिरी बात रखकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सक्षम रक्षकों के बारे मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमने इतने हजार लोगों को रोजगार दिया। अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, रोजगार देने के साथ–साथ हमें यह भी ख्याल करना चाहिए कि क्या रोजगार प्राप्त लोगों को वें सुविधायें मिल रही हैं जिनके वे हकदार हैं। सिक्योरिटी गार्ड के साथ जितना अत्याचार हमारे हरियाणा प्रदेश में हो रहा है उतना दूसरी जगहों पर कहीं भी नहीं हो रहा है। उनसे वर्दियां खरीदवाई जाती हैं। वे रात को ड्यूटी देते हैं। उनके कांट्रैक्टर उनका चालान काटते हैं कि तुमने टोपी नहीं पहनी या तुमने बैल्ट नहीं पहनी और हर सिक्योरिटी गार्ड 12–12 घंटे की ड्यूटी देता है लेकिन बावजूद इसके इन बेचारों को ओवर टाइम तक नही मिलता है। एक आदमी से दो आदमियों का काम करवाकर एक तरह से एक आदमी का रोजगार खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये सिक्योरिटी गार्ड बेचारे तड़प–तड़पकर अपना जीवन बीता रहे हैं। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बेहतर यह होता कि सरकार मिनिमम वेजिज को ही बढ़ा देती। आज मजदूर को मिनिमम वेजिज भी नहीं मिलता है। हुडड्डा साहब के समय में एक बहुत अच्छी बात हुई थी उस समये मेरे बाबू जी श्रम मंत्री होते थे, तो उस समय फरीदाबाद में एक घोषणा हुई थी कि मजदूर को तनख्वाह चैक से दे दी जाये ताकि बेइमानी का झंझट ही खत्म हो जाये। मजदूरी के मामले में नकदी का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। अगर मजदूर के खाते में चैक जायेगा तो स्वतः पता लग जायेगा कि उसने कितने दिन काम किया था, कितने दिन काम नहीं किया था और जितने दिन काम किया था उसकी तनख्वाह उसको मिल जायेगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः नीरज जी, आपको बोलने के लिए 6 मिनट का समय दिया गया था लेकिन आप 10 मिनट से भी ज्यादा बोल चुके हैं। दूसरे माननीय सदस्यों को भी अपनी बात रखनी है इसलिए आप अब अपनी सीट पर बैठ जाइये। ईश्वर जी, अब आप अपनी बात रखें?

श्री ई□वर सिंह (गुहला): अध्यक्ष महोदय, मैं रिजर्व हलके से चुनकर इस सदन में आया हूँ और इसलिए अपने समाज से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने का मेरा दायित्व बन जाता है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में आरक्षण, वंचित समुदाय के उत्थान करने वाला मसला नहीं रहा है बल्कि यह एक राजनीतिक औजार बन गया है। यह बात कहने की मुझे इसलिए जरूरत पड़ी कि लोक सभा में 84 एस.सी. वर्ग के तथा 47 एस.टी. वर्ग के अर्थात कुल टोटल 131 मैम्बर्ज ऐसे हैं जो रिजर्व सीटों से चुनाव जीतकर आते हैं। हरियाणा प्रदेश में विधान सभा की 90 सीटें हैं यदि 20 परसेंट के हिसाब से आरक्षित सीटों का कोटा देखें तो इस विधान सभा में 18 आरक्षित सीटें होनी चाहिए जबकि हमें केवल 17 सीटें ही दी जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेकर आज तक केवल 17 आरक्षित सीटों का ही प्रावधान क्यों हुआ है, मुझे इसके बारे में बताया जाये?

श्री अध्यक्षः ईश्वर जी, आपको इस बारे में पहले पता करना चाहिए था। हरियाणा प्रदेश को बने 50 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। आपने यह प्रश्न पूछने में कुछ ज्यादा देर तो नहीं कर दी है?

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, अगर देर भी हो गई है तो आप अब इस काम को कर दीजिए। आपकी बहुत कृपा हो जायेगी। आपका नाम इतिहास में रोशन हो जायेगा। आप मेहरबान हो जाओ। अध्यक्ष महोदय, हम अपना हक मांग रहे है। 18 आरक्षित सीटों के स्थान पर हमें विधान सभा में केवल 17 सीटें ही दी जा रही हैं। कितने अफसोस की बात है कि वर्ष 1966 से लेकर आज तक हमारी एक आरक्षित सीट खाली चली आ रही है। 20 परसैंट कोटे के हिसाब से विधान सभा में हमारी 18 आरक्षित सीटें बनती हैं। अतः विधान सभा में 18 आरक्षित सीटों का प्रावधान होना चाहिए। जब संसद में 84 एस.सीज. वर्ग तथा 47 एस.टीज. वर्ग अर्थात कुल मिलाकर 131 आरक्षित सीटों का पूरा कोटा दिया जा रहा है तो फिर विधान सभा में हमारी एक सीट लगातार कम क्यों होती जा रही है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यही बात कहना चाहता हूँ कि संसद के अंदर 131 सदस्य हैं। जिसमें 47 सदस्य एस.टीज. वर्ग से हैं और 84 सदस्य एस.सी. वर्ग से हैं। इस

प्रकार से उनका पूरा कोटा है। लेकिन हमारे यहां एक सीट लगातार कम होती चली आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि जो अनुच्छेद 300 है उसमें प्रावधान है कि रिजर्व सीटें पूरी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 332 यह दर्शाता है कि विधान सभा में भी इसका प्रोविजन होना चाहिए। इस एक्ट के बाद भी जब यह कानून है अर्थात् मूल अधिकार है और 332 अनुच्छेद होने के बाद भी हरियाणा विधान सभा में रिजर्व की 17 सीटें हैं जोकि सही नहीं है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, बौनों, निराश्रित बच्चों, एक या एक से अधिक बेटी वाले अभिभावकों, स्कूल न जा रहे दिव्यांग बच्चों और कश्मीरी विस्थापितों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनकर सदन हैरान हो जायेगा। आज मानव तस्करी बढ़ती जा रही है। मानव तस्करी में सरकार का दायित्व कम और समाज का दायित्व ज्यादा होता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक साल में 29 बेटियां गुमशुदा हुई हैं। इसमें सरकार को सहजता से नहीं बल्कि सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 के क्राइम डाटा इस बात की पुष्टि करता है कि 20 लड़कियां गुमशुदा हुई हैं और उनमें से एक भी ट्रेस नहीं हुई है। साल भर में मानव तस्करी के 34 मामले दर्ज हुए हैं। 34 मामलों में बंधुआ मजदूर हैं उनको नौकर बनाने के लिए तस्करी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की शुरूआत की थी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में लिंगानुपात में तो जरूर सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है और समाज की सोच में भी परिवर्तन हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मानव तस्करी बढ़ती जा रही है। किशोर युवाओं को बंधुआ मजदूर नौकर बनाने के लिए उठाया जा रहा है। यह बहुत गंभीर समस्या इस प्रदेश के लिए बनती जा रही है। मानव अंगों की तस्करी हो रही है और बड़े लैवल पर इसका कारोबार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रिपोर्ट के साथ सदन में यह कहना चाहता हूँ कि इस साल के अंदर 23 नाबालिग लड़कियों और 3 नाबालिग लड़कों की तस्करी हुई है। खासकर के किशोरियों को जबरन वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जाता है और उनकी जबरन शादी करवाई जाती है। यह प्रदेश के लिए एक गंभीर मुद्दा है। पुलिस जांच से पता चला है कि जिन

लड़कियों की तस्करी हुई हैं उनको जबरन देह व्यापार में धकेला गया है। आज छोटे–छोटे बच्चों को भिखारी बनाया जा रहा है। हॉस्टल, ढाबा, दूकानों आदि जगहों पर छोटे–छोटे बच्चों से तस्करी के काम करवाये जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस धंधे में गरीब आदमी ही फंसता है अमीर के बच्चे इसमें शामिल नहीं होते हैं। यह हमारे लिए सामाजिक मुद्दा है। सरकार को इस तरफ गंभीरता से सोचना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये गुमशुदा लड़कियां कहां गई और किस ढंग से उठाई गई थी और कितनी लड़कियों को देह व्यापार में धकेला गया, इस मुद्दे पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा गुहला हल्के में कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि घग्गर के पानी में पंजाब का जैसे पटियाला, राजपुरा या पंचकूला के साथ एरिया का कैमिकल्ज मिक्स होता है, जिसके कारण पानी दुषित हो जाता है।

.....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है, जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बैठक का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री ई□वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, दुषित पानी से हमारे एरिया में काला पीलिया की बीमारी फैलनी शुरू हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूँ कि हमारे यहां कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वॉटर स्कीम लागू की जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में कैंसर के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका कारण पीने के पानी का स्वच्छ न होना है । जो व्यक्ति स्वच्छ पानी नहीं पीयेगा उसकी किडनी, लीवर आदि खराब हो जाएगा, पीलिया बढ़ जाएगा और उसको कैंसर हो जाएगा । हम चाहते हैं कि हमें मारकन्डा नदी नही की डिस्ट्रिब्यूट्री से कैनाल बेस्ड वाटर दिया जाए । हमने इसके हिसाब से म्यूनिसिपल कमेटी से रेजोल्यूशन भी डलवाया है और मैं सिंचाई विभाग से भी यही कहूंगा कि इसको प्रायोरिटी पर लेकर लागू किया जाए । दूसरा, मैं यूनिवर्सिटी की बात करना चाहता हूं । पहले यूनिवर्सिटीज के नाम से रीजनल सैंटर्स खोले जाते थे लेकिन अब उनको बंद कर दिया गया है

। हमने सरकार को एक प्रस्ताव दिया है कि हम 90 एकड़ जमीन रीजनल सैंटर्स खोलने के लिए सरकार को मुफ्त देंगे । अध्यक्ष महोदय, 20 एकड़ जमीन में यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है जबकि हम 90 एकड़ जमीन रीजनल सैंटर खोलने के लिए दे रहे हैं । अतः मेरा निवेदन है मेरे क्षेत्र में रीजनल सैंट्र्स खोले जाएं । हमारा क्षेत्र पंजाब के बॉर्डर के साथ लगता है और वह बैकवर्ड एरिया है । वह ऐजुकेशन की दृष्टि से भी बहुत बैकवर्ड एरिया है । अगर वहां पर रीजनल सैंट्र्स खोले जाएंगे तो इससे यूनिवर्सिटीज और वहां की जनता दोनों को लाभ होगा । सरकार ने हमारे एरिया में एक मैडिकल कॉलेज मंजूर किया हुआ है । ऐसे में मेरा कहना है कि जब वहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है तो फिर मैडिकल कॉलेज तो कम से कम खोल दिया जाए । हमारे पास जमीन अवेलेबल है, हमने उसका प्रस्ताव डी.सी. के पास भेजा हुआ है। 90 एकड़ जमीन बहुत होती है । इतनी जमीन में तो ऐजुकेशन का बहुत बड़ा सैंटर खोला जा सकता है । आजकल सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है उसको प्राप्त करने के लिए केवल एस. सीज./एस.टीज., बैकवर्ड क्लासिज या फिर वे बच्चे जाते हैं जो प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी फीस देने में असमर्थ है । सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए नजदीक के किसी सेलर, मिल आदि से बच्चों को लाकर उनका ऐडमिशन कर दिया जाता है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ईश्वर सिंह जी, अब आप सम अप कीजिए ।

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी तो आपने हाउस का समय 5 मिनट बढ़ाया था ।

श्री अध्यक्ष : ईश्वर सिंह जी, वे बढ़ाए हुए 5 मिनट अब खत्म हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको सम अप करने के लिए कह रहा हूं ।

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब वे बच्चे अप्रैल माह के बाद लोटकर स्कूलों में नहीं आते तो सरकारी स्कूलों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है । मैंने कल शिक्षा से संबंधित एक प्रश्न लगाया था और इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात भी की थी कि 5 किलोमीटर के दायरे में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकते और सरकार ने नॉर्म्स बनाए हैं कि जिन सरकारी स्कूलों में 15 बच्चों से ज्यादा नहीं होंगे उनको मिडिल स्कूल में अपग्रेड नहीं किया जाएगा । ऐसा होने पर जो वे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे । मेरा कहना है कि शहरों के सरकारी स्कूलों के लिए सरकार चाहे 5–6 बच्चों तक का क्राइटेरिया तय कर दे लेकिन

देहात के स्कूलों को अपग्रेड करने का क्राइटेरिया चेंज किया जाए । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे इसको बदलने का आश्वासन भी दिया था । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । जय हिन्द ।

.....

गैर सरकारी दिवस को सरकारी दिवस में परिवर्ति करना

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि दिनांक 27 फरवरी, 2020 वीरवार के गैर–सरकारी कार्य दिवस को सरकारी कार्य दिवस में परिवर्तित कर दिया जाए और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव दिनांक 27 फरवरी, 2020 को रख लिया जाए ताकि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अधिक से अधिक समय मिल सके । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले सवा पांच साल से देख रही हूं कि सरकार एक भी दिन को नॉन ऑफिशियल डे नहीं रखा है जबकि वीरवार के दिन को बी.ए.सी. की मीटिंग में नॉन ऑफिशियल डे निर्धारित किया गया था इसलिए गैर सरकारी दिवस ही 27 फरवरी, 2020 को रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, उस दिन हमारे पास खाली समय है और उस दिन के लिए हमारे पास कोई गैर सरकारी कार्य के लिए नोटिस भी नहीं आया है । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर नोटिस दिया हुआ है । (विघ्न)

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, इसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने समय मांगा था।

Smt. Geeta Bhukkal: Speaker Sir, It was decided in the Business Advisory Committee meeting that Thrusday will be non-official day. That is why I have given a notice on it and that was very-very important.

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यदि हाऊस की सहमति हो तो बैठक का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन की बैठक का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

.....

गैर सरकारी दिवस को सरकारी दिवस में परिवर्ति करना (पुनरारम्भ)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

श्री अध्यक्षः गीता जी, आपको बोलने देने के लिए ही सदन की बैठक का समय बढ़ाया है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, जब आपने प्रस्ताव रखा है तो मुझे अपनी बात कहने दें।

श्री अध्यक्षः गीता जी, आप अपनी बात कहें।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि deaths due to accidents on the roads और आवारा पशुओं की वजह से या rash driving की वजह से एक्सीडैंट्स होते रहते हैं। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं हैं।

श्री अध्यक्षः गीता जी, आप इस विषय को कल जीरो ऑवर में उठा लें।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपनी बात रखने के लिए समय ही नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्षः गीता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कल आपको बोलने के लिए समय दिया जाएगा।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, नॉन ऑफिशियल डे पर बोलने के लिए मैंने ही सिंगल नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्षः गीता जी, यह मेरा आपसे प्रामिस है कि कल आपको सबसे पहले बोलने के लिए मौका दिया जाएगा।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, ठीक है। मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको चाहे आप कॉलिंग अटैंशन में ले लें।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि हाऊस की सहमति हो तो दिनांक 27.2.2020 गुरुवार को गैर सरकारी कार्य दिवस को सरकारी कार्य

दिवस में परिवर्तित कर दिया जाए ताकि सभी सदस्यों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके।

श्री अध्यक्ष : क्या इस बारे में हाउस सहमत है।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, दिनांक 27.2.2020 को गैर सरकारी दिवस को सरकारी दिवस में परिवर्तित किया जाता है। दिनांक 27.2.2020 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में भाग ले सकें।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन बुधवार, दिनांक 26.2.2020 प्रातः 11:00 बजे तक स्थगित किया जाता है।

*2:36 बजे

(तत्पश्चात् सभा बुधवार, दिनांक 26.2.2020 प्रातः 11:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)